धनबाद
बुधवार 17.06.2026
मूल्य- ₹ 2.50
वर्ष-32 अंक-115 पृष्ठ- 12
ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष-2
संवत 2083

झारखण्ड से प्रकाशित सर्वाधिक लोकप्रिय दैनिक

बिहार ऑब्जर्वर

सीएम निगम में वर्षो से जमे अपर नगर आयुक्त प्रकाश और फुड इंस्पेक्टर के मामले में लें संज्ञान : जे.पी.वालिया

भूमाफियाओं और रियल स्टेट घोटालेबाजों के साथ अघोषित पार्टनर बनकर करोड़ों का घोटाला किया है भ्रष्ट अधिकारियों ने

धनबाद (कासं): झारखण्ड मुक्ति मोर्चा (यू) के धनबाद महानगर अध्यक्ष जे.पी.वालिया ने आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ज्ञापन देकर धनबाद नगर निगम में वर्षो से जमे अपर नगर आयुक्त प्रकाश राम और फुड इंस्पेक्टर अनिल कुमार के काले धन और घोटाले की जांच एसीबी की टीम रांची से भेजकर जांच करवाएं तो एक बड़ा घोटाला सामने आयेगा।

उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आग्रह किया है कि नगर निगम के राजस्व हित और जनहित में दोनों का स्थानांतरण दूसरे नगर निगम में करने का आग्रह करते हुए कहा है कि पिछले कई वर्षो से पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल के हटने के बाद अपर नगर आयुक्त प्रकाश राम और फुड इंस्पेक्टर अनिल कुमार अपने पावर का दुरूपयोग कर भूमाफियाओं और बिल्डरों को बड़े पैमाने पर लाभ पहुंचाया है। यही नहीं मैंने इस मामले पर मुख्य सचिव अविनाश कुमार को

मेयर संजीव सिंह के आदेश के बाद भी पीड़ित महिला को न्याय नहीं दिया निगम के अधिकारी ने

शिकायत पत्र भेजा है कि कैसे हीरापुर रजिस्ट्रार बंगला की पीछे होटल माफिया के इशारे पर एक गरीब महिला का घर बिना नोटिस और बिना सूचना के सरकारी खाते की जमीन पर बंदोबस्ती प्राप्त कर घर का निर्माण हुआ था कमला देवी के नाम पर।

कमला देवी के पति शिबू सिंह अपर समाहर्ता के चालक थे और एसी बंगला के क्वार्टर में रहते थे। उनकी मृत्यु के बाद उनकी पुत्री इति सिंह उनके घर में रहती है। उस घर को खाली कराने के लिए पूर्व एसी राय का रिश्तेदार भूमाफिया ने एसी बंगला के दीवार को तोड़कर बड़े पैमाने पर सरकारी भूमि अवैध ढंग से दखल कर होटल और बंगला निर्माण करवाया है।

करोड़ों के होटल सरकारी जमीन पर कैसे बना इसकी जांच उपायुक्त धनबाद से कराने की मांग करते हुए कहा है कि कई भूमाफियाओं के रियल स्टेट और होटल के धंधों में नगर निगम के अपर नगर आयुक्त प्रकाश राम और फुड इंस्पेक्टर अनिल कुमार अघोषित पार्टनर हैं और श्री वालिया ने मुख्यमंत्री से कहा है कि फुड इंस्पेक्टर का काम मिठाई और खाद्यान्न जांच का है नहीं कि राज्य सरकार और रैयतों के जमीन पर बने निर्माण को तोड़ने का। उन्होंने कहा कि गरीबों को नियम और कानून की जानकारी नहीं रहती है। इसी कारण ये भ्रष्ट अधिकारी नंगा नाच कर हेमंत सरकार की छवि धूमिल कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि पीड़ित महिला ने मेयर संजीव सिंह से मिलकर न्याय की मांग की थी। मेयर संजीव सिंह ने नगर आयुक्त को इस मामले पर गलत तरीके से निर्माण तोड़ने वाले कर्मचारियों के विरूद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया था लेकिन मेयर के आदेश के बाद भी महिला को न्याय नहीं मिला है।

मोरहाबादी मैदान में सीएम हेमंत सोरेन ने तीन दिवसीय कृषि व्यापार मेला का किया उद्घाटन

कृषि का दायरा इतना बड़ा कि किसी एक क्षेत्र में भी आगे बढ़ें तो बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं : हेमंत सोरेन

रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आज खेती-बाड़ी सिर्फ पारंपरिक पेशा नहीं रह गया है, बल्कि यह रोजगार और उद्यम का बड़ा माध्यम बनकर उभरा है। बड़ी संख्या में लोग कॉरपोरेट क्षेत्र की नौकरियां छोड़कर खेती और उससे जुड़े व्यवसायों की ओर लौट रहे हैं। ऐसे में नई-नई तकनीकों का उपयोग और आधुनिक खेती को अपनाना समय की जरूरत है।

मंगलवार को मोरहाबादी मैदान में तीन दिवसीय झारखंड कृषि व्यापार मेला-२०२६ के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि का दायरा इतना बड़ा है कि यदि कोई व्यक्ति किसी एक क्षेत्र को भी गंभीरता से अपनाता है तो वह बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकता है। फल-सब्जी उत्पादन, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन और कृषि आधारित उद्योगों में अपार संभावनाएं हैं।

मुख्यमंत्री ने रासायनिक खाद के बजाय जैविक खेती और जैविक खाद के उपयोग पर जोर देते हुए कहा कि जिन राज्यों में रासायनिक खाद का अत्यधिक उपयोग हो रहा है, वहां की उपज को लेकर लोगों में चिंता बढ़ी है। रासायनिक खाद का अत्यधिक इस्तेमाल स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदेह हो सकता है। उन्होंने किसानों और सरकार को मिलकर काम करने की जरूरत बताते हुए कहा कि खेती को लाभकारी बनाने और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए दोनों की साझी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों को आधुनिक तकनीक और नई पद्धतियों से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। कृषि के क्षेत्र में नई-नई तकनीकों का विकास हो रहा है और किसानों को उसका ▶▶ 8

जी-7 शिखर सम्मेलन में मिले नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप, 16 महीने बाद आमने-सामने आए दोनों नेता

नई दिल्ली (ईएमएस): फ्रांस में आयोजित जी-७ शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात ने वैश्विक स्तर पर ध्यान आकर्षित किया। दोनों नेताओं ने सम्मेलन स्थल पर गर्मजोशी से हाथ मिलाया और संक्षिप्त बातचीत भी की। यह पिछले १६ महीनों में दोनों नेताओं की पहली आमने-सामने मुलाकात मानी जा रही है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी-७ शिखर सम्मेलन में विशेष आमंत्रित नेता के रूप में शामिल हुए हैं। सम्मेलन का आयोजन फ्रांस के एवियन-ले-बैंस में किया जा रहा है, जहां दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के नेता वैश्विक सुरक्षा, व्यापार, ऊर्जा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और भू-राजनीतिक चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता भी प्रस्तावित है। इस बैठक में भारत-अमेरिका व्यापार समझौता, ▶▶ 8

हेमन्त सोरेन
मुख्यमंत्री, झारखण्ड

संदेश

विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा निवारण दिवस

प्रति वर्ष मरुस्थलीकरण और सूखा निवारण दिवस पर हम भूमि और जल के महत्व पर चिंतन करते हैं। मरुस्थलीकरण और सूखा निवारण दिवस 2026 का विषय "चारागाह पहचानें। सम्मान करें। पुनर्स्थापित करें" है। यह हमें दर्शाता है कि पृथ्वी की आधी से अधिक सतह को आच्छादित करने वाले चारागाह खाद्य सुरक्षा, जैव विविधता और जलवायु सहनशीलता बनाए रखने में कितने महत्वपूर्ण हैं। कई पीढ़ियों से पशुपालक और आदिवासी समुदाय अपनी संरक्षकता के माध्यम से इन भू-भागों की सुरक्षा करते आए हैं।

झारखण्ड राज्य जो समृद्ध वनों, उपजाऊ मिट्टी और विविध पारिस्थितिक तंत्रों से संपन्न है, आज वनों की कटाई, भूक्षरण और जल संकट जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। ये खतरे हमारे कृषि, जल संसाधनों और असंख्य परिवारों की आजीविका को प्रभावित कर रहे हैं। वैश्विक समुदाय का हिस्सा होने के नाते हमें अपनी भूमि के मूल्य को पहचानना होगा, पारंपरिक ज्ञान का सम्मान करना होगा और बंजर क्षेत्रों को पुनर्स्थापित करना होगा ताकि एक सतत् भविष्य सुनिश्चित किया जा सके।

यह दिवस हमें याद दिलाता है कि हमारी भूमि का स्वास्थ्य हमारे लोगों की समृद्धि से जुड़ा हुआ है। जल संरक्षण, वनों की रक्षा, पर्यावरण से अनुकूल खेती अपनाने और भूमि क्षरण को रोकने के माध्यम से हम झारखण्ड की प्राकृतिक संपदा को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। हमारी भूमि ही हमारा जीवन है और इसे पहचान कर, सम्मान देकर और पुनर्स्थापित करके हम न केवल अपने पर्यावरण की रक्षा करते हैं, बल्कि अपने बच्चों के भविष्य को भी सुरक्षित बनाते हैं।

जोहार !

PR 382549 (Forest, Environment and Climate Changes) 26-27

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड

सिरप अब डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही मिलेगा

नई दिल्ली (ईएमएस): कफ सिरप अब बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं खरीदे जा सकेंगे। केंद्र सरकार ने ड्रग्स नियमों में बदलाव किया है। इसके तहत सिरप को अब उस लिस्ट से हटा दिया गया है, जिसमें दवाएं सीधे दुकान से खरीदी जा सकती हैं। सरकार का कहना है कि इससे सिरप आधारित दवाओं पर निगरानी और गुणवत्ता नियंत्रण मजबूत होगा। साथ ही सिरप निर्माता और विक्रेता को लाइसेंसिंग और क्वालिटी कंट्रोल से जुड़े सख्त नियमों का पालन करना ही होगा। मध्य प्रदेश में अक्टूबर २०२५ में दूषित सिरप से २६ बच्चों की मौत हो गई थी।

नई व्यवस्था के तहत ड्रग्स रूल्स, १९४५ की अनुसूची में बदलाव किया गया है। ▶▶ 8

आधार का इस्तेमाल केवल पहचान तक सीमित रहेः सुप्रीम कोर्ट का केंद्र और राज्यों को नोटिस

आधार का इस्तेमाल बढ़े पैमाने पर कथित घुसपैठिए और अवैध प्रवासी करते

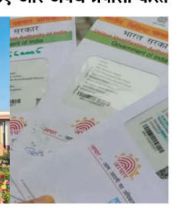

नई दिल्ली (ईएमएस): सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महत्वपूर्ण जनहित याचिका पर सुनवाई कर केंद्र सरकार, सभी राज्य सरकारों, केंद्रशासित प्रदेशों, भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) को नोटिस भेजा है। याचिका में यह सुनिश्चित करने की मांग की गई है कि आधार का उपयोग केवल पहचान के प्रमाण के रूप में करे, न कि नागरिकता, निवास, पते या जन्मतिथि के सबूत के तौर पर इसका उपयोग किया जाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर याचिका पर सहमति जताकर संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है।

सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में बताया गया है कि आधार अधिनियम, २०१६ की धारा ९ स्पष्ट रूप से कहती है कि आधार नागरिकता या निवास का प्रमाण नहीं है। यूआईडीएआई के अपने दिशानिर्देश भी स्पष्ट करते हैं कि आधार केवल पहचान का सबूत है, न कि नागरिकता, ▶▶ 8

झारखंड में दुर्लभ खनिजों की खोज, खनन और तकनीकी सहयोग करेंगी अमेरिकी कंपनियां

रांची (एजेंसी): झारखंड में परंपरागत खनिजों के अलावा दुर्लभ एवं महत्वपूर्ण खनिजों (क्रिटिकल मिनरल्स) की खोज, खनन, प्रसंस्करण और तकनीकी सहयोग के क्षेत्र में अमेरिकी कंपनियों ने रुचि दिखाई है। इस संबंध में मंगलवार को मुख्य सचिव अविनाश कुमार और अमेरिकी काउंसलेट जनरल कैली जाइल डियाज के नेतृत्व में आए प्रतिनिधिमंडल के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान झारखंड के खनिज क्षेत्र में उपलब्ध व्यापक संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई।

बैठक में प्रतिनिधिमंडल को बताया गया कि झारखंड में कोयला, लौह अयस्क, तांबा, बॉक्साइट, सोना और चूना पत्थर (लाइम स्टोन) जैसे परंपरागत खनिजों के विशाल भंडार उपलब्ध हैं तथा इनके खनन और प्रसंस्करण के क्षेत्र में राज्य ने उल्लेखनीय प्रगति की है।

इसके अलावा राज्य ▶▶ 8

लैंडमाइन फटने से चार सैनिक घायल

राजौरी (ईएमएस): जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास हुए एक धमाके में सेना के ४ जवान घायल हो गए, जिनमें एक जूनियर कमीशंड ऑफिसर भी शामिल है। यह धमाका नौशेरा सेक्टर के कलाल इलाके में सेना के जवानों की पेट्रोलिंग के दौरान गलती से लैंडमाइन एक्टिवेट होने की वजह से हुआ। धमाके में एक जेसीओ और तीन सैनिक घायल हुए और उन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। अधिकारियों के मुताबिक सीमा पार से होने वाली घुसपैठ रोकने के लिए लैंडमाइन बिछाई जाती हैं, जो कभी-कभी बारिश में बह जाती हैं और ऐसे हादसों का कारण बनती हैं।

संपादकीय | अपना स्वार्थ देखने से कैसे जुड़ेंगी नदियां!

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों से कहा है कि नदियों को जोड़ने के रास्ते में बाधा डालनेवाले जल विवादों का समाधान आपसी सहमति और सहयोग के जरिये निकाला जाए. हालिया 51वीं 'प्रगति' बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने यह बात कही. उन्होंने एक्स पर पोस्ट में कहा कि 'प्रगति' सत्र के दौरान 30,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की समीक्षा की गई. लेकिन प्रधानमंत्री ने अपना संबोधन नदियों को जोड़ने से शुरू किया और उसी से संबंधित परियोजना पर फोकस किया.

इस सिलसिले में मोदी ने राज्यों से सहयोग, समय पर मंजूरी व प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी के माध्यम से अंतरराज्यीय जल विवादों के हल की चर्चा के क्रम में केन-बेतवा नदियों को जोड़नेवाली परियोजना का उदाहरण दिया. प्रधानमंत्री ने केन-बेतवा परियोजना को आदर्श और मॉडल के रूप में देखने को भी कहा.

केन और बेतवा नदियों को जोड़नेवाली परियोजना पर काम के साथ-साथ विवाद भी चल रहा है. राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठजोड़ (एनडीए) सरकार के नदियों को जोड़नेवाले महत्वाकांक्षी एजेंडे में केन-बेतवा पहली परियोजना है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिसंबर, 2021 में केन-बेतवा परियोजना को मंजूरी दी और बताया गया कि इस पर 44,605 करोड़ रु. की लागत आएगी. वर्ष 2030 में इसका काम पूरा होना है. 25 दिसंबर, 2024 को प्रधानमंत्री ने केन-बेतवा नदी लिंक (जोड़ो) की आधारशिला रखी.

नदियों को जोड़ने की योजना कोई नई नहीं है. प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ही इसके लिए कमेटी बनाई, जो के. एल. राव कमेटी के

नाम से जानी जाती है. इस कमेटी द्वारा तय देश भर की नदियों को जोड़ने की रूपरेखा 1970 के दशक से चर्चा में है. 1980 के दशक में इस योजना को तेजी से अमल में लाने के लिए एक एन.पी.पी. (नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान) तैयार हुआ. उसके तहत 1982 में बनी राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी को केंद्र ने नदियों को जोड़ने का काम सौंपा और इसके लिए 30 लिंक परियोजनाओं की पहचान की गई.

इस योजना के अंतर्गत केन-बेतवा लिंक एकमात्र परियोजना है, जिसका कार्यान्वयन शुरू हुआ. इस परियोजना को नाम दिया गया राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी -2026.

दो साल में केन-बेतवा लिंक के अमल में आने से पहले रास्ते में आनेवाली बुनियादी दिक्कतों की गहराई में गए बगैर सतही आकलन के कारण काम ढीला चल रहा है. इसका कारण है, उस जगह और आसपास के जनजीवन की भावनाओं की उपेक्षा. नदियों को जोड़ने के क्रम में वहां के बाशिंदों से जुड़ाव को नजरअंदाज करने का परिणाम है आंदोलन. केन नदी से सटे दौधान गांव में डैम बनाने के लिए जमीन अधिग्रहण से 22 गांवों के 7,000 परिवार विस्थापित होंगे. उनमें से 10 गांव लगभग पूरी तरह जलमग्न हो जाएंगे.

नदियों को जोड़ने में अभी तक आशानुकूल सफलता नहीं मिलने का कारण राज्य सरकारों का आपस में दिलों का नहीं जुड़ना है. इसकी वजह क्षेत्रीय और राजनीतिक पूर्वाग्रह दिल में संजोकर राज्यों का वार्ता के लिए बैठना है. ऐसा नहीं है कि नदी लिंक में पानी के लेन-देन, अदला-बदली में अलग-अलग दलों की सरकारें सिर्फ अपने स्वार्थ को आगे रखकर बात करती हैं. एक दल की सरकारों पर भी अपना क्षेत्रीय पक्ष हावी रहता है. जब दिल नहीं जुड़ेंगे तो नदियां कैसे जुड़ेंगी? दिल तोड़नेवाली बातें नदियों को तोड़ रही हैं. सतलुज-यमुना लिंक, कावेरी जल विवाद, नर्मदा जल विवाद अब नदी-लिंक योजना के इतिहास का बहुविवादित अध्याय बन चुका है. राज्यों में सरकारें बदलीं, केंद्र में सरकारें बदलीं. सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई करते, निर्देश देते-देते थक चुका. न नदियां जुड़ीं, न लोग जुड़े.

ताइवान ने आखिर चीन की ओर रॉकेट क्यों छोड़े?

दुनिया के कई इलाके इस वक्त जंग की चपेट में हैं. ऐसे में यदि कुछ और इलाकों में जंग फैल जाए तो निश्चय ही यह दुनिया के लिए किसी दु:स्वप्न से कम नहीं होगा. ईरान ने तो धमकी भी दे दी है कि जंग अब केवल उसके इलाके में या फिर अरब देशों तक ही सीमित नहीं रहेगी! ईरान की चेतावनी गंभीर चिंता का विषय तो है ही क्योंकि हम भी सीधे तौर पर उससे प्रभावित हो रहे हैं. इस बीच एक नई खबर ने और चिंता बढ़ा दी है. ताइवान ने चीन के संभावित समुद्री हमले का मुकाबला करने के बहाने हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए चीन की दिशा में लाइव-फायर सैन्य अभ्यास किया है. यानी चीन की ओर निशाना साध कर समुद्र में रॉकेट दागे हैं मगर यह ध्यान रखा है कि रॉकेट चीन की सीमा में जाकर नहीं गिरे. ताइवान से चीन की दूरी महज 100 किलोमीटर है. रॉकेट शूट एंड स्कूट यानी दागो और भागो की रणनीति के तहत दागा गया है. इसका अर्थ होता है कि रॉकेट लॉन्चर निशाना साधने के बाद तत्काल अपनी जगह बदल लेता है ताकि दुश्मन को उसके स्थान का अंदाजा नहीं मिल सके. आप सोचेंगे कि चीन तो पूरे साल कई बार ताइवान की हवाई सीमा का उल्लंघन करता रहता है तो फिर ताइवान ने यदि जंग की आशंका में अभ्यास किया है तो इसमें गलत क्या है? सामान्य तौर पर इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता है लेकिन मामला यह है कि ताइवान की किसी भी हरकत को चीन बर्दाश्त करने के मूड में नहीं दिखता है. वह ताइवान को अपने भीतर मिला लेना चाहता है. मगर इस अभ्यास में महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस सिस्टम से ताइवान ने चीन की ओर रॉकेट दागने का अभ्यास किया है, वह सारा सिस्टम अमेरिका ने ताइवान को उपलब्ध कराया है. यह पहले से ही स्पष्ट है कि चीन ताइवान को अपने में मिला ले, यह अमेरिका कभी नहीं होने देगा. मान लीजिए कि चीन यदि ताइवान पर कब्जा कर लेता है तो इसका मतलब होगा कि पश्चिमी प्रशांत महासागर में उसके दबदबे को कोई चुनौती नहीं दे पाएगा. इतना ही नहीं गुआम और हवाई द्वीपों पर मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने को भी खतरा उत्पन्न हो सकता है. चीन भी इस बात को समझता है ताइवान पर हमले का मतलब है दुनिया को आर्थिक तंगी की ओर ले जाना क्योंकि अमेरिका चुप नही बैठेगा और चीन की खुद की आर्थिक स्थिति खराब होगी. अब सवाल पैदा हो रहा है कि क्या ताइवान ने अभी जो रॉकेट दागे हैं, वह कहीं अमेरिका के इशारे पर तो नही किया है? चीन ने ईरान की मदद करके, अमेरिका को परेशान किया है तो कहीं अमेरिका भी चीन को परेशान करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है? यदि यह बात सही है तो फिर दुनिया के सामने आने वाला वक्त अंधेरे से घिरा होगा. अमेरिका और चीन दोनों ही आर्थिक और सामरिक रूप से सक्षम देश हैं लेकिन दुनिया में आग लगे रहने का मतलब है कि छोटी और मझोली अर्थव्यवस्थाओं का पूरी तरह तबाह हो जाना. दुर्भाग्य की बात है कि यूनाइटेड नेशन जैसी संस्थाएं पूरी तरह से पंगु हो चुकी हैं. वो कहने के लिए केवल वजूद में हैं. कोई नहीं सुन रहा है. अब जरूरत इस बात की है कि दुनियाभर के देश एक स्वर में जंग के खिलाफ आवाज उठाएं.

आज का कार्टून

जब अदालतों में कानून की भाषा सरल होगी...

> दुनिया के कई देशों में कानून की भाषा को सरल और नागरिक-अनुकूल बनाने के लिए एआई का प्रयोग तेजी से बढ़ रहा है। अमेरिका में न्यायालयों और विधि-फर्मों में एआई आधारित उपकरण का इस्तेमाल न सिर्फ कानूनी दस्तावेजों का विश्लेषण करने के लिए, बल्कि उन्हें साधारण भाषा में रूपांतरित करने के लिए भी किया जा रहा है। ब्रिटेन में सरकार ने इस अभियान को एआई-सहयोग से और मजबूत किया है, ताकि नागरिकों को अदालतों और प्रशासनिक आदेशों की भाषा आसान रूप में मिल सके। कनाडा में भी न्याय-अभिगम कार्यक्रम के तहत एआई व्यवस्था अदालतों से जुड़े दस्तावेजों को आम नागरिक की भाषा में समझा कर उपलब्ध कराती है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में स्थानीय न्यायालयों ने उन क्षेत्रों के लोगों के लिए एआई-आधारित अनुवाद और सरलीकरण प्रणाली शुरू की है, जहां अंग्रेजी मातृभाषा नहीं है।

मनीष जैसल

कानून की भाषा और आम नागरिक के बीच की दूरी कम करने में कृत्रिम मेधा नई संभावनाएं खोल रही है। समाज में कानून को लेकर जो धारणा वर्षों से बनी हुई है, वह किसी को भी असहज कर देने वाली है। अदालतों की लंबी तारीखों और मोटी फाइलों से आम आदमी विचलित होता है। लोग अक्सर कहते भी हैं कि कानून के फेर में न पड़ो, वरना जिंदगी कोर्ट-कचहरी में निकल जाएगी। जब कोई नोटिस या कानूनी कागज घर पहुंचता है, तो सबके चेहरे पर तनाव की रेखाएं खिंच जाती हैं।

देश में न्याय और नागरिक के बीच सबसे ऊंची दीवार यदि कोई है, तो वह है कानून की जटिल भाषा। अदालतों में दायर याचिकाओं से लेकर बैंक-कर्ज के दस्तावेजों, करायेदार से संबंधित समझौतों और बीमा-पॉलिसी की शर्तों तक हर जगह ऐसी भाषा दिखाई देती है, जिसे पढ़ने मात्र से आम आदमी भ्रम में पड़ जाता है।

न्याय व्यवस्था तकनीक और डिजिटलीकरण के साथ बदल रही है, लेकिन भाषा की जटिलता आज तक कम नहीं हुई है। कानून जनता के लिए बना है, लेकिन उसकी भाषा जनता से कोसों दूर है। ऐसे में कृत्रिम मेधा यानी एआई एक नए युग की शुरुआत कर रही है, जहां कानूनी शब्दावली और आम नागरिक के बीच की दूरी कम हो सकती है।

कानूनी भाषा के कठिन होने का एक बड़ा कारण उसकी सटीकता है। विधि-निर्माता इस बात की कोशिश करते हैं कि शब्दों का ऐसा इस्तेमाल हो, जिससे किसी अर्थ-भ्रम की संभावना न बचे। इसलिए लंबे वाक्य, जटिल उपवाक्य, विशिष्ट परिभाषाएं और बहुस्तरीय शर्तें दस्तावेजों का हिस्सा बनती हैं। मगर यही सटीकता आम आदमी को कानून की समझ से दूर कर देती है। वह समझना तो चाहता है, लेकिन शब्दों की दीवार उसे पीछे धकेल देती है।

कई नागरिक कभी-कभी अपने हस्ताक्षर किए हुए दस्तावेज भी पूरी तरह नहीं पढ़ते, क्योंकि वे यह मान लेते हैं कि वे इसे समझ ही नहीं पाएंगे। मौजूदा दौर में एआई अब वकीलों और उनके मुवक्किल के बीच एक सेतु बन रही है। आज ऐसी तकनीक विकसित हो रही है, जो जटिल कानूनी दस्तावेजों को सरल भाषा में बदल सकती है। यह अनुवाद मात्र शब्दों का नहीं, अभिप्राय का होता है।

इस तरह के परिवर्तन से न सिर्फ जानकारी साफ होती है, बल्कि भय-भाव कम होता है, जो वर्षों से कानून के साथ जुड़ा रहा है। ऐसी ही स्थिति किरायेदारी-समझौते, बीमा-दावे, बैंक-कर्ज और सरकारी नोटिस में भी दिखाई देती है। जब किसी समझौते में लिखा होता है कि 'किराएदार को संपत्ति को पूर्ववत स्थिति में लौटाना अनिवार्य होगा', तो बहुत-से लोग इसका वास्तविक अर्थ नहीं समझते।

यही वाक्य जब सीधे शब्दों में बदल कर आता है कि 'जगह जैसे मिली थी वैसे ही वापस करनी है', तो उसकी स्पष्टता ही उसका अधिकार बनती है। इस अंतर की वजह से तकनीक की आवश्यकता महसूस हुई, क्योंकि जानकारी तभी शक्ति बनती है, जब उसे समझा जा सके। कृत्रिम मेधा के माध्यम से कानूनी दस्तावेजों की व्याख्या, सार, सरल-भाषा और प्रश्न-उत्तर आधारित स्पष्टीकरण संभव होने लगे हैं। कई एआई आधारित मंच यह सुविधा दे रहे हैं कि नागरिक किसी दस्तावेज का अर्थ पूछे और वह आसान भाषा में मिल जाए।

नागरिक यदि पूछे 'क्या इस क्लॉज में मेरे लिए कोई जोखिम है?' तो एआई उत्तर दे सकती है- यदि आप नियम तोड़ते हैं, तो कंपनी आप पर जुर्माना लगा सकती है। यह परिवर्तन न केवल सुविधा है, बल्कि न्याय को जनता तक ले जाने का माध्यम है। डिजिटल युग ने प्रक्रियाओं को सरल किया है, भाषा को नहीं। अब ई-फाइलिंग से बहस तक ऑनलाइन हो रही है। दस्तावेज डिजिटल स्वरूप में उपलब्ध हैं, लेकिन भाषा वही पहेली बनी हुई है। ऐसी स्थिति में एआई की भूमिका तकनीकी प्रगति के साथ न्यायिक लोकतंत्र की आवश्यकता भी है।

दुनिया के कई देशों में कानून की भाषा को सरल और नागरिक-अनुकूल बनाने के लिए एआई का प्रयोग तेजी से बढ़ रहा है। अमेरिका में न्यायालयों और विधि-फर्मों में एआई आधारित उपकरण का इस्तेमाल न सिर्फ कानूनी दस्तावेजों का विश्लेषण करने के लिए, बल्कि उन्हें साधारण भाषा में रूपांतरित करने के लिए भी किया जा रहा है।

ब्रिटेन में सरकार ने इस अभियान को एआई-सहयोग से और मजबूत किया है, ताकि नागरिकों को अदालतों और प्रशासनिक आदेशों की भाषा आसान रूप में मिल सके। कनाडा में भी न्याय-अभिगम कार्यक्रम के तहत एआई व्यवस्था अदालतों से जुड़े दस्तावेजों को आम नागरिक की भाषा में समझा कर उपलब्ध कराती है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में स्थानीय न्यायालयों ने उन क्षेत्रों के लोगों के लिए एआई-आधारित अनुवाद और सरलीकरण प्रणाली शुरू की है, जहां अंग्रेजी मातृभाषा नहीं है।

इन देशों के अनुभव बताते हैं कि भाषा-सरलीकरण के बाद न्यायिक प्रक्रियाओं में आम जनता की भागीदारी बढ़ी है और विवादों की संख्या में कमी आई है। यूरोप के कई देशों में भी न्याय-व्यवस्था में इसे शामिल किया जा रहा है और विशेष रूप से फ्रांस, जर्मनी और नीदरलैंड जैसे देशों में कानून की जटिल शब्दावली को नागरिक-अनुकूल रूप में बदलने की दिशा में संगठित पहल दिखाई देती है।

फ्रांस में न्याय मंत्रालय एआई-सहायता से अदालतों के आदेशों का सहज भाषा में सार उपलब्ध करा रहा है। जर्मनी में 'लीगल टेक' जैसे नवउद्यम किरायेदारी विवाद, बीमा दावे और कर संबंधी दस्तावेजों को आम आदमी की भाषा में समझाने में तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। एस्टोनिया ने तो कृत्रिम मेधा-आधारित 'डिजिटल जज' शुरू किया है, जो छोटे मामलों में तकनीक-सहायता से निर्णय प्रक्रिया को सरल करता है।

भारत में भी कानून की भाषा को सरल बनाने और तकनीकी माध्यम से आम नागरिक तक पहुंचाने की दिशा में उल्लेखनीय काम हो रहा है। एक अनुवाद मंच ने बाईस भारतीय भाषाओं में चालीस हजार से अधिक कानूनी दस्तावेजों का अनुवाद किया है, जिससे अंग्रेजी-भाषी कानूनी दस्तावेजों का लाभ हिंदी-भाषी और अन्य भाषाई समूहों तक पहुंचने लगा है। इसके साथ ही, कई 'लीगल-टेक' कृत्रिम मेधा का उपयोग कर कानूनी शोध, दस्तावेज विश्लेषण और समझ-सार तैयार करने में लगे हैं। इसके नतीजे सामने आ रहे हैं।

आज आवश्यकता इस बात की है कि इस दिशा में संस्थाएं, न्यायालय, विश्वविद्यालय और प्रशासन मिलकर काम करें। जैसे हम शिक्षा में डिजिटल संसाधन उपलब्ध कराते हैं, वैसे ही कानून की भाषा को सरल बनाने का भी सार्वजनिक तंत्र विकसित होना चाहिए। कानून तभी लोगों का साथी बन सकता है, जब उसकी भाषा लोगों की भाषा हो। आज भी अनेक नागरिक अपने अधिकारों से इसलिए दूर रह जाते हैं, क्योंकि कानूनी शब्दावली उन्हें जटिल लगती है। जब तकनीक, विशेष रूप से कृत्रिम मेधा, इस भाषा को सरल, स्पष्ट और समझने योग्य बनाने का कार्य करेगी, तब न्याय केवल अदालतों तक सीमित अवधारणा नहीं रहेगा, बल्कि आम नागरिकों के जीवन का हिस्सा बन जाएगा।

दूसरों में उलझने के बजाय खुद को सुलझाएं...

> जीवन की इस भागदौड़ भरी दुनिया में हम अक्सर खुद को भूल जाते हैं। चारों ओर फैली अफवाहें, तुलनाओं की होड़, दूसरों की नजरों का डर- ये सब हमें उलझाते रहते हैं। मगर क्या हमने सोचा है कि असली शांति कहां मिलेगी? बाहरी दुनिया की जटिलताओं में नहीं, बल्कि अपने भीतर की सरलता में। 'दूसरों में मत उलझो, अपने आप में सुलझो' - यह वाक्य मात्र शब्द नहीं, बल्कि जीवन का मूल मंत्र है।

अविनाश जोशी

यह हमें सिखाता है कि सच्ची मुक्ति तभी संभव है, जब हम अपनी आंतरिक यात्रा पर ध्यान केंद्रित करें। आधुनिक जीवन की व्यस्तता में हम सोशल मीडिया की चकाचौंध में खो जाते हैं, जहां हर कोई अपनी जिंदगी को संपूर्ण दिखाने की होड़ में लगा है। नतीजा? चिंता, ईर्ष्या और अशांति। अगर हम ठहरें, आत्ममंथन करें, तो पाएंगे कि समस्याओं का मूल कारण बाहरी नहीं, आंतरिक है। दरअसल, बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि पड़ोसी का बच्चा कितना होशियार है, रिश्तेदार के बच्चे कितना कमाते हैं। यह तुलना का जाल हमें बांध लेता है। गांवों में अभी भी लोग एक-दूसरे की संपत्ति, विवाह या संतान की सफलता पर चर्चा करते हैं। क्या यह उलझन हमें आगे ले जाती है? नहीं। यह हमें पीछे धकेलती है। आधुनिक मनोविज्ञान कहता है - सामाजिक तुलना के सिद्धांत के अनुसार, ऊपर-नीचे की तुलना अवसाद का कारण बनती है। सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग विदेश जाकर छुट्टियां मनाने की तस्वीरें प्रदर्शित करते हैं, महंगी कारें दिखाते हैं। हम सोचते हैं कि हमारी जिंदगी ऐसी क्यों नहीं है! अपने आप में सुलझना एक आंतरिक प्रक्रिया है, जो आत्म-चिंतन से शुरू होती है। रोजाना सुबह दस मिनट शांत बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान देना चाहिए। योग का प्राणायाम या लोक संगीत की धुनें सुनना हमें भीतर ले जाएंगी। स्वामी विवेकानंद कहते थे, 'तुम्हें बाहर नहीं, भीतर झांकना है।' अपने आप में सुलझना मतलब अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना। मान लें कि हमें अपनी नौकरी पसंद नहीं, लेकिन डर लगता है छोड़ने का कि समाज कहेगा नाकाम हो गया। मगर हम अपने जुनून को पहचानें, जैसे लेखन, चित्रकला या कविता, तो रास्ता खुद बन जाएगा। राजस्थान के लोक कलाकारों से सीखने की जरूरत है, जो रेगिस्तान की कठोरता में भी अपनी रंगीन कला से जीवन को सजाते हैं। वे दूसरों की नकल नहीं करते, अपनी आत्मा की आवाज सुनते हैं।

इस प्रक्रिया में डायरी लेखन बड़ा सहायक है। हर शाम पांच मिनट लिखने की जरूरत है कि आज क्या अच्छा हुआ, क्या गलत, कल क्या सुधारना है। यह अपनी भावनाओं से रूबरू कराएगा। मनोविज्ञान में इसे 'जर्नलिंग' कहते हैं, जो तनाव को 20 प्रतिशत कम कर देती है। दूसरों में उलझने का एक बड़ा कारण है अपेक्षाएं। हम चाहते हैं कि माता-पिता हमारी हर बात मानें, मित्र हमेशा साथ दें और हमारे वरिष्ठ अधिकारी हमारी सराहना करें। मगर जब ऐसा न हो, तो उलझन शुरू। सुलझने का तरीका?

अपेक्षाओं को कम करना और जो जैसा है, वैसा स्वीकार करना चाहिए। आज के दौर में कई युवा उद्यमी खुद को प्राथमिकता देने के साथ-साथ दुनिया की परवाह न करने के सिद्धांत पर चलते हैं। वे निवेशकों की बात सुनते हैं, लेकिन अपनी दृष्टि पर अडिग रहते हैं। एक अध्ययन के मुताबिक 70 प्रतिशत सफल लोग वे हैं, जो आंतरिक प्रेरणा से चलते हैं, न कि बाहरी प्रशंसा से। परिवार और समाज में इस तरह की स्पष्टता लाने के लिए शुरुआत खुद से करना चाहिए। बच्चों को सिखाना होगा कि वे अंकपत्र के नंबरों पर नहीं, बल्कि अपनी क्षमता पर ध्यान दें। राजस्थान के स्कूलों में अब योग और ध्यान को शामिल किया जा रहा है, जो इसी दिशा में कदम है। पति-पत्नी के रिश्ते में भी एक-दूसरे को बदलने की कोशिश छोड़ें, खुद को बेहतर बनाएं। तब रिश्ते मजबूत होंगे। एक बार एक महिला ने बताया, वह घर के सदस्यों की हर बात पर उलझती थीं, लेकिन जब उन्होंने अपनी दिनचर्या में ध्यान जोड़ा, तो शांति मिली।

आर्थिक दृष्टि से देखें तो यह सिद्धांत और भी प्रासंगिक है। शेयर बाजार में लोग दूसरों के सुझावों पर निवेश करते हैं, नुकसान होता है। लेकिन अगर हम अपनी जोखिम क्षमता समझें, लंबी अवधि की योजना बनाएं, तो सुलझन मिलेगी। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में सीमेंट और रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों में भी यही लागू होता है। कंपनियां जो बाहरी प्रतिस्पर्धा में उलझती हैं, पिछड़ जाती हैं। जो अपनी केंद्रीय शक्ति पर काम करती हैं, आगे बढ़ती हैं।

आध्यात्मिक स्तर पर उस सुलझन को ईश्वर से जोड़कर देखा जाता है। हिंदू दर्शन में आत्मा को परमात्मा का अंश कहा गया है। बाहर भटकने से क्या फायदा? भीतर जाकर खोजें। ध्यान, जप, भजन- ये सब माध्यम हैं। सूफी संत बाबा बुल्ले शाह ने कहा, 'बुल्लेया की जाण मैं नूं, रांझा हो गया।' यानी जब मैं रांझा बन गया, तभी हीर मिली। यानी खुद को खोकर ही पा सकते हैं। राजस्थानी कवि सम्मेलनों में ऐसी ही रचनाएं सुनने को मिलती हैं, जो आत्म-साक्षात्कार पर जोर देती हैं।

बाधाएं भी आएंगी। मन भटकेगा, पुरानी आदतें लौटेंगी। लेकिन धैर्य रखना चाहिए। छोटे-छोटे कदम उठाने की जरूरत है, जैसे फोन की स्क्रीन अवधि कम करना और प्रकृति में घूमना। अध्ययनों से सिद्ध है कि नियमित अभ्यास से खुशी का स्तर 40 प्रतिशत बढ़ जाता है। यह यात्रा निरंतर है। दूसरों की जिंदगी के बजाय अपनी को संवारना चाहिए। कल जब आईना देखा जाए, तो मुस्कुराता चेहरा नजर आए। जीवन छोटा है, उलझनों में गंवाने की जरूरत नहीं है। रेगिस्तान में भी फूल खिलते हैं, अगर जड़ें मजबूत हों। अपने आप में हम अगर सुलझ गए, दुनिया खुद सुलझ जाएगी।

हाईवा की टक्कर से एक की मौत, महिला गंभीर

निरसा (ससे) : निरसा थाना क्षेत्र के खुशरी मोड़ के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में पांड्रा गांव निवासी ६० वर्षीय मनोज सिन्हा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि स्कूटर पर लिफ्ट लेकर सवार वीणा घोष गंभीर रूप से घायल हो गई।

मृतक का फाईल फोटो

जानकारी के अनुसार, मनोज सिन्हा स्कूटर से निरसा बाजार जा रहे थे। रास्ते में पांड्रा गांव की रहने वाली वीणा घोष ने उनसे लिफ्ट ली थी। जैसे ही वे खुशरी मोड़ के समीप पहुंचे, सामने से आ रहे एमपीएल परिवहन के अधीन संचालित एक हाईवा ने उनकी स्कूटर को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कूटर सड़क पर गिर गई और हाईवा का पिछला पहिया मनोज सिन्हा के ऊपर चढ़ गया, जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई।हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई। आसपास के लोग बड़ी संख्या में घटनास्थल पर पहुंच गए। घायल वीणा घोष को तत्काल एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। चिकित्सकों के अनुसार उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। घटना की सूचना मिलते ही निरसा थाना पुलिस और स्थानीय विधायक अरूप चटर्जी मौके पर पहुंचे। इसके बाद उन्होंने स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने शव को कैंजे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया तथा दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है।

हादसे के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखा गया। ग्रामीणों का कहना है कि इस सड़क पर एमपीएल परिवहन के भारी वाहनों का दिनरात आवागमन होता है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बना रहता है। लोगों ने प्रशासन से इस मार्ग पर सुरक्षा के ठोस इंतजाम करने और भारी वाहनों की आवाजाही पर नियंत्रण लगाने की मांग की है।

बंद घर से लाखों की चोरी

धनबाद (कासं) : भूली के आजाद नगर स्थित अमन सोसायटी गेट नंबर१ में चोरों ने एक बंद मकान को निशाना बनाते हुए लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। घटना हाउस नंबर-१३५ निवासी शाहनवाज खान के घर में बीती रात हुई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार, शाहनवाज खान ने अपने इलाज के लिए बैंक से ५ लाख का लोन लिया था। यह रकम घर के लॉकर में रखी गई थी। पीड़ित परिवार का आरोप है कि चोर लगभग ५ लाख नकद के अलावा सोने के झुमके और चांदी के कुछ आभूषण भी अपने साथ ले गए। घटना की सबसे अहम कड़ी सीसीटीवी फुटेज है, जिसमें संदिग्ध व्यक्ति चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों की पहचान करने में जुटी हुई है।

सूचना मिलने के बाद भूली ओपी पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। मामले की जांच कर रहे एएसआई मनोज ओझा ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच की जा रही है तथा जल्द ही आरोपियों की पहचान कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। वार्ड संख्या १७ के पार्षद इम्तियाज अंसारी ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू की। घटना के बाद स्थानीय लोगों में भय और नाराजगी का माहौल है। लोगों ने पुलिस प्रशासन से क्षेत्र में रात्रि गश्ती बढ़ाने और आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है।

मां तारा प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव कलश यात्रा के साथ शुरू

धनबाद (कासं) : मां तारा भक्त मंडली की ओर से कुम्हारपट्टी स्थित नवनिर्मित अघोर आश्रम में मां तारा की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का शुभारंभ भव्य कलश यात्रा के साथ हुआ। धार्मिक आस्था और श्रद्धा से ओतप्रोत इस आयोजन में बड़ी संख्या में महिलाओं और श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कलश यात्रा मंदिर प्रांगण से शुरू होकर मनईटांड़, पुराना स्टेशन रोड और रेलवे कॉलोनी होते हुए नमदेश्वर महादेव मंदिर पहुंची। वहां वैदिक मंत्रोच्चार के बीच कलश में पवित्र जल भरने के बाद श्रद्धालु पुनः शोभायात्रा के साथ मंदिर परिसर लौटे।

मुख्य पुजारी प्रवीण मिश्रा ने बताया कि तीन दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान के पहले दिन कलश यात्रा निकाली गई है। दूसरे दिन नगर भ्रमण के उपरांत वैदिक विधिविधान के साथ मां तारा की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जबकि तीसरे दिन विशाल भंडारे का आयोजन होगा, जिसमें श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद वितरण किया जाएगा।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में समाजसेवी दिलीप सिंह शामिल हुए और मां तारा का आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि ऐसे धार्मिक आयोजन समाज में एकता, भाईचारे और सांस्कृतिक मूल्यों को मजबूत करते हैं। उन्होंने युवाओं से भी धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों में बढ़चढ़कर भाग लेने की अपील की। इस अवसर पर गुरु चंद्रभूषण चौधरी, प्रवीण मिश्रा, अनिकेत रॉय, सुधीर अघोरी, बड़े महतो, पिंटू मोदी, तारक दा, गौतम सिंह, श्याम कुमार, अक्षय कुमार महतो, वीरेंद्र शंकर, गौतम महतो सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। पूरे क्षेत्र में भक्तिमय माहौल बना रहा और जयकारों से वातावरण गूंज उठा।

डीसी ने की जिला कार्यकारिणी समिति की बैठक

धनबाद (कासं) : धनबाद की कार्यकारिणी बैठक उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन की अध्यक्षता में आयोजित की गई। जिसमें जिले की स्कूली शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने, संविदा कर्मियों के कल्याण और प्रशासनिक पारदर्शिता को लेकर कई अहम प्रस्तावों पर विचार और निर्णय लिए गए। संतोषप्रद सेवा के आधार पर प्रखण्ड साधनसेवियों एवं संकुल साधनसेवियों के मानदेय में ३ प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि को स्वीकृति दी गई है, जो विगत १ अप्रैल के प्रभाव से लागू होगी। कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय एवं झारखण्ड बालिका आवासीय विद्यालय के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों (लेखापाल, रसोइया और रात्री प्रहरी) के मानदेय में ४ प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि की मंजूरी दी गई है। यह वृद्धि जिला चयन समिति द्वारा उनके विगत वर्ष के कार्यों की समीक्षा के बाद दी जाएगी। सुरक्षा के दृष्टिकोण से धनबाद जिले के २४ जर्जर विद्यालय भवनों को चिन्हित किया गया है, जहाँ पठनपाठन का कार्य कराना जोखिम भरा है। इन विद्यालयों के बच्चों को निकट के सुरक्षित विद्यालयों, सामुदायिक भवनों, पंचायत भवनों या पैक्स भवनों में अस्थाई रूप से शिफ्ट किया जाएगा।

प्रखण्ड केलियासोल एवं एग्यारकुण्ड में रिसोर्स शिक्षक कार्यरत नहीं होने के कारण समावेशी शिक्षा कार्य प्रभावित हो रहा था, जिसे देखते हुए रिसोर्स शिक्षकों का पुनर्युक्तिकरण किया जाएगा। केलियासोल प्रखण्ड में कोआर्डिनेटर न होने के कारण काम प्रभावित हो रहा था, जिसे सुधारने के लिए दूसरे प्रखण्ड से यहाँ स्थानांतरण किया जाएगा। उत्कृष्ट विद्यालय, निरसा की वार्डनसहशिक्षिका अनिशा सिंह के कार्यकाल में दसवीं का परिणाम अच्छा नहीं रहने के कारण विभागीय निर्देशानुसार उनके स्थानांतरण पर विचार किया गया।

इसके अलावा लंबे समय से एक ही स्थान पर जमे प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी, लेखापाल-सहकंप्यूटर ऑपरेटरों के भी स्थानांतरण पर चर्चा हुई। बैठक में उप विकास आयुक्त सन्नी राज, जिला शिक्षा पदाधिकारी अभिषेक झा, जिला शिक्षा अधीक्षक आयुष कुमार, जिला भूअर्जन पदाधिकारी राम नारायण खलखो, डीआईओ सुनीता तुलस्यान समेत समिति के अन्य सदस्य मौजूद रहे।

मतदाता सूची में सुधार संबंधित जानकारी ली गई

पुटकी (ससे) : कांग्रेस पार्टी के बाघमारा विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी अवध नारायण प्रसाद एवं प्रखण्ड कांग्रेस के संगठन प्रभारी बिजेन्द्र पासवान के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमण्डल बाघमारा बाजार, माटीगढ़ा के बूथ नंबर ५, ६, ७, ८, ९ एवं १० तथा बाघमारा बाजार क्षेत्र के बूथ नम्बर ८३, ८४, ८५, ८६, ८८, ८९ एवं ९३ के बूथों पर पहुंचकर एसिड आई आर के तहत मतदाता सूची में सुधार संबंधित जानकारी ली गई। बूथों पर भ्रमण के दौरान धनबाद जिला कांग्रेस कमिटी के सचिव एवं इंटक नेता इंदल यादव, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता धनेश्वर ठाकुर, यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव आकाश कुमार, राहुल बजरंगी, सावन सुमन, रवि पासवान, रंजन यादव आदि शामिल थे।

महादेव मंदिर के प्राणप्रतिष्ठा को ले देवी देवताओं को कराया गया नगर भ्रमण

धनबाद (कासं) : सहयोगी नगर सेक्टर३ स्थित नवनिर्मित भव्य श्री श्री विश्वनाथ महादेव मंदिर में तीन दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के द्वितीय दिन वैदिक मंत्र वेदी पूजन, अन्नाधिवास तथा देवीदेवताओं का नगर भ्रमण किया गया। तत्पश्चात सहयोगी नगर एवं आसपास क्षेत्र के भक्तजन उपस्थित होकर प्रसाद ग्रहण किया।

कार्यक्रम में उपस्थित मंदिर कमिटी के सदस्य एवं श्री राम सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय प्रताप सिंह ने बताया कि शाम में कला निकेतन, भूली द्वारा कृष्ण लीला एवं महारथी कर्ण नाटक की प्रस्तुति दी जाएगी। १७ जून को मुख्य अनुष्ठान के तहत मूर्तियों की विधिविधान से प्राण प्रतिष्ठा, महायज्ञ की पूर्णाहुति और विशाल महाभंडारा का आयोजन होगा। इस भव्य आयोजन को सफल बनाने में आयोजन समिति के उदय प्रताप सिंह, हरीश सिंह, मृत्युंजय तिवारी, कैशव नायक, राजेश कुमार सहित सभी सदस्य तनमन से जुटे हुए हैं।

जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति की बैठक आयोजित

धनबाद (कासं) : उप विकास आयुक्त सन्नी राज की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि, जिले के सभी २३ बैंकों के शाखा प्रबंधक, जिला समन्वयक एवं संबंधित विभागों के पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में एनपीसीआई, किसान क्रेडिट कार्ड एवं फसल ऋण, मुद्रा ऋण योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम तथा डीपीएम से संबंधित मामलों की विस्तृत समीक्षा की गई। विभिन्न योजनाओं के तहत प्राप्त आवेदनों की स्थिति, स्वीकृति एवं वितरण की प्रगति पर चर्चा करते हुए संबंधित बैंकों को लक्ष्य के अनुरूप कार्य करने का निर्देश दिया गया।

बैठक के दौरान डीडीसी ने विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लंबित आवेदनों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सभी बैंकों को निर्देश दिया कि लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करें ताकि पात्र लाभुकों को समय पर लाभ मिल सके। उन्होंने प्रखंड स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठकों में बैंक अधिकारियों की उदासीनता पर भी कड़ी नाराजगी जताई। डीडीसी ने कहा कि कई बैंक शाखाओं द्वारा प्रखंड स्तरीय बैठकों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है, जो स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने निर्देश दिया कि अगली बैठक में संबंधित बैंक प्रबंधक स्वयं उपस्थित रहें तथा सभी आवश्यक प्रतिवेदनों एवं अद्यतन आंकड़ों के साथ भाग लें। डीडीसी ने सभी बैंक प्रबंधकों को २३ जून को आयोजित होने वाली समीक्षा बैठक में पूर्ण तैयारी एवं सभी आवश्यक प्रतिवेदनों के साथ उपस्थित रहने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं वित्तीय समावेशन के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सभी बैंकों की सक्रिय सहभागिता आवश्यक है। बैठक में विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशानिर्देश भी दिए गए।

भाजपाइयों ने चलाया स्वच्छता अभियान

कतरास (ससे) : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के १२ साल पूरे होने के मौके पर सिनीडीह मंडल की जनता भारतीय पार्टी की ओर से न्यूक्लेश कोबिलबेरा के हनुमान नगर में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान हनुमान मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र सहित चबूतरा और शेड की सफाई की गई। मंत्री मंडल के अध्यक्ष, पूर्व मंडल अध्यक्ष उत्तम गायली, उपाध्यक्ष हरेंद्र गिरि, उपाध्यक्ष चंचल बाउरी, राजेश राजवार, अमन बरनवाल आदि उपस्थित थे।

तत्काल टिकट को ले दलालों पर कार्रवाई की मांग

धनबाद (कासं) : नारी शक्ति जन सुविधा केन्द्र, भूली की अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद, विधायक तथा मेयर प्रत्याशी रह चुकीं लक्ष्मी देवी ने रेलवे की तत्काल टिकट व्यवस्था में व्याप्त अनियमितताओं और टिकट दलालों की सक्रियता पर चिंता जताते हुए रेलवे प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है।

रेलवे अधिकारियों को दिए गए आवेदन में लक्ष्मी देवी ने बताया कि वह वर्ष २०१३ से तमिलनाडु के वेल्लोर स्थित सीएमसी अस्पताल में गंभीर बीमारी का इलाज करा रही हैं। उनका अगला चिकित्सकीय परामर्श २२ जून को निर्धारित है, जिसके लिए उन्हें १७ जून को तत्काल आरक्षण टिकट की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि उनके साथ तीन अन्य लोगों का भी आरक्षण कराया जाना आवश्यक है। लक्ष्मी देवी ने आरोप लगाया कि तत्काल टिकट काउंटरों पर अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं और टिकट दलालों के माध्यम से टिकटों की कालाबाजारी की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। इसका खामियाजा आम यात्रियों,

विशेषकर गंभीर रूप से बीमार मरीजों और उनके परिजनों को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने रेलवे प्रशासन से अनुरोध किया है कि उनकी चिकित्सकीय आवश्यकता को देखते हुए तत्काल आरक्षण टिकट उपलब्ध कराया जाए तथा तत्काल टिकट प्रणाली की निष्पक्ष जांच कर दोषी दलालों और संबंधित लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि इससे आम यात्रियों को राहत मिलेगी और रेलवे व्यवस्था के प्रति जनता का भरोसा और मजबूत होगा।

बीसीसीएल में स्वच्छता पखवाड़ा अभियान का शुभारंभ

धनबाद (कासं) : स्वच्छ भारत मिशन के तहत आयोजित राष्ट्रव्यापी स्वच्छता अभियान के अंतर्गत कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार कोयला भवन मुख्यालय में बीसीसीएल द्वारा 'स्वच्छता पखवाड़ा' का शुभारंभ किया गया। स्वच्छता के महत्व के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने तथा स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण के निर्माण में जनभागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कंपनी स्तर पर १६ जून से ३० जून तक चलने वाले इस अभियान के अंतर्गत कोयला भवन मुख्यालय एवं विभिन्न क्षेत्रों में स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण संबंधी कई गतिविधियाँ संचालित की गई।

मुख्य कार्यक्रम कोयला भवन मुख्यालय के बेसमेंट हॉल में आयोजित हुआ, जहाँ निदेशक (तकनीकी/संचालन) श्री संजय कुमार सिंह तथा निदेशक, तकनीकी (परियोजना एवं योजना), राजीव कुमार सिन्हा ने कार्यक्रम में उपस्थित मुख्यालय के सभी अधिकारियों एवं कर्मियों को स्वच्छता शपथ दिलाई। इस अवसर पर महाप्रबंधक (मानव संसाधन) कुमार मनोज, महाप्रबंधक (सतर्कता) एन.के. ठाकुर, महाप्रबंधक (भूसंपदा) अरविंद सिन्हा, महाप्रबंधक (पीएफ एवं पेंशन) विद्युत् साहा, विभागाध्यक्ष (प्रशासन) मनीष मिश्रा, विभागाध्यक्ष (सीएसआर) सुरेन्द्र भूषण सहित कोयला भवन मुख्यालय के अन्य महाप्रबंधकगण, विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे।

महात्मा गाँधी के स्वच्छ और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए सभी कार्मिकों ने स्वच्छता शपथ ली और अपने परिसर, कार्यस्थल, समाज और परिवेश को साफ़ रखने तथा दूसरों को भी स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का प्रण लिया। सभी ने सामूहिक रूप से यह संकल्प लिया कि वे स्वच्छता को व्यक्तिगत जिम्मेदारी मानकर न केवल स्वयं सफाई रखेंगे, बल्कि दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। सभी ने प्रतिवर्ष १०० घंटे अर्थात प्रत्येक सप्ताह २ घंटे श्रमदान कर स्वच्छता के संकल्प को चरितार्थ करने का संकल्प लिया।

उपस्थित सभी अधिकारियों एवं कर्मियों ने इस दौरान स्वच्छ भविष्य के संदेश के साथ सिग्नेचर कैम्पेन में भाग लिया और स्वच्छता से जुड़े अपने संदेश साझा किए। प्रतिभागियों ने इसके साथ ही स्वच्छता सेल्फी प्वॉइंट पर अपनी तस्वीरें लेकर स्वच्छता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की।

अपने संबोधन में निदेशक (तकनीकी/संचालन) संजय कुमार सिंह ने कहा कि स्वच्छता एक उच्च मानवीय गुण है, तथा हर व्यक्ति को इसे अपने आचरण में ढालना चाहिए, जिससे वह अपने आसपास के परिवेश एवं वातावरण को स्वच्छ रखने में योगदान दे सके। निदेशक तकनीकी (परियोजना एवं योजना) राजीव कुमार सिन्हा ने कहा कि स्वच्छता हम सभी का नैतिक दायित्व है और हम सभी को स्वच्छता की आदत अपनाते हुए राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देना चाहिये।

उल्लेखनीय है कि मुख्यालय के अतिरिक्त बरोरा, ब्लॉक२, सीवी, सिजुआ, ईजे (पूर्वी झरिया), डब्ल्यूजे (पश्चिमी झरिया), बस्ताकोला एवं लोदना सहित बीसीसीएल के सभी क्षेत्रों में स्वच्छता शपथ कार्यक्रम आयोजित किए गए। अधिकारियों एवं कर्मियों ने स्वच्छता शपथ लेते हुए अपने कार्यस्थलों एवं आसपास के परिवेश को स्वच्छ रखने का संकल्प लिया। विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में सेल्फी प्वॉइंट स्थापित किए गए तथा ब्लॉक२ क्षेत्र सहित विभिन्न स्थानों पर एंटीलिटरिंग पोस्टर प्रदर्शित कर स्वच्छता के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया गया।

स्वच्छता पखवाड़ा के आगामी कार्यक्रमों के अंतर्गत केंद्रीय अस्पताल एवं क्षेत्रीय अस्पतालों में स्वच्छता अभियान, बीसीसीएल कॉलोनियों में तालाबों, जल टंकियों एवं सार्वजनिक स्थलों की सफाई, वर्षा जल संचयन प्रणालियों का निरीक्षण, सिग्नेचर अभियान, स्वच्छता जागरूकता कार्यशालाएं, परियोजना विद्यालयों में चित्रकला प्रतियोगिता, पौधारोपण अभियान, साइबर स्वच्छता जागरूकता सत्र, स्वच्छता रैली तथा धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों पर विशेष स्वच्छता अभियान सहित विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति व्यापक जनजागरूकता विकसित करना है।

गौरतलब है कि स्वच्छता पखवाड़ा अभियान के साथ-साथ बीसीसीएल में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में १५ जून से सात दिवसीय योग शिविर का भी आयोजन किया जा रहा है। शिविर के दूसरे दिन आज आयोजित योग सत्र में अधिकारियों एवं कर्मियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया तथा योग प्रशिक्षक श्री डी.एन. पासवान के नेतृत्व में विभिन्न योग क्रियाओं का अभ्यास किया। योग शिविर का समापन २१ जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर किया जाएगा।

ईसीएल ने सामुदायिक व्यय का विस्तार किया

संकटोडिया (ससे): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार निर्वाचित भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले नेता के रूप में ४,३९९ दिन पूर्ण करने के अवसर पर, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल) पूर्वी भारत के कोयला क्षेत्रों में केंद्र सरकार के 'नया भारत निर्माण' के दृष्टिकोण को ठोस विकासात्मक परिणामों में परिवर्तित करने की दिशा में अपनी भूमिका को और सुदृढ़ कर रही है।

कोल इंडिया लिमिटेड की इस अनुषंगी कंपनी ने अपनी सामुदायिक निवेश रणनीति को और अधिक प्रभावी बनाते हुए अपने कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) व्यय का लगभग ८० प्रतिशत हिस्सा अपनी खनन परियोजनाओं के २५ किलोमीटर के दायरे में स्थित क्षेत्रों पर केंद्रित किया है। कंपनी का यह दृष्टिकोण सरकार की स्थानीय स्तर तक विकास योजनाओं की प्रभावी पहुँच सुनिश्चित करने की नीति के अनुरूप है।

वित्तीय वर्ष २०२५-२६ के दौरान ईसीएल ने सीएसआर गतिविधियों पर निर्धारित

₹७.५१ करोड़ के बजट के मुकाबले लगभग ₹८.८२ करोड़ व्यय किए, जो ११७ प्रतिशत उपयोगिता को दर्शाता है। यह व्यय मुख्य रूप से स्वास्थ्य, पोषण एवं कौशल विकास जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित रहा, जो मोदी सरकार की समावेशी विकास नीति के प्रमुख स्तंभ हैं। स्वास्थ्य एवं पोषण पर सर्वाधिक व्यय किया गया, जबकि आजीविका से जुड़े कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से वंचित एवं परियोजना-प्रभावित समुदायों की रोजगार क्षमता बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया।

कंपनी की विकासात्मक पहलों में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता बढ़ाना, व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना तथा ग्रामीण अवसंरचना का सृजन शामिल है। इनमें सिंचाई प्रणालियों का पुनरुद्धार एवं जलाशयों का पुनर्जीवन जैसे कार्य भी सम्मिलित हैं, जो पश्चिम बंगाल एवं झारखंड के खनन-प्रधान जिलों में स्थानीय आर्थिक तंत्र को नई दिशा प्रदान कर रहे हैं।

ईसीएल का विकास मॉडल केंद्र सरकार की उस व्यापक नीति के अनुरूप है, जिसमें केवल कल्याणकारी सहायता के वितरण के बजाय क्षमता निर्माण पर बल दिया जा रहा है। विशेष रूप से वंचित युवाओं तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदायों को लक्षित कौशल विकास कार्यक्रमों का उद्देश्य स्थानीय आबादी को औपचारिक आर्थिक गतिविधियों से जोड़ना है, जिससे सरकार के रोजगार सृजन एवं आत्मनिर्भरता संबंधी लक्ष्यों को समर्थन प्राप्त हो सके।

इसके साथ ही पर्यावरणीय सततता भी कंपनी की एक प्रमुख प्राथमिकता के रूप में उभरी है। ईसीएल ने अपनी सीएसआर पहलों को पारिस्थितिकीय पुनर्स्थापन तथा उत्तरदायी खनन प्रथाओं से जोड़ते हुए पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। बढ़ती नियामकीय आवश्यकताओं एवं जलवायु संबंधी चुनौतियों के संदर्भ में यह पहल विशेष महत्व रखती है।

सीएसआर व्यय के क्षेत्रीय वितरण से संतुलित विकास की प्रतिबद्धता स्पष्ट होती है। पश्चिम बंगाल एवं झारखंड दोनों राज्यों में लगभग समान रूप से संसाधनों का आवंटन किया गया है, जिससे पूर्वी भारत के संसाधन-समृद्ध क्षेत्रों में ईसीएल की विकास सहयोगी के रूप में भूमिका और अधिक सुदृढ़ हुई है।

कंपनी की आंतरिक प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्टों के अनुसार स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच, शैक्षिक उपलब्धियों तथा आजीविका सृजन के क्षेत्रों में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किए गए हैं। यह तथ्य दर्शाता है कि कंपनी केवल व्यय-आधारित दृष्टिकोण तक सीमित न रहकर परिणामोन्मुख विकास मॉडल की दिशा में अग्रसर है।

निदेशक मंडल स्तर की निगरानी से लेकर विकेन्द्रीकृत कार्यान्वयन तक विस्तृत बहु-स्तरीय प्रशासनिक ढाँचे के माध्यम से ईसीएल ने अपनी सीएसआर गतिविधियों को संस्थागत स्वरूप प्रदान किया है। इससे सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार संबंधी प्राथमिकताओं के अनुरूप पारदर्शिता, जवाबदेही एवं व्यापक प्रभाव सुनिश्चित हुआ है।

जब केंद्र सरकार अवसंरचना-आधारित विकास एवं सामाजिक समावेशन को और अधिक गति दे रही है, तब ईसीएल की विकसित होती सीएसआर रणनीति यह दर्शाती है कि सार्वजनिक उपक्रम केवल आर्थिक विकास के वाहक ही नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर सामाजिक परिवर्तन के प्रभावी साधन भी बन रहे हैं। इस प्रकार, 'नया भारत' की परिकल्पना को देश के औद्योगिक एवं खनन क्षेत्रों में साकार करने में ईसीएल महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

प्लॉट/भूमि के लीज नवीनीकरण हेतु सेल की व्यापक नीति जारी

बोकारो (ससे): स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) द्वारा अपनी भूमि संपत्तियों के इष्टतम उपयोग और कुशल प्रबंधन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भूखंडों एवं भूमि के पट्टा (लीज) नवीनीकरण के लिए एक व्यापक नीति की घोषणा की गई है। १५ मई २०२६ से प्रभावी यह नीति पट्टा नवीनीकरण की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सुस्पष्ट और सुगम बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह मानक व्यवस्था विशेष रूप से केवल उन मौजूदा पट्टों के नवीनीकरण मामलों पर लागू होगी जिनकी अवधि समाप्त हो चुकी है या जो नवीनीकरण के लिए देय हैं, इसे किसी भी नए आवंटन पर लागू नहीं किया जाएगा।

इस नीति के अंतर्गत भूमि के पट्टों को तीन विशिष्ट श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। श्रेणी-ख में वाणिज्यिक संगठनों जैसे केंद्रीय लोक उपक्रम, राज्य सार्वजनिक उपक्रम, बैंक, एटीएम, बीमा कंपनियां, निजी प्रतिष्ठान, पेट्रोल पंप और वाणिज्यिक परिसरों को शामिल किया गया है। श्रेणी-२ के तहत केंद्रीय और राज्य सरकार के विभागों, नगर निगमों, पेशेवर निकायों, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी और शैक्षणिक संस्थानों को रखा गया है। श्रेणी-३ में सामाजिक, धार्मिक, चैरिटेबल और कल्याणकारी संस्थाओं जैसे मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, श्मशान घाट, कब्रिस्तान, चैरिटेबल स्कूल एवं अस्पताल, सार्वजनिक पुस्तकालय और दिव्यांगजनों व महिला कल्याण के लिए कार्यरत संगठनों को शामिल किया गया है।

पट्टा नवीनीकरण शुल्क को अधिक तर्कसंगत बनाते हुए श्रेणी-ख (वाणिज्यिक) के लिए वर्तमान भूमि प्रीमियम का २५ प्रतिशत और श्रेणी-२ (सरकारी/ गैर-वाणिज्यिक) के लिए १० प्रतिशत शुल्क निर्धारित किया गया है, जबकि श्रेणी-३ (सामाजिक/ धार्मिक/ धर्मार्थ) के लिए मात्र १ रुपये की टोकन राशि तय की गई है। नए गाइड लाइन के तहत वार्षिक ग्राउंड रेंट और सेवा शुल्क के तीन गुना के बराबर राशि ब्याज-मुक्त सिक्योरिटी डिपाजिट के तहत देय होगा। इसी प्रकार वार्षिक ग्राउंड रेंट अब नवीनीकरण शुल्क का १ प्रतिशत होगा जिसमें प्रत्येक पांच वर्ष में पिछले भुगतान पर १० प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी जबकि पुराने नियम के अनुसार यह भूमि मूल्यांकन का १ प्रतिशत हुआ करता था। नए गाइड लाइन के तहत वार्षिक सेवा शुल्क अब नवीनीकरण शुल्क का २ प्रतिशत होगा जिसमें प्रत्येक पांच वर्ष में पिछले भुगतान पर १० प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी जबकि पुराने नियम के अनुसार यह भूमि मूल्यांकन का २ प्रतिशत हुआ करता था। इसके अतिरिक्त, १ अप्रैल २००८ को या उसके बाद नवीनीकृत हो चुके मामलों के लिए नए गाइडलाइन के अनुसार ग्राउंड रेंट और सेवा शुल्क का पुनर्निर्धारण किया जाएगा तथा किसी भी अतिरिक्त भुगतान को भविष्य के बकाये में समायोजित किया जाएगा। वैसे मामले जहाँ नवीनीकरण नहीं कराये जाने के कारण लीज़ पहले ही ख़त्म हो चुका है, उन्हें एक मौका देते हुए यह प्रावधान रखा गया है कि यदि नई नीति जारी होने के एक वर्ष के भीतर वे नवीनीकरण करा लेते हैं, तो उन्हें दंडात्मक ब्याज से छूट देते हुए केवल भारतीय स्टेट बैंक की नकद साख दर पर साधारण ब्याज देय होगा।निर्धारित अवधि के बाद नवीनीकरण कराने पर १२ प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण दंडात्मक ब्याज देय होगा। इसके अलावा लगातार डिफॉल्ट करने पर पट्टाधारक को अनधिकृत कब्जाधारी मानकर बेदखली एवं अन्य विधि सम्मत कार्रवाई भी की जा सकती है।

यह नीति बोकारो इस्पात संयंत्र की भूमि संपत्तियों के संरक्षण, कानूनी अनुपालन और शहरी बुनियादी ढांचे के सुव्यवस्थित विकास को सुनिश्चित करने की दिशा में अहम है।

चिरेका कर्मचारियों को महाप्रबंधक ने पुरस्कार प्रदान कर किया सम्मानित

चित्तरंजन(ससे): देवेंद्र कुमार, वरिष्ठ तकनीशियनविद्युत विभाग तथा ओम शंकर, वरिष्ठ तकनीशियन यांत्रिक विभाग को आज, १६.०६.२०२६ को, मई २०२६ माह के लिए मैन ऑफ़ द मंथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मोहित चंद्रा , महाप्रबंधक ने यह पुरस्कार उनके असाधारण प्रदर्शन, समर्पण और योगदान के लिए प्रदान किया और उन्हें बधाई दी । देवेंद्र कुमार काफी मेहनती कर्मचारी हैं। ये सेंसर, पावर, केबल, कोर और कंट्रोल जैसे केबल विस्तारीकरण का काम ड्राइंग के अनुसार करते हैं। अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने कई बार केबल के उपयोग में आने वाले लंबाई मात्रा को सीमित कर कार्य कुशलता का परिचय दिया । श्री ओम

शंकर,व्हील शॉप के एक्सल सेक्शन में टर्नर (सीनियर टेक्नीशियन) के रूप में कार्यरत है।उन्होंने एक माह में व्हील सेट के अब तक के उच्चतम उत्पादन को हासिल करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

इनकी लगन, कौशल और निरंतर प्रयास ने शॉप के उत्पादन लक्ष्यों को पूरा करने में अहम भूमिका निभाई। ये व्हील शॉप के बहुकुशल कर्मचारियों में से एक हैं और सभी प्रकार की टर्निंग मशीनों को कुशलतापूर्वक संचालित करने में सक्षम हैं। इनकी बहुमुखी प्रतिभा और चुनौतीपूर्ण कार्यों को सफल बनाने की तत्परता इनकी उत्कृष्टता के प्रति संकल्प को दर्शाती है।

स्कूली बस का पिछड़ा हिस्सा पुल के नीचे गिरा,कोई हताहत नहीं

डुमरी (ससे): डुमरी थाना क्षेत्र के परसबेडा पुल पर एक बड़ा हादसा होते-होते बच गया।प्रोग्रेसिव पब्लिक स्कूल की बस पुल पार करने के दौरान बस के पिछले हिस्से का चक्का पुल के किनारे से नीचे उतर गया।गनीमत रही कि चालक की सूझबूझ और सतर्कता के कारण एक बड़ी दुर्घटना होने से बच गई।जबकि राहत की बात यह रही कि बस में सवार सभी बच्चे सुरक्षित रहे। वहीं घटना की खबर जैसे ही बस में सवार बच्चों के माता पिता व अभिभावकों को हुई वे दौड़े दौड़े घटना स्थल पहुंचे और बच्चों को सकुशल देखकर राहत की सांस ली।लोगों ने सभी वाहन चालकों से अपील है कि वाहन सावधानी पूर्वक और नियंत्रित गति से चलाएं, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं से बचा जा सके।क्योंकि सतर्कता ही सुरक्षा कवच है।

रेलकर्मियों ने महाप्रबंधक से मुलाकात कर अपनी समस्याओं से अवगत कराया

हाजीपुर (ससे): मुख्यालय, हाजीपुर में ०४ रेलकर्मियों एवं उनके आश्रितों ने पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह से मुलाकात की तथा अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत कराया । महाप्रबंधक ने संबंधित विभागों को प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही करते हुए निर्धारित समय सीमा में केस निष्पादन के निर्देश दिए। विदित हो कि रेलकर्मियों की विभागीय समस्याओं के निष्पादन के उद्देश्य से महाप्रबंधक से मुलाकात हेतु प्रत्येक मंगलवार का दिन निर्धारित किया गया है। इसके लिए रेलकर्मी अपना नाम पूर्व में कार्मिक विभाग में पंजीकृत करवाकर मंगलवार को महाप्रबंधक से मुलाकात कर अपनी समस्याएं उनके सामने रख सकते हैं ।

बीएलओ एक और दो को मिला प्रशिक्षण,मिली जानकारी

डुमरी (ससे): प्रखण्ड सह अंचल कार्यालय के सभागार में मंगलवार को बूथ नंबर ०१ से ७० तक के बीएलओ और बीएलओ-२ का प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया।सीओ सह प्रभारी बीडीओ शशिभूषण वर्मा के नेतृत्व में आयोजित शिविर में निर्वाचन आयोग के बीएलओ और राजनीतिक दलों के द्वारा बनाये गये बीएलओ-२ शामिल हुए।प्रशिक्षक के रूप में सुजीत पाठक ने बताया कि मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य डुमरी प्रखंड में ९१ फीसदी मैपिंग कार्य पूर्ण हो गई है।

छुटे हुए नाम की जांच बीएलओ एवं बीएलओ-२ संयुक्त रूप से करेंगे।छुटे हुए नाम जोड़ने के लिए ११ प्रमाण पत्रों में से किसी एक प्रमाण पत्र की जरूरत होगी।बताया कि एसआइआर से किसी को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है।किसी भी योग्य मतदाता का नाम नहीं छुटेगा।

प्रशिक्षण शिविर में कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष नागेश्वर मंडल जिला उपाध्यक्ष महेश भगत युवा कांग्रेस के जिला महासचिव गुड्डु मलिक आजसू नेता छक्कन महतो झामुमो नेता पंकज कुमार कांग्रेस के भुनेश्वर दास, खुर्शीद अंसारी, शिवा दास, घनश्याम शर्मा, दिलीप मंडल, मुस्तफा अंसारी, तुराबलि अंसारी, निजामुद्दीन अंसारी, संजय मंडल, मुमताज़ अंसारी, महेंद्र बिन्द, मुबारक अंसारी, शिवम सेठ, धर्मेन्द्र साव, अबुल अंसारी, सिराज अंसारी, असलम अंसारी, संजय कुमार, इम्तियाज अंसारी, संतोष मंडल, मुकेश मुर्मू, करीम बख्श अजीत स्वर्णकार आदि उपस्थित थे।प्रखंड के बूथ संख्या ७१ से २११ तक के बीएलओ और बीएलओ टू का प्रशिक्षण दो पालियों में १७ जून को होगी।

28 जून को जिलेभर में आयोजित होगा राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान

बोकारो (ससे): राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस (एनआइडी) के तहत आगामी २८ जून २०२६ को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की तैयारियों को लेकर समाहरणालय स्थित सभागार में उप विकास आयुक्त (डीडीसी) श्रीमती शताब्दी मजूमदार की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सिविल सर्जन, नोडल पदाधिकारी,सभी प्रखंड चिकित्सा प्रभारी पदाधिकारी तथा विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

बैठक में बताया गया कि राष्ट्रीय पल्स पोलियो दिवस के अवसर पर जिले के सभी २,००५ बूथों पर शून्य से पांच वर्ष तक के बच्चों को पोलियो रोधी खुराक पिलाई जाएगी। इस वर्ष अभियान के तहत ३,५३,०७२ बच्चों को पोलियो की खुराक देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अभियान को सफल बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा व्यापक स्तर पर तैयारी की जा रही है।

उप विकास आयुक्त (डीडीसी) ने कहा कि अभियान की सफलता का आधार बूथ दिवस होता है। इसलिए सभी संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी यह सुनिश्चित करें कि बूथ दिवस पर ही कम-से-कम ९५ प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि तैयार किए गए एक्शन प्लान का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए तथा इसकी नियमित समीक्षा और निगरानी की जाए। उन्होंने सिविल सर्जन को अभियान की

प्रगति पर लगातार नजर रखने तथा आवश्यकतानुसार त्वरित निर्णय लेने का निर्देश दिया।

उप विकास आयुक्त (डीडीसी) ने कहा कि अभियान की सफलता के लिए जनभागीदारी अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाया जाए। उन्होंने शिक्षा विभाग को विद्यालयों में बच्चों के माध्यम से अभिभावकों तक संदेश पहुंचाने तथा पल्स पोलियो दिवस की जानकारी साझा करने का निर्देश दिया।

साथ ही, महिला पर्यवेक्षिका, आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिकाओं को अपने-अपने पोषक क्षेत्रों में घर-घर संपर्क स्थापित कर लोगों को जागरूक करने और अभियान से जोड़ने का निर्देश दिया।

बैठक में सिविल सर्जन डॉ. ए.बी. प्रसाद ने कहा कि गर्मी के मौसम को देखते हुए पोलियो वैक्सीन की गुणवत्ता बनाए रखना प्राथमिकता होगी। इसके लिए सभी केंद्रों पर पर्याप्त मात्रा में आइस पैक एवं कोल्ड चेन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित रहे। २० जून तक प्रशिक्षण और १८ जून तक माइक्रो प्लान तैयार करने का निर्देश

सिविल सर्जन ने सभी प्रखंड चिकित्सा प्रभारी पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि अभियान से जुड़े सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम २० जून तक पूर्ण कर लिए जाएं। साथ ही, प्रत्येक प्रखंड से माइक्रो प्लान तथा मैनपावर आइडेंटिफिकेशन संबंधी प्रतिवेदन १८ जून तक जिला स्तर पर उपलब्ध कराया जाए, ताकि अभियान संचालन में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो।

बैठक में निर्णय लिया गया कि २५ जून से जिलेभर में सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी) तथा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन (आइपीसी) गतिविधियों को और अधिक गति दी जाएगी। इसके तहत विभिन्न माध्यमों से लोगों को अभियान की तिथि, महत्व और बच्चों को पोलियो खुराक दिलाने के प्रति जागरूक किया जाएगा।

अभियान के सफल संचालन के लिए सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, जेएसएलपीएस, जिला समाज कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग तथा पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका और जिम्मेदारियों की विस्तार से समीक्षा की गई। सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने का निर्देश दिया गया।

बैठक में बताया गया कि अभियान के दौरान जिलेभर में २,००५ बूथों के अतिरिक्त ६० ट्रांजिट टीमों तथा २४ मोबाइल टीमों को भी तैनात किया जाएगा। ये टीमें रेलवे स्टेशन, बस पड़ाव, भीड़भाड़ वाले स्थलों तथा दूरस्थ क्षेत्रों में पहुंचकर बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने* का कार्य करेंगी।

अभियान की प्रगति और संचालन व्यवस्था की निगरानी के लिए प्रतिदिन मॉर्निंग एवं इवनिंग समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। इससे किसी भी प्रकार की समस्या का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जा सकेगा।

मौके पर नोडल पदाधिकारी डा. शलिना टुडु, सदर अस्पताल उपाधीक्षक डॉ एन पी सिंह, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी रवि कुमार, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी डॉ सुमन गुप्ता, जिला शिक्षा पदाधिकारी श्री जगरनाथ लोहरा, एपीआरओ अविनाश कुमार सिंह समेत सभी प्रखंड चिकित्सा प्रभारी पदाधिकारी व अन्य उपस्थित थे।

मादक पदार्थों के दुरुपयोग को समाप्त करने हेतु जागरूकता अभियान की शुरुआत

बोकारो (ससे): पर्यटन, कला-संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, रांची तथा जिला प्रशासन, बोकारो के संयुक्त तत्वावधान में मंगलवार को चंदनकियारी स्थित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मादक पदार्थों के दुरुपयोग को समाप्त करने हेतु जागरूकता अभियान-२०२६ का शुभारंभ* किया गया।अभियान का उद्देश्य *युवाओं एवं आम नागरिकों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक कर नशामुक्त समाज के निर्माण के लिए प्रेरित करना है।

अभियान के दौरान उपस्थित प्रशिक्षकों, खेल मित्रों एवं खिलाड़ियों ने नशे से दूर रहने तथा समाज में नशामुक्ति के प्रति व्यापक जनजागरूकता फैलाने* की शपथ ली। सभी प्रतिभागियों ने मादक पदार्थों के सेवन के विरुद्ध लोगों को जागरूक करने और स्वस्थ समाज निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प व्यक्त किया। कार्यक्रम के अंतर्गत नशामुक्ति के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने के लिए ३ किलोमीटर की जागरूकता रैली निकाली* गई। रैली में शामिल खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों ने विभिन्न नारों और संदेशों के माध्यम से लोगों को मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों से अवगत कराया तथा नशे से दूर रहने की अपील की।

अभियान के तहत बताया गया कि नशा व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। यह केवल व्यक्ति ही नहीं, बल्कि उसके परिवार और समाज के लिए भी नुकसानदायक है। ऐसे में जागरूकता अभियान लोगों को नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराते हुए उन्हें नशामुक्त जीवन अपनाने के लिए प्रेरित करने का सशक्त माध्यम है। कार्यक्रम में *प्रशिक्षक मोहन साहू, महेंद्र करमाली, हेमंत कुमार, आशु भाटिया, चौहान महतो, खेल मित्र तथा चंदनकियारी खेल केंद्रों के खिलाड़ी एवं अन्य* प्रतिभागी उपस्थित थे।

जन समस्याओं के समाधान को लेकर आयोजित हुआ लोक संवाद डीडीसी ने सुनीं समस्याएं

बोकारो (ससे): समाहरणालय सभागार में मंगलवार को आयोजित हम आपको सुनते हैं... (लोक संवाद) कार्यक्रम में उप विकास आयुक्त (डीडीसी) श्रीमती शताब्दी मजूमदार ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे नागरिकों की समस्याओं एवं शिकायतों की सुनवाई की। कार्यक्रम के दौरान लोगों ने अपनी व्यक्तिगत एवं जनहित से जुड़ी समस्याओं को आवेदन के माध्यम से रखा। सुनवाई के क्रम में डीडीसी ने प्रत्येक मामले का अवलोकन करते हुए संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित किया जाए तथा आवेदकों को अनावश्यक रूप से कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़े। लोक संवाद में शिक्षा, स्वास्थ्य, बीएसएल, सामाजिक सुरक्षा, खेल, चास अंचल, डीपीएलआर, राजस्व, आपूर्ति, बीएसएल, नियोजन आदि विभागों से संबंधित मामले थे।

मौके पर अपर समाहर्ता श्री सुनील चन्द्र, डीपीएलआर श्रीमती पूर्णिमा कुमारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी श्री रवि कुमार, जिला भू अर्जन पदाधिकारी श्रीमती अनुराधा कुमारी, जिला नियोजन पदाधिकारी श्री प्रत्युश शेखर, जिला शिक्षा पदाधिकारी श्री जगरनाथ लोहरा, जिला शिक्षा अधीक्षक श्री अतुल कुमार चौबे, जिला खेल पदाधिकारी श्रीमती हेमलता बून, जिला कल्याण पदाधिकारी सुचिता किरण, अंचलाधिकारी चास श्री राम सेवक राम, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी अविनाश कुमार सिंह समेत अन्य उपस्थित थे।

स्थानीय स्तर पर भी हुई सुनवाईजिला प्रशासन के निर्देशानुसार जिले के सभी प्रखंड एवं अंचल कार्यालयों में भी लोक संवाद का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी* ने आमजनों से प्राप्त आवेदनों की सुनवाई की तथा कई मामलों का मौके पर ही समाधान किया।

लोक संवाद के माध्यम से प्राप्त शेष मामलों को आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित विभागों को भेजा गया, ताकि उनका शीघ्र एवं प्रभावी निष्पादन सुनिश्चित किया जा सके।

डी.बी. पब्लिकेशन्स प्रा. लि. के लिए जोड़ाफाटक रोड, धनबाद से राजेन्द्र कुमार अग्रवाल द्वारा मुद्रित एवं अंजना अग्रवाल द्वारा प्रकाशित. संपादक - गणेश मिश्रा. फोन - 9431726337
e-mail : biharobserver@gmail.com RNI No- 58991/95. * पी.आर.बी. एक्ट के तहत समाचार चयन एवं प्रकाशन के लिए गणेश मिश्रा जिम्मेवार होंगे एवं समस्त विवाद धनबाद न्यायालय के अधीन होंगे

जनता दरबार में आमजनों की समस्याओं से अवगत हुए डीसी

धनबाद (ससे) : उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन द्वारा कार्यालय कक्ष में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने जिले के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की समस्याओं को सुना एवं आश्वासन दिया कि उनके सभी शिकायतों का जल्द से जल्द जाँच कराते हुए उचित समाधान कराया जाएगा। जनता दरबार में भूमि मापी करने, गैराबद सरकारी भूमि को अवैध कैंजे से मुक्त कराने, तालाब को अतिक्रमण मुक्त करने, जलापूर्ति उपलब्ध कराने, आवागमन हेतु सड़क से अवैध कब्जा हटाने, पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देने, बेलगड़िया में आवास उपलब्ध कराने, पर्यटन स्थल को विकसित करने, पैतृक संपत्ति के बंटवारे, सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में नामांकन करने, अनुकंपा पर नियोजन करने, दिव्यांग हेतु सरकारी योजनाओं का लाभ देने समेत पारिवारिक मामले, जमीन के मामले, धोखाधड़ी के मामले एवं कई अन्य आवेदन प्राप्त हुईं।

उपायुक्त ने कहा कि जनता की समस्याओं का समय पर समाधान करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अधिकारी केवल आवेदनों को लंबित न रखें, बल्कि धरातल पर जाकर उनका त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करें। कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

श्रवण बाधित छात्रा को उपलब्ध कराई गई हियरिंग ऐड मशीन

धनबाद (कासं) : धनबाद जिला प्रशासन आमजनों की समस्याओं के त्वरित एवं संवेदनशील समाधान के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। इसी क्रम में आयोजित उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन के जनता दरबार में एक दिव्यांग छात्रा की सहायता के लिए मानवीय पहल करते हुए उसे तत्काल डिजिटल हियरिंग ऐड (कान की मशीन) उपलब्ध कराई गई। धनसार के चाँदमारी निवासी सुधीर कुमार विश्वकर्मा ने जनता दरबार में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन को आवेदन देकर बताया कि उनकी १७ वर्षीय पुत्री समृद्धि कुमारी बचपन से ही श्रवण बाधित है। तमाम कठिनाइयों के बावजूद वह वर्तमान में आठवीं कक्षा में अध्ययनरत है।

उन्होंने बताया कि क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज (सीएमसी), वेलोर में चिकित्सकीय जांच के उपरांत डॉक्टरों ने समृद्धि के लिए डिजिटल हियरिंग ऐड लगाने की सलाह दी थी। लेकिन दैनिक मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करने वाले श्री विश्वकर्मा की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वे उक्त मशीन खरीद सकें। आर्थिक तंगी के कारण उनकी पुत्री को पढ़ाई एवं दैनिक जीवन में कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए उपायुक्त आदित्य रंजन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए

जिला समाज कल्याण पदाधिकारी स्नेह कश्यप को आवश्यक निर्देश दिए। आवेदन प्राप्त होने के उपरांत सभी आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा कर तत्काल छात्रा के लिए डिजिटल हियरिंग ऐड मशीन उपलब्ध करा दी गई।

मशीन प्राप्त होने के बाद समृद्धि कुमारी एवं उनके पिता ने जिला प्रशासन और उपायुक्त के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस सहायता से समृद्धि को सुनने में काफी सहूलियत होगी तथा उसकी पढ़ाई और दैनिक गतिविधियों में आने वाली बाधाएं दूर होंगी। उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन जरूरतमंद एवं दिव्यांगजनों की सहायता के लिए प्रतिबद्ध है तथा जनता दरबार के माध्यम से प्राप्त होने वाले मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन सुनिश्चित किया जा रहा है।

ग्रामीण भाजपा ने किया प्रगति पथ यात्रा कार्यक्रम का आयोजन

गोविंदपुर (ससे) : धनबाद जिला ग्रामीण भाजपा ने गोविंदपुर में जिला अध्यक्ष मोहन कुंभकार की अध्यक्षता में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के १२ वर्षों के सफल कार्यकाल के उपलक्ष्य में 'प्रगति पथ यात्रा' कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें मुख्य अतिथि सांसद ढुलू महतो ने गोविंदपुर में एलिवेटेड रोड निर्माण का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि एलिवेटेड रोड मोदी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे केवल धनबाद जिला ही नहीं बल्कि जीटी रोड कर गुजरने वाले सभी लोगों को लाभ होगा। भाजपा नेत्री तारा देवी, धरनीधर मंडल, बलदेव महतो, ओमप्रकाश बजाज, बलराम साव, जग्गू साव, इंद्रजीत मंडल आदि शामिल थे।

बीडीओ ने शिक्षकों के साथ किया बैठक

बलियापुर (ससे) : डांगेपाड़ा में विभिन्न सरकारी स्कूलों के प्रधान अध्यापकों की बैठक बीडीओ प्रभाष चंद्र दास की अध्यक्षता में हुई। बैठक में दिव्यांग बच्चों का नामांकन हर हाल में स्कूलों में कराने की जरूरत बताया। दिव्यांग बच्चों का नामांकन के साथसाथ वैसे बच्चों का नियमित उपस्थिति भी सुनिश्चित करने को कहा गया। बैठक में इसके अलावा शिशु गणना के मुताबिक सभी बच्चों का नामांकन हुआ या नहीं इसका भी पालन करने की जरूरत बताया।

बैठक में बच्चों को एनीमिया की गोली खिलाने तथा गुणवत्तापूर्ण मध्यान भोजन, शौचालय की साफसफाई तथा बच्चों के पीने के लिए हमेशा घड़ा में पानी उपलब्ध कराने की जरूरत बतायां बैठक में सभी स्कूलों के प्रधान शिक्षक उपस्थित थे। दूसरी ओर प्रखंड कार्यालय में बीडीओ प्रभाष चंद्र दास की पुण्यतिथि में समीक्षा बैठक हुई। जिसमें मनरेगा, आवास समेत अन्य विषयों पर चर्चा की गयी।

मारवाड़ी महिला सम्मेलन ने विद्यालय में लगाया वाटर कूलर

गोविंदपुर (ससे) : मारवाड़ी महिला सम्मेलन की गोविंदपुर

शाखा ने प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय गोविंदपुर में वाटर कूलर लगाया। महिलाओं ने वाटर कूलर का उद्घाटन समारोह पूर्वक किया। अध्यक्ष निर्मला अग्रवाल ने कहा कि इस विद्यालय की करीब ७०० बालिकाओं को शीतल पेयजल उपलब्ध कराने के लिए वाटर कूलर लगाया गया है।

समिति इस तरह आगे भी रचनात्मक कार्य करती रहेगी। प्रधानाध्यापक अशोक श्रीवास्तव ने महिलाओं का स्वागत किया और वाटर कूलर के लिए आभार प्रकट किया। मौके पर सचिव सीमा अग्रवाल, कोषाध्यक्ष मीनू अग्रवाल, राष्ट्रीय प्रमुख रेणु दुदानी, सरोज सरिया, सुनीता बंसल, प्रभा सरिया, मीणा बंसल, वर्षा अग्रवाल, रागिनी शर्मा आदि मौजूद थी। पुरुषोत्तम मास की समाप्ति के अवसर पर महिलाओं ने अग्रसेन भवन में ५१ पंडितों को भोजन कराया और उन्हें उपहार प्रदान किया।

थाना प्रभारी ने लाइसेंसधारियों के साथ की बैठक

कतरास (ससे) : मुहर्रम पर्व के मद्देनजर कतरास थाना परिसर में थानेदार प्रवीण कुमार ने अखाड़ा कमिटी के लाइसेंसधारियों के साथ बैठक की। बैठक में सभी १२ लाइसेंसी और २ ग़ैरलाइसेंसी मुहर्रम अखाड़ा कमिटी के सदस्य उपस्थित थे। बैठक में सभी अखाड़ों का पंचमी से दशमी तक होने वाले कार्यक्रमों एवं जुलूस रुट की जानकारी ली गयी। पुलिस ने प्रत्येक अखाड़ा कमिटी के सदस्यों की उपस्थिति में जुलूस रूट के सत्यापन का कार्य प्रारंभ किया गया। सभी लाइसेंसधारियों को मुहर्रम को शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर आवश्यक दिशानिर्देश दिया गया।

बैंक कर्मचारी ने की आत्महत्या

धनसार (ससे) : धनसार थाना क्षेत्र के अनुग्रह नगर में एक ३५ वर्षीय बैंक कर्मचारी कुंदन सिंह ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जैसे ही जानकारी मिली, धनसार पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को कैंजे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए धनबाद भेजा। प्रारंभिक जांच में पुलिस ने बताया कि कुंदन सिंह अकेले रहते थे और स्थानीय बैंक में कार्यरत थे। पुलिस के अनुसार, उन्होंने अपने घर के अंदर ही आत्महत्या की। घटना से परिवार में अराजकता फैल गई है और अभी तक आत्महत्या का सही कारण स्पष्ट नहीं है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि कुंदन काफी समय से अकेले रह रहे थे। उनकी मौत ने इलाके में शोक की लहर पैदा कर दी है। पुलिस शव को परीक्षण रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई करेगी। घटना की सूचना मिलने पर उनके परिजन भी मौके पर पहुंचे, लेकिन देर शाम होने के कारण पोस्टमार्टम नहीं किया जा सका। शव को परिजनों को पोस्टमार्टम करने के बाद सौंपा जाएगा।

ड्रंक एंड ड्राइव के विरुद्ध चला अभियान, 8 वाहन जब्त

धनबाद (कासं) : सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने तथा यातायात नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार के निर्देशानुसार देर रात जिले में ड्रंक एंड ड्राइव के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया गया। अभियान का संचालन सीएमआरआई गेट के समीप ट्रैफिक डीएसपी रोहित कुमार साव के नेतृत्व में किया गया। इस दौरान ट्रैफिक थाना प्रभारी जय प्रकाश समेत ट्रैफिक पुलिस के अन्य पदाधिकारी एवं जवान बड़ी संख्या में मौजूद रहे। अभियान के तहत देर रात तक वाहनों की सघन जांच की गई। पुलिस टीम ने चारपहिया एवं दोपहिया वाहनों को रोककर उनके दस्तावेजों की जांच की तथा वाहन चालकों की ब्रेथ एनालाइजर मशीन के माध्यम से जांच की। इस दौरान लगभग ४१२ से अधिक वाहन चालकों की जांच की गई।

प्राथमिक विद्यालय भवन जर्जर

बलियापुर (ससे) : प्रखंड के प्रधानखंटा पंचायत के प्राथमिक विद्यालय सूडी.कुल्ही जहां प्रथम क्लास से पांचवी तक की पढ़ाई होती है। काफी छोटेछोटे बच्चे वहां पढ़ाई करते हैं। बात करें तो बिल्डिंग की तो एक ही बिल्डिंग है जो काफी जर्जर अवस्था में है। बिल्डिंग जर्जर होने के कारण प्रथम क्लास से पांचवी तक की पढ़ाई एक ही रूम में पढ़ाया जाता है। वह रूम भी जर्जर अवस्था में है कब गिर जाएगा। कोई ठीक नहीं अध्यापकों का कहना है कि हर दिन प्रार्थना करके निकलते हैं कि आज का दिन सही से पठनपाठन का कार्य हो कुछ अनहोनी ना हो जाए हर समय डर सताता है। वहां के लोगों का कहना है कि इस जर्जर बिल्डिंग के कारण कई अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं। प्रधान अध्यापकों का कहना है कि कई बार इसको लेकर लिखित शिकायत दे चुके हैं लेकिन विभाग से कोई आश्वासन व कार्य नहीं हुआ है। जहां मिड डे मील की खाना बनते हैं वह चक्रवर्ती ने कहा इसको लेकर कई बार लिखित एवं मौखिक शिकायत किया गया लेकिन अभी तक कोई भी पहल नहीं हो रही है। बच्चों में एक डर सा समाया हुआ है। सांसद एवं विधायक से आग्रह है कि स्कूल को जल्द से जल्द नए भवन में तब्दील किया

भवन भी काफी जर्जर है। वहीं भाजपा पूर्वी मंडल अध्यक्ष विद्युत जाए ताकि बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे।

डीडीसी ने की स्वास्थ्य संस्थानों के बजट व व्यय की समीक्षा

धनबाद (कासं) : उप विकास आयुक्त सन्नी राज की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में स्वास्थ्य विभाग से संबंधित बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला अंतर्गत संचालित जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं स्वास्थ्य उपकेंद्र के कार्यों, उपलब्ध बजट तथा व्यय की समीक्षा की गई। बैठक में स्वास्थ्य संस्थानों को आवंटित राशि के उपयोग, विभिन्न मदों में हुए व्यय तथा लंबित व्यय विवरणियों पर विस्तार से चर्चा की गई। डीडीसी ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को बजट का समुचित एवं समयबद्ध उपयोग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने व्यय से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने तथा वित्तीय प्रबंधन में पारदर्शिता बनाए रखने पर बल दिया। बैठक में ममता वाहन सेवा के संचालन को लेकर भी चर्चा की गई। डीडीसी ने कहा कि ममता वाहन के संचालन हेतु इच्छुक व्यक्ति, संस्था अथवा वाहन संचालक संबंधित क्षेत्र के चिकित्सा पदाधिकारी प्रभारी से संपर्क कर आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने सभी को ममता वाहन सेवा के सुचारू संचालन एवं अधिक से अधिक इच्छुक संचालकों को जोड़ने हेतु आवश्यक पहल करने का निर्देश दिया। बैठक में सिविल सर्जन-सहमुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम प्रबंधक सहित स्वास्थ्य विभाग के अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। डीडीसी ने सभी स्वास्थ्य संस्थानों से प्राप्त व्यय विवरणियों की समीक्षा कर आवश्यक दिशानिर्देश दिए तथा लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा।

108 चिन्हित बच्चों में से 98 का सफल उपचार

धनबाद (कासं) : उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन के निर्देशानुसार राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत जिले में जन्मजात विकृतियों से प्रभावित बच्चों की पहचान एवं उपचार का कार्य निरंतर किया जा रहा है। कार्यक्रम के तहत कुल १०८ बच्चों को विभिन्न जन्मजात विकृतियों से प्रभावित चिन्हित किया गया। इनमें से ९८ बच्चों का सफलतापूर्वक उपचार कराया जा चुका है। उपचार प्राप्त बच्चों में ६८ बच्चे जन्मजात हृदय रोग, १२ बच्चे कटे होंठ एवं तालु तथा १८ बच्चे क्लब फुट से प्रभावित थे। स्वास्थ्य विभाग द्वारा बताया गया कि शेष १० बच्चे फॉलोअप श्रेणी में हैं तथा उनके उपचार एवं स्वास्थ्य स्थिति की नियमित निगरानी की जा रही है। बच्चों की गंभीर स्थिति और विशेषज्ञ चिकित्सा की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, स्वास्थ्य विभाग द्वारा उन्हें देश के नामचीन चिकित्सा संस्थानों से संबद्ध कर पूर्णतः निःशुल्क चिकित्सा सहायता प्रदान की गई। जिला प्रशासन की प्राथमिकता है कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों में जन्मजात विकृतियों की समय पर पहचान कर उनका निःशुल्क एवं गुणवत्तापूर्ण उपचार सुनिश्चित किया जा रहा है, जिससे बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य एवं जीवन की नई दिशा मिल रही है। इस अभियान की सफलता से न केवल बच्चों को नया जीवन मिला है, बल्कि उनके परिवारों को भी भारी मानसिक और आर्थिक राहत पहुंची है।

अनियंत्रित ट्रक बिजली पोल से टकराया, आपूर्ति ठप

धनबाद (कासं) : भूली क्षेत्र में बीती रात एक तेज रफ्तार पोल्ट्री फार्म की ७०९ ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे बिजली के खंभे से जा टकराई। हादसा इतना जोरदार था कि बिजली का पोल बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और ट्रक

का अगला हिस्सा भी टूट गया। राहत की बात यह रही कि घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। ट्रक चालक ने बताया कि चलती गाड़ी का एक्सेल बॉल ज्वॉइंट अचानक टूट जाने के कारण वाहन से उसका नियंत्रण हट गया। इसके बाद ट्रक सीधे बिजली के पोल से जा भिड़ी। टक्कर के प्रभाव से पोल पूरी तरह मुड़ गया और बिजली के तार भी टूटकर नीचे गिर गए। हादसे के कारण बिजली आपूर्ति व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। पोल और तार क्षतिग्रस्त होने से बीती रात से ही भूली के कई इलाकों में बिजली आपूर्ति ठप हो गई है। भीषण गर्मी के बीच बिजली नहीं रहने से स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने भूली थाना और बिजली विभाग को अवगत कराया। मौके पर पहुंचे बिजली विभाग के फोरमैन विनोद कुमार ने बताया कि पोल और बिजली के तार गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिसके कारण पूरे क्षेत्र की सप्लाई बाधित हुई है। उन्होंने कहा कि विभाग की टीम युद्धस्तर पर मरम्मत कार्य में जुटी हुई है। क्षतिग्रस्त पोल को बदलने और बिजली लाइन को दुरुस्त करने का कार्य जारी है तथा जल्द से जल्द विद्युत आपूर्ति बहाल करने का प्रयास किया जा रहा है।

फिलहाल घटनास्थल पर मरम्मत कार्य जारी है और विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने तथा टूटे हुए तारों से दूर रहने की अपील की है।

झारखंड राज्य बास्केटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ

गोविंदपुर (ससे) : झारखंड बास्केटबॉल संघ के तत्वावधान में एवं धनबाद जिला बास्केटबॉल संघ द्वारा आयोजित २६वीं यूथ झारखंड राज्य बास्केटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ के. के. ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन्स, नीरो, गोविंदपुर में भव्य समारोह के साथ हुआ। उद्घाटन समारोह की शुरुआत राज्य के विभिन्न जिलों से आए बालक एवं बालिका खिलाड़ियों के आकर्षक मार्च पास्ट से हुई। इसके पश्चात मुख्य अतिथि जमशेदपुर पूर्व के विधायक एवं झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री सरयू राय सहित अन्य अतिथियों ने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर प्रतियोगिता का विधिवत उद्घाटन किया।

धनबाद जिला बास्केटबॉल संघ की अध्यक्ष डॉ. साधना कुमारी ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए पुष्पगुच्छ एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। अपने स्वागत भाषण में

उन्होंने खिलाड़ियों को खेल भावना, अनुशासन एवं समर्पण के साथ प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर झारखंड बास्केटबॉल संघ के सचिव एवं अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल कोच जे. पी. सिंह ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि ऐसी प्रतियोगिताएँ युवा खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा निखारने एवं राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचने का अवसर प्रदान करती हैं। उन्होंने खिलाड़ियों से कड़ी मेहनत एवं अनुशासन के साथ अपने खेल को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। मुख्य अतिथि सरयू राय ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि झारखंड प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की धरती है।

उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों में से भविष्य का कोई खिलाड़ी भारतीय बास्केटबॉल टीम का प्रतिनिधित्व करेगा और देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करेगा। उन्होंने खेलों को युवाओं के सर्वांगीण विकास का महत्वपूर्ण माध्यम बताया। कार्यक्रम के दौरान क्रेसेंट इंटरनेशनल स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम ने उपस्थित दर्शकों एवं अतिथियों का मन मोह लिया। खिलाड़ियों एवं खेल प्रेमियों ने प्रस्तुति की भूरिभूरि प्रशंसा की।

इस अवसर पर झारखंड बास्केटबॉल संघ के अध्यक्ष ओलंपियन हरभजन सिंह, पूर्व बियाडा अध्यक्ष विजय झा, डॉ. शिवानी झा, डॉ. नेहा प्रियदर्शिनी, उदय कांत तिवारी, जुबैर आलम सहित अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित थे।

गुरुग्राम में 13 बांग्लादेशी गिरफ्तार

गुरुग्राम(ईएमएस): राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए अवैध घुसपैठियों के विरुद्ध गुरुग्राम पुलिस का अभियान लगातार जारी है। अपराध शाखा टीमों ने ८०० से अधिक संदिग्धों के दस्तावेज चेक किए। इस दौरान १३ बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। सभी बांग्लादेश बॉर्डर से अवैध रूप से भारत में घुसे और अब गुरुग्राम में रह रहे थे। पुलिस अब इन सभी को डिपोर्ट कराएगी।

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINNER BUILDING CONSTRUCTION DEPARTMENT BUILDING DIVISION, JAMTARA

3rd call Notice Inviting e-quotation No-03/2026-27

e-Quotations are invited for preparation of the estimate related to the **Construction of Weigh Bridge and Operator Room Block Campus 1500MT Grain Godown in Block- Narayanpur, District-Jamtara** Suppliers, Retailers, Distributers and Others for following items mentioned below. Details of relevant items are available on the e-Tender Portal. The quotationer may download the document from the website and quote their rate (Inclusive of all types of taxes, G.S.T, Contractor's profit, Over head charges, Labour Cess and Royalty) online from 06.07.2026 at 11:00 A.M. to 13.07.2026 at 11:00 A.M. and the e-Quotation will be opened on to 14.07.2026 at 12:00 Noon.

Sl. No.	Description of Items	Unit	Quoted Rate	
			In Figure	In Words
1	e- Quotation for Construction of Weigh Bridge and Operator Room Block Campus 1500MT Grain Godown in Block - Narayanpur, District - Jamtara for the year 2026-2027. Sl. No. 01 only.	1.00 Each		

Note: - List of Items can be seen on the website www.jharkhandtenders.gov.in and may contact to the Office of The Executive Engineer, Building Division, Jamtara.

Terms and Conditions:-

1. The rate quoted by quotationer shall be firm and final.
2. The quotationer shall furnish GST registration number and his PAN.
3. The undersigned reserves the right to accept/reject/cancel any or all quotations without assigning any reason thereof.
4. For any query or clarification you may contact The Executive Engineer/Estimating Officer, Building Division, Jamtara @ 9431369703/8969157568 respectively.

Executive Engineer,
Building Division, Jamtara

PR 382444 Building(26-27)D

कार्यालय नगर निगम गिरिडीह

ई0निविदा आमंत्रण सूचना

1. विज्ञापनदाता का नाम :– उप नगर आयुक्त, गिरिडीह नगर निगम।
2. वेबसाईट पर निविदा अपलोड करने की तिथि एवं समय :– दिनांक 22.06.2026 को पू0 11:00 बजे से।
3. वेबसाईट पर निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि एवं समय :– दिनांक 13.07.2026 को अ0 02:00 बजे तक।
4. निविदा खोलने की तिथि एवं समय :– दिनांक 14.07.2026 को अ0 03:00 बजे गिरिडीह नगर निगम।
5. निविदा आपलोड करने का वेबसाईट :– **www.Jharkhandtenders.gov.in**
6. कार्य की विरणी :–

निविदा सं0	योजना का नाम	परिमाण विपत्र की राशि	अग्रधन की राशि 2 प्रतिशत	परिमाण विपत्र का मूल्य	कार्य समाप्ति अवधि
1	2	3	4	5	6
UDD/GMC/XI/01/2026-27	वार्ड नं0 09 में भण्डारीडीह मेन रोड से अमीत बरदियार छठ घाट तक अवस्थित नाली में स्लैब निर्माण कार्य।	1886600	37732	5000	60 दिन
UDD/GMC/XI/02/2026-27	वार्ड नं0 01, 02, 04, 05, 07, 08, 10, 11, 12 एवं 18 में विभिन्न स्थानों में अवस्थित नाली में स्लैब निर्माण।	2351800	47036	5000	60 दिन
UDD/GMC/XI/03/2026-27	वार्ड नं0 03, 13, 14 ,15 16 ,17, 19, 20, 21, 22, 23 एवं 24 में विभिन्न स्थानों में अवस्थित नाली में स्लैब निर्माण।	2499800	49996	5000	60 दिन
UDD/GMC/XI/04/2026-27	वार्ड नं0 29, 33 एवं 34 में विभिन्न स्थानों में अवस्थित नाली में स्लैब निर्माण।	2485000	49700	5000	60 दिन
UDD/GMC/XI/05/2026-27	वार्ड नं0 30, 31 एवं 32 में विभिन्न स्थानों में अवस्थित नाली में स्लैब निर्माण।	2498400	49968	5000	60 दिन
UDD/GMC/XI/06/2026-27	वार्ड नं0 15 में बरमसीया पार्क से शमशान घाट तक पी0सी0सी0 निर्माण।	2334143	46683	5000	90 दिन
UDD/GMC/XI/07/2026-27	वार्ड नं0 15 में सवेरा सिनेमा हॉल से शमशान घाट तक नाली निर्माण।	4084789	81,696	10000	90 दिन

(नोटः– केवल ई–निविदा स्वीकृत होगा। अन्य सूचनाएँ वेवसाईट http:WWW.Jharkhandtenders.gov.in/ नगर निगम गिरिडीह के सूचना पट पर देखा जा सकता है।)

उप नगर आयुक्त,
गिरिडीह नगर निगम।

PR.NO.382451 Urban Development(26-27):D

झारखण्ड सरकार
कार्यपालक अभियंता का कार्यालय ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, धनबाद

मोबाईल नं0 : 7061981397 Email : rdsd.dhanbad@rediffmail.com

पत्रांकः– 595 **अति अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना** धनबाद/दिनांक– 16.06.2026

ई0– निविदा सूचना संख्या – **13/2026-27/RDSD/EE/Dhanbad**

1.कार्य की विस्तृत विवरणीः–

क्र0 सं०	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (लाख में)	अग्रधन की राशि	परिमाण विपत्र का मूल्य	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1.	धनबाद जिलान्तर्गत कलियासोल प्रखण्ड के मौजा कलियासोल में प्रखण्ड स्तरीय स्टेडियम निर्माण।	260.08400	परिमाण विपत्र की राशि 2%	10000.00	15 महीना

2. वेबसाइट में निविदा प्रकाशन की तिथि –22.06.2026
3. ई–निविदा प्राप्ति की तिथि एवं समय–दिनांक 22.06.2026 से दिनांक 29.06.2026 को अपराह्न 5:00 बजे तक।
4. ई–निविदा खोलने का स्थान – कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, धनबाद।
5. ई–निविदा खोलने की तिथि एवं समय– 01.07.2026 अपराह्न 2:00 बजे
6. ई–निविदा आमंत्रित करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं पता :– ई0 बेनीलाल मंराडी, कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, धनबाद।
7. ई–निविदा प्रकोष्ठ का दूरभाष सं० – 7061981397 (संबंधित कार्यपालक अभियंता का दूरभाष नम्बर)
8. **Office Help Line No. 9835146652**
9. परिमाण विपत्र की राशि घट–बढ़ सकती है तदनुसार अग्रघन की राशि देय होगी।
10. जिस संवेदक का इस प्रमंडल में पूर्व से आवंटित कोई कार्य लंबित है अथवा उनका कार्यान्वयन संतोषजनक नहीं रहा है, उन्हें कार्य आवंटन पर विचार नहीं किया जायेगा।
11. निविदा शुल्क एवं अग्रधन की राशि केवल **Online Mode** द्वारा स्वीकार्य होगी।
12. निविदा शुल्क एवं अग्रधन की राशि का ई–भुगतान जिस खाता से किया जायेगा, उसी खाते में अग्रधन की राशि वापस होगी। अगर खाता को बंद कर दिया जाता है तो सारी जबावदेही आपकी होगी।

विस्तृत जानकारी के लिये वेबसाईट www.jharkhandtenders.gov.in एवं कार्यालय की सूचना पट्ट पर देखा जा सकता है।

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल,धनबाद

PR 382524 (REO)26-27*D

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)
कार्यालयः जिला पशुपालन पदाधिकारी, बोकारो

ई–मेल– ahdbkr@gmail.com

–ः पशुपालकों के लिए आवश्यक सूचना ः–

सरकार के सचिव कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग) झारखण्ड, राँची के राज्यादेश संख्या 09रा0 (विभाग) दिनांक 08.06.2026 के आलोक में वितीय वर्ष 2026–27 के तहत् मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजनान्तर्गत ग्रामीण स्तर पर युवाओं/ युवतियों को स्वानियोजित करने तथा राज्य में दुध, ऊन, मांस एवं अण्डा के उत्पादन में वृद्धि लाकर आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से अनुदानित / लाभुक अंशदान (स्वयं या बैंक ऋण) पर संचालन हेतु पशुपालन प्रक्षेत्र की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित होंने हेतु इच्छुक पशुपालक विहित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किया जाता है।

योजना का विवरण निम्नवत् हैः–

क्र0 सं0	योजना का नाम	योजना का लागत राशि	भौतिक लक्ष्य (मदवार)		कुल योग
			75% अनुदान पर	90% अनुदान पर	
1	2	3	4	5	6
01	बकरा विकास योजना (08+02)	49600/-	433	256	689
02	सूकर विकास योजना (04+01)	57800/-	108	63	171
03	बैकयार्ड लेयर कुक्कुट (400 लो इनपुट लेयर कुक्कुट)	118200/-	103	61	164
04	ब्रायलर कुक्कुट पालन योजना (500 ब्रायलर रेयरिंग युनिट)	67500/-	187	110	297
05	बत्तख चूजा वितरण की योजना (15 दिवसीय 30 चूजा)	3400/-	742	439	1181
06	भेंड़ पालन योजना (08+02)	49600/-	75	43	118

लाभुकों का चयन हेतु अर्हता एवं प्रक्रियाः–

- पशुपालक झारखण्ड राज्य के बोकारो जिला का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है।
- ग्रामीण क्षेत्र के इच्छुक लाभुकों को योजना का लाभ ग्राम सभा के द्वारा सुयोग्य लाभुकों का चयनोपरांत योजना का नियमानुसार लाभ दिया जायेगा।
- पंचायत / ग्राम सभा से सृजित लाभुकों के आवेदन पर प्रखण्ड स्तरीय अनुमोदन समिति के अनुशंसा उपरांत अंतिम स्तर पर जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा अनुमोदित प्राप्त किया जाएगा।
- 75% अनुदान की योजना का लाभ जिसे के सभी वर्ग पशुपालकों को प्राथमिकता के आधार पर लाभ नियमानुसार दिया जायेगा।
- 90% अनुदान की योजना का लाभ अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति/असहाय विधवा औरत/दिव्यांग/निःसंतान दम्पत्ति जिनका उम्र कम से कम 50 वर्ष हो को लाभ दिया जाएगा।
- सूकर विकास योजना / बैक्यार्ड लेयर कुक्कुट (लो इनपुट लेयर कुक्कुट पालन)/ ब्रायलर कुक्कुट पालन (500 ब्रायलर रेयरिंग युनिट) के योजना के लाभुकों का गृह निर्माण मनरेगा अभिसरण के तहत् किया जायेगा।
- चयनित गाँव के लाभुक स्थानीय निवासी हो तथा चयनित लाभुक द्वारा इस संबंध में आवासीय प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र (जहाँ लागु हो) जमा करना अनिवार्य है।
- बत्तख चूजा वितरण की योजना से लाभान्वित लाभुकों को भी मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजनान्तर्गत अन्य योजनाएँ (यथा– बकरा विकास, सूकर विकास, बैक्यार्ड/लो इनपुट लेयर कुक्कुट पालन की योजना, ब्रायलर कुक्कुट पालन इकाई की योजना एवं भेंड़ पालन योजना) के लिये योग्य माने जायेंगे। जबकि बकरा विकास, सूकर विकास, बैक्यार्ड/लो इनपुट लेयर कुक्कुट पालन की योजना, ब्रायलर कुक्कुट पालन तथा भेंड़ पालन योजना की इकाई में से किसी भी योजना का लाभ मिलने पर लाभुक अन्य योजनाओं के लिये योग्य नहीं होंगे।
- विगत पांच वर्षो में जिन परिवारों (JSFSS/NFHS अंतर्गत परिभाशित) द्वारा अनुदान का लाभ लिया गया है, उन्हें पुनः अनुदान अनुमान्य नहीं होगा।
- सभी योजनाओं का संचालन हेतु लाभुकों का Escrow Account/Dedicated bank account खोला जायेगा एवं अनुदान राशि संबंधित बैंक के Escrow Account/Dedicated Account में सरकारी अनुदान की राशि DBT के माध्यम से स्थनांतरित किया जायेगा। पंचायत स्तरीय समिति/ग्राम सभा के द्वारा लाभुक अंशदान राशि अंतिम रुप से चयनित लाभुकों को 01 माह के अन्दर में Escrow Account/Dedicated bank account में जमा करना अनिवार्य होगा, तद्पश्चात लाभुकों को पशुओं के क्रय/प्राप्त करने की अर्हता प्राप्त होगी। पशु–पक्षी इत्यादि के आपूर्ति के उपरांत सरकारी अनुदान एवं लाभुक अंशदान की राशि एक मुश्त आपूर्तिकर्त्ता के बैंक खाता में हस्तांतरित की जायेगी।
- आवेदन की अंतिम तिथि प्रखण्ड स्तरीय समिति द्वारा पूर्ण आवेदन ग्राम सभा के अनुमोदन के साथ जिला स्तरीय समिति को दिनांक 20.07.2026 तक भेजना अनिवार्य है।
- उपरोक्त योजनाओं के आवेदन करने हेतु आवेदन प्रपत्र संबंधित प्रखण्ड पशुपालन पदाधिकारी/भ्रमणशील पशुचिकित्सा पदाधिकारी से प्राप्त करेंगे।

निवेदक :–
जिला पशुपालन पदाधिकारी, बोकारो

PR 382509 Animal Husbandry(26-27)#D

अल नीनो सक्रिय होने से मानसून पड़ा कमजोर, अब तक 25 फीसदी बारिश कम

नई दिल्ली,(ईएमएस): प्रशांत महासागर में अल नीनो सक्रिय हो गया है। इस बीच मॉनसून की शुरूआत अच्छी नहीं रही। मॉनसून आगे तो बढ़ रहा है, लेकिन चाल धीमी है। जून के पंद्रह दिन बीत जाने के बाद भी बारिश में २५ फीसदी की कमी है। आने वाले हफ्ते में यह कमी और ज्यादा बढ़ने की संभावना है। आईएमडी के मुताबिक मॉनसून कई दिनों बाद कुछ आगे बढ़ा है। इसने तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार के कुछ हिस्सों को कवर किया। वहीं मुंबई के लोगों को मॉनसून के लिए अभी इंतजार करना होगा। मुंबई में मॉनसून सामान्य तौर पर ११ जून को पहुंचता है।

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, बोकारो (जिला ग्रामीण विकास शाखा)

–:: मनरेगा संबंधित आम सूचना ::–

ग्रामीण विकास विभाग, झारखंड सरकार के संकल्प संख्या –4729 दिनांक 04.06.2007 के द्वारा निर्गत नियुक्ति सेवा शर्त एवं कर्तव्य नियमावली 2007 एवं संकल्प सं0– 6440 दिनांक 17.07.2012 के द्वारा निर्गत नियुक्ति, सेवा शर्त एवं कर्तव्य (संशोधन) नियमावली, 2012 तथा पत्रांक (N) 848 दिनांक 21.03.2017 के आलोक में मनरेगा अधिनियम, 2005 के अंतर्गत बोकारो जिला में संविदा आधारित रिक्त पदों पर नियुक्त एवं कार्यरत मनरेगा के कतिपय क्षेत्रीय कर्मी विगत् माह मार्च 2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। जिससे मनरेगा योजना के क्रियान्वयन में काफी कठिनाई उत्पन्न हो रही है, चूँकि मनरेगा योजना मॉग आधारित योजना है एवं ग्रामीणों द्वारा काम की मॉग के आधार पर 15 दिनों के अंदर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना होता है। ऐसी परिस्थिति में कर्मियों के हड़ताल पर रहने के कारण मनरेगा योजना के क्रियान्वयन एवं ग्रामीणों को ससमय रोजगार उपलब्ध कराने पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। मनरेगा क्षेत्रीय कर्मियों का योजना में मानव दिवस सृजन करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कर्मियों के हड़ताल में रहने के कारण बोकारो जिला में माह मार्च, अप्रैल एवं मई 2026 तक में निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध मात्र 32.3 प्रतिशत ही मानव दिवस का सृजन किया जा सका है।

ग्रामीण विकास विभाग, झारखंड, रॉची के पत्रांक (N) 623 दिनांक 29.05.2026 के आलोक में इस कार्यालय के ज्ञापांक 148/मनरेगा दिनांक 30.05.2026 द्वारा भी सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को हड़ताली कर्मियों को नोटिस निर्गत करने हेतु निदेश दिया गया है। उपरोक्त वर्णित परिस्थिति में मनरेगा योजना की महत्ता तथा ग्रामीणों को ससमय रोजगार उपलब्ध कराने के परिपेक्ष्य में बोकारो जिला के सभी मनरेगा अंतर्गत हड़ताल पर गये ग्राम रोजगार सेवकों/अतिरिक्त ग्राम रोजगार सेवकों को सूचित किया जाता है कि हड़ताल से सूचना प्रकाशन की तिथि से सात दिनों के अंदर सेवा में लौटते हुए संबंधित प्रखंड में योगदान देना सुनिश्चित करेंगे।

निर्धारित समय–सीमा के अंदर हड़ताली कर्मियों के सेवा में वापस नहीं आने की स्थिति में यह समझा जाएगा कि आप मनरेगा अधिनियम, 2005 के विरूद्ध कार्य कर रहे है एवं अपनी संविदा सेवा देने में इच्छुक नहीं है। अतः लोक कल्याण हित में संबंधित कर्मी के विरूद्ध संविदा सेवा को समाप्त करने हेतु नियम संगत कार्रवाई की जाएगी।

उपायुक्त,
–सह–जिला कार्यक्रम समन्वयक,बोकारो

PR 382490 (District)26-27*D

ई० प्रोक्यूरमेंट सेल
कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल धनबाद

अल्पकालीन ई–प्रोक्योरमेंट नोटिस

ई–टेन्डर रेफरेन्स नं0 03/2026–27/EE/BCD/DHANBAD

क्रमांक	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (रू० में)	अग्रधन की राशि (रू० में)	परिमाण विपत्र का मूल्य (रू० में)	कार्य समाप्ति की अवधि
1	Construction of Library Building at Pandarpala, Wasseypur, Dhanbad	1,17,20,100.00	2,34,500.00	10,000.00	08 माह।

1. वेबसाईट पर निविदा प्रकाशन की तिथि :–20.06.2026 03:00 बजे
2. वेबसाईट में निविदा डालने की अन्तिम तिथि/समय :–11.07.2026 03:00 बजे
3. निविदा प्रकाशित करने वाले कार्यालय का नाम एवं पताः–कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल, धनबाद।
4. निविदा खोलने की तिथि/समय एवं स्थान :–13.07.2026 03:30 बजे नोडल पदाधिकारी, ई0 प्रोक्यूरमेंट सेल, मुख्य अभियंता का कार्यालय, भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड, रॉची।
5. प्रोक्योरमेन्ट पदाधिकारी का सम्पर्क संख्या :–9973309316
6. ई–प्रोक्योरमेन्ट सेल का हेल्पलाईन संख्या :–7488650243
7. परिमाण विपत्र की राशि घट–बढ़ सकती है तद्नुसार अग्रधन की राशि देय होगी।
8. सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई–गवर्नेस विभाग, झारखण्ड सरकार के आदेश ज्ञापांक 120 दिनांक 03.10.2023 के द्वारा निर्गत SOP (मानक संचालन प्रक्रिया) एवं भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 2229 दिनांक 06.10.2023 के आलोक में निविदा शुल्क एवं अग्रधन की राशि केवल **Online Mode** द्वारा स्वीकार्य होगी।
9. निविदा शुल्क एवं अग्रधन की राशि का ई–भुगतान जिस खाता से किया जायेगा, **SOP** के तहत अग्रधन की राशि उसी खाते में वापसी होगी। अगर खाता को बंद कर दिया जाता है तो उसकी संपूर्ण जवाबदेही निविदादाता की होगी।

अन्य किसी भी प्रकार के बदलाव की सूचना **http://jharkhandterders.gov.पद** पर देखा जा सकता है।

Note :- UCAN Registration is mandatory for the Bidders

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल, धनबाद।

PR.NO.382533 Building(26-27):D

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINNER BUILDING CONSTRUCTION DEPARTMENT BUILDING DIVISION, JAMTARA

2nd Call Notice Inviting e-quotation No-02/2026-27

e-Quotations are invited for preparation of the estimate related to the **Elevator Supply, Installation & Commissioning including Civil Work for Lift at 12 Court Building, Jamtara.** Suppliers, Retailers, Distributers and Others for following items mentioned below. Details of relevant items are available on the e-Tender Portal. The quotationer may download the document from the website and quote their rate (Inclusive of all types of taxes, G.S.T, Contractor's profit, Over head charges, Labour Cess and Royalty) online from 06.07.2026 at 11:00 A.M. to 13.07.2026 at 11:00 A.M. and the e-Quotation will be opened on to 14.07.2026 at 12:00 Noon.

Sl. No.	Description of Items	Unit	Quoted Rate	
			In Figure	In Words
1.	e-Quotation for Elevator Supply, Installation & Commissioning including Civil Work for Lift at 12 Court Building, Jamtara Sl. No. 01 to 02 only.	2.00 Each		

Note: - List of Items can be seen on the website www.jharkhandtenders.gov.in and may contact to the Office of The Executive Engineer, Building Division, Jamtara.

Terms and Conditions:-

1. The rate quoted by quotationer shall be firm and final.
2. The quotationer shall furnish GST registration number and his PAN.
3. The undersigned reserves the right to accept/reject/cancel any or all quotations without assigning any reason thereof.
4. For any query or clarification you may contact The Executive Engineer/Estimating Officer, Building Division, Jamtara @ 9431369703/8969157568 respectively.

Executive Engineer,
Building Division, Jamtara

PR 382442 Building(26-27).D

कार्यालय नगर पंचायत, जामताड़ा

Email Id- Jamtaranagarpanchayat@gmail.com

!! आम–सूचना !!

नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची के अधिसूचना संख्या संचिका सं0–06/न0वि0(TCPO)/म0उ0वि0–05/2017–1315, दिनांक–27.04.2026 के आलोक में नगर पंचायत, जामताड़ा क्षेत्रान्तर्गत रहने वाले लोगों को निर्देश दिया जाता है कि वे इस पत्र के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर, जो भी भवन/वाणिज्यिक भवन इत्यादि दिनांक–31.12.2024 के पूर्व से निर्मित है, जो किसी कारणवशः बिना नक्शा पास कराये भवन का निर्माण करा लिए है वे अपने भवन/ वाणिज्यिक भवन इत्यादि के निर्माण को नियमितीकरण करवा लें। उसके उपरांत निरीक्षण के कम में बिना नक्शा या नियमितीकरण का कोई भवन पाया जाता है तो उसे अवैध निर्माण माना जायेगा तथा सरकार द्वारा विधिवत् क्षतिग्रस्त किया जा सकता है।

अनाधिकृति निर्माण पर लागू नियमितीकरण शुल्क या स्वीकृति योजना से आंशिक विचलन पर

क0	उपयोग	प्लॉट का क्षेत्रफल (वर्ग मी0में)	शुल्क दर कुल अतिक्रमण किए गए निर्मित क्षेत्र/ अनाधिकृत क्षेत्र (नगर पंचायत,जामताड़ा) पर
1	आवासीय	150 तक	रू0 40 प्रति वर्ग मी0
		150–300	रू0 60 प्रति वर्ग मी0
2	वाणिज्यिक	150 तक	रू0 80 प्रति वर्ग मी0
		150–300	रू0 120 प्रति वर्ग मी0

नोटः– नक्शा स्वीकृति हेतु नगर पंचायत, जामताड़ा के किसी भी **LTP** से सम्पर्क करें।

1. श्री राजकिशोर कुमार–7717760331
2. श्री इरशाद अंसारी–8709847652
3. श्री प्रियंक मंगलन–9199539199

PR 382445 Urban Development and Housing(26-27)D

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत,जामताड़ा

Government of Jharkhand
Urban Development & Housing Department
Chas Municipal Corporation, Chas

Short Notice Inviting Tender

Reference No. - UDD/CMC/06/2026-27

Group No.	Name of work	Tender Cost (Rs.)	Earnest Money(Rs.)	Cost of BOQ (Rs.)	Completion period
01	ANNUAL REPAIR AND MAINTENANCE OF DEPARTMENTAL 684 Nos. DRILLED TUBEWELLS IN DIFFERENT WARDS UNDER CHAS MUNICIPAL CORPORATION, CHAS	70,02,733.20	1,40,500.00	10,000.00	12 months
A	वेबसाईट पर निविदा प्रकाशन की तिथि	22/06/2026			
B	निविदा प्राप्ति (ऑन लाईन बिडिंग) की अंतिम तिथि एवं समय	29/06/2026 at 02:00 PM			
C	बिड खोलने की तिथि एवं समय	01/07/2026 at 03:00 PM			
D	निविदा आमंत्रित करने वाले पदाधिकारी का पदनाम	Additional Municipal Commissioner Chas Municipal Corporation, Chas.			

NOTE:

- Only e-Tenders will be accepted.
- Further details can be seen on website http:/jharkhandtenders.gov.in
- e-Procurement में Tender fee एवं EMD की राशि ऑनलाईन सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई–गवर्नेस विभाग, झारखण्ड राँची का आदेश ज्ञापांक 120 दिनांक 03.10.2023 एवं नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड राँची का पत्रांक 05/विविध (e-Tender) – 12/2023/न0वि0–4847 (अनु0) दिनांक 11.10.2023 के तहत ली जायेगी।

ह/0
अपर नगर आयुक्त
चास नगर निगम

PR 382446 Urban Development (26-27)_D

टीएमसी के बागी सांसदों का एनसीपीआई में विलयः काकोली घोष दस्तीदार बनीं अध्यक्ष

कोलकाता,(ईएमएस) : तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के २० बागी सांसदों ने दलबदल विरोधी कानून से बचने और अपनी राजनीतिक दिशा बदलने के लिए बड़ा मास्टरस्ट्रोक चला है। इन सांसदों ने नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया (एनसीपीआई) में विलय कर लिया है, जिसकी कमान अब टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी की कभी करीबी रहीं काकोली घोष दस्तीदार के हाथों में है। इस कदम के साथ ही यह गुट अब बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) में शामिल होने की तैयारी में है।

यह राजनीतिक तख्तापलट एक गोपनीय सहमति से हुआ है। काकोली घोष को एनसीपीआई का अध्यक्ष चुने जाने से दो दिन पहले पार्टी की तत्कालीन अध्यक्ष शेवली कुंडू ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। इसके बाद, ३० मई को चार बार की सांसद काकोली घोष को आधिकारिक तौर पर एनसीपीआई का नया अध्यक्ष चुना गया। इसके बाद इन २० बागी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर उन्हें अनजान पार्टी के साथ अपने विलय की आधिकारिक जानकारी दी, इसके बाद से घटनाक्रम राष्ट्रीय सुर्खियों में आ गया है। टीएमसी के भीतर इस उथल-पुथल की जड़ पार्टी के अघोषित उत्तराधिकारी अभिषेक बनर्जी को माना जा रहा है। बागी सांसदों का आरोप है कि अभिषेक का अहंकारी रवैया और पार्टी के आंतरिक ढांचे की लगातार अनदेखी ही बड़ी बगावत की मुख्य वजह बनी।

इस पूरे घटनाक्रम में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने परदे के पीछे से अहम भूमिका निभाई। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और वरिष्ठ सांसद निशिकांत दुबे जैसे नेताओं ने बागी गुट के साथ लगातार संपर्क बनाकर उनकी आगे की रणनीति तय करने में मदद की। यहाँ तक कि कई महत्वपूर्ण बैठकें केंद्रीय मंत्री यादव के आवास पर ही हुईं। इन सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष को दिए पत्र में खुद को बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए का हिस्सा बताकर सत्ताधारी गठबंधन में सीटें आवंटित करने की मांग की है।

बात दें कि नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया (एनसीपीआई) को जनवरी २०२३ में राजनीतिक दल के तौर पर मान्यता मिली थी। पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले से संचालित यह एक अनजान राजनीतिक दल है, जिसने २०२३ के त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में ४ उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें से एक को सबसे ज्यादा महज ५३६ वोट ही मिल सके थे। छह बार के सांसद और बागियों में सबसे वरिष्ठ सदस्य सुदीप बंद्योपाध्याय भी हाल ही में गुट में शामिल हुए हैं।

यदि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला विलय को मंजूरी देते हैं, तब यह भारतीय राजनीति में एक बड़ा उलटफेर होगा। कल तक संसद या किसी भी राज्य विधानसभा में एक भी सदस्य न रखने वाली एनसीपीआई रातों-रात लोकसभा की पाँचवीं सबसे बड़ी पार्टी और सत्ताधारी एनडीए का दूसरा सबसे बड़ा घटक दल बनेगी।

राज्य बार काउंसिलों में हो महिला प्रतिनिधित्व का 10 प्रतिशत को-ऑप्शन

नई दिल्ली(ईएमएस)। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया को राज्य बार काउंसिलों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के लिए १० फीसदी को-ऑप्शन वाले हिस्से के लिए एक एक समान, पारदर्शी और निष्पक्ष तरीका बनाने की मंज़ूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बीसीआई का सुझाव काफी निष्पक्ष लग रहा था। चीफ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने देखा कि ज्यादातर राज्य बार काउंसिलों के चुनाव या तो पूरे हो चुके थे या पूरे होने वाले थे।

अब कार्यवाही में बस एक ही मुद्दा बचा था कि को-ऑप्शन के जरिए महिलाओं के लिए तय की गई अतिरिक्त १० फीसदी सीटें कैसे भरी जाएं। सुनवाई के दौरान बीसीआई ने कोर्ट को बताया कि उसने को-ऑप्शन के नियम बना लिए हैं और वह उन्हें कोर्ट के सामने रखने को तैयार है। बेंच ने याद दिलाया कि उसके पहले के निर्देशों में महिला वकीलों के लिए ३० फीसदी प्रतिनिधित्व की बात कही गई थी, जिसमें २० फीसदी चुनाव के जरिए और १० फीसदी को-ऑप्शन के जरिए होना था। आखिरकार कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से वकील राधिका गौतम को अधिकार दिया कि वे राज्य बार काउंसिल के नवनिर्वाचित सदस्यों और अन्य संबंधित पक्षों से सलाह-मशविरा करने के बाद को-ऑप्शन (सह-चयन) के लिए एक समान प्रक्रिया तैयार करें।

मंगलवार की सुनवाई के दौरान, सीनियर एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा ने छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ी चिंताओं को उठाया। गोवा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि लगभग ४ हजार सदस्यों वाली बार होने के बावजूद, राज्य को अक्सर महाराष्ट्र और गोवा की बार काउंसिल में प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है। उन्होंने कहा कि दमन और दीव और कई पूर्वोत्तर राज्यों में भी इसी तरह की समस्याएं आती हैं। सीजेआई ने इस चिंता को माना और कहा कि ये वास्तविक मुद्दे हैं। जब अरोड़ा ने अनुरोध किया कि को-ऑप्शन की प्रक्रिया बनाते समय राज्य-विशेष के कारकों पर भी विचार किया जाए, तो बेंच ने संकेत दिया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ऐसे खास मुद्दों पर राज्य बार काउंसिलों से सलाह ले सकता है।

जनगणना के कारण चार राज्यों में समय से पहले हो सकते हैं चुनाव

नई दिल्ली,(ईएमएस): भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और गोवा जैसे चार महत्वपूर्ण राज्यों में २०२७ के विधानसभा चुनाव तय समय से पहले करने की संभावना पर काम कर रही है। ये चुनाव आमतौर पर फरवरी-मार्च २०२७ में होने हैं, लेकिन सूत्रों के अनुसार, जनगणना की प्रक्रिया के साथ संभावित टकराव और हालिया राजनीतिक घटनाक्रमों के चलते इन्हें पहले करने की तैयारी है। मणिपुर को हालांकि जातीय तनाव के कारण योजना से बाहर किया गया है।

समय से पहले चुनाव करने का मुख्य कारण जनगणना है, जो फरवरी-मार्च २०२७ में ही प्रस्तावित है। जनगणना और चुनाव दोनों प्रक्रियाओं में अधिकांशतः शिक्षक और सरकारी कर्मचारी शामिल होते हैं, जिससे लोगों की कमी हो सकती है। एक वरिष्ठ भाजपा पदाधिकारी ने बताया कि इस संभावना को देखकर संबंधित राज्यों से चर्चा हुई है। उत्तराखंड भाजपा दिसंबर में ही चुनाव कराने की पक्षधर है, ताकि कर्मचारियों पर दोहरा बोझ न पड़े और जनगणना कार्य के लिए उन्हें पर्याप्त समय मिल सके। राजनीतिक रूप से भाजपा पश्चिम बंगाल में मिली हालिया सफलता के मोमेंटम को भुनाना चाहती है। भाजपा के वरिष्ठ नेता के अनुसार, पार्टी कैडर का उत्साह बढ़ा हुआ है, और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड व गोवा में प्रो-इंकंबेंसी का माहौल है। उत्तर प्रदेश भाजपा का मानना है कि समय से पहले चुनाव उनके लिए फायदेमंद हो सकते हैं, जहां वे लगातार तीसरी बार सत्ता में आने की उम्मीद हैं। गोवा में भी भाजपा तीसरी बार सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार दिख रही है और कार्यकर्ताओं का मानना है कि इससे विपक्ष को पर्यावरण और जमीन से जुड़े मुद्दों पर तैयारी का कम समय मिलेगा।

सिपाही के 4210 पदों के लिए 16 लाख आवेदन आए

बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा

पटना,(ईएमएस) : बिहार पुलिस में कांस्टेबल के ४२१० पदों के लिए आयोजित भर्ती परीक्षा इस बार अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गई है। केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) द्वारा आयोजित इस परीक्षा में करीब १६ लाख उम्मीदवार शामिल हो रहे हैं, जिससे यह राज्य की सबसे बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में से एक बन गई है। परीक्षा १४ जून से शुरू होकर १७ जून तक अलग-अलग चरणों में आयोजित की जा रही है। पूरे राज्य में परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन का मुख्य उद्देश्य किसी भी प्रकार की नकल या पेपर लीक की संभावना को समाप्त करना है। इसी क्रम में परीक्षा व्यवस्था में कई सख्त नियम लागू किए गए हैं, जो पहले की परीक्षाओं की तुलना में काफी अलग हैं।

इस बार अभ्यर्थियों को अपना पेन परीक्षा केंद्र में लाने की अनुमति नहीं दी गई है। सभी उम्मीदवारों को पेन परीक्षा केंद्र पर ही उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा सबसे बड़ा बदलाव यह किया गया है कि किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा समाप्त होने से पहले परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।

अधिकारियों का मानना है कि इससे प्रश्नपत्र से जुड़ी किसी भी तरह की सूचना के लीक होने की संभावना को रोका जा सकेगा। मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही जिला प्रशासन और परीक्षा से जुड़े अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि परीक्षा अवधि के दौरान वे अपने मोबाइल फोन का उपयोग न करें, ताकि निगरानी व्यवस्था पूरी तरह मजबूत बनी रहे।

परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जा रही है। पहली पाली सुबह १० बजे से दोपहर १२ बजे तक और दूसरी पाली दोपहर ३ बजे से शाम ५ बजे तक हो रही है। अभ्यर्थियों को निर्धारित समय से पहले रिपोर्ट करना अनिवार्य किया गया है। यह परीक्षा ऑफलाइन मोड में ओएमआर शीट पर ली जा रही है, जिसमें कुल १०० बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्नपत्र में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स जैसे विषय शामिल हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है, जिससे गलत उत्तर देने पर अंक नहीं काटे जाएंगे।

लिखित परीक्षा के बाद केंद्रीय चयन पर्षद द्वारा प्रोविजनल आंसर-की जारी की जाएगी, जिस पर उम्मीदवार आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। अंतिम चयन प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी होगी-लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) और शारीरिक मानक परीक्षण (पीएसटी), जिसके बाद दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा। मुजफ्फरपुर जिले में इस परीक्षा के लिए २२ केंद्र बनाए गए हैं। जिला प्रशासन ने तैयारियों की समीक्षा करते हुए परीक्षा प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने पर जोर दिया है।

ऑटो-बाइक की टक्कर में युवक की मौत

पटना (एजेंसी): राजधानी पटना में मंगलवार को एनएच-३० पर लालू पेट्रोल पंप के पास तेज रफ्तार ऑटो और बाइक की आमने-सामने टक्कर होने की सूचना है। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

युवक की मौत की सूचना मिलते ही परिजन और स्थानीय लोग आक्रोशित हो उठे। बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर पहुंचे और शव को सड़क पर रखकर एनएच-३० जाम कर दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। सड़क पर हो रहे विरोध प्रदर्शन के कारण हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई और यातायात पूरी तरह बाधित हो गया।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और काफी समझाइश के बाद परिजनों को शांत कराकर जाम हटवाया। इसके बाद यातायात सामान्य हो सका। मृतक की पहचान बेऊर निवासी ५० वर्षीय अमरेंद्र कुमार के रूप में हुई है। हादसे के बाद परिवार में शोक का माहौल है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।

भारतीय क्रिकेटर आकाशदीप के घर पहुंचे सीएम सम्राट, शादी की दी

बड्डी (एजेंसी): मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मंगलवार को भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज आकाशदीप के पैतृक गांव बड्डी पहुंचे। मुख्यमंत्री ने आकाशदीप को उनकी शानदार उपलब्धियों पर बधाई दी और उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं। इस दौरान आकाशदीप ने मुख्यमंत्री को भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी भेंट की, जबकि उनकी मां ने शॉल ओढ़ाकर उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया () पर भी पर पोस्ट कीं।

परिवार से मिले, कहा-बिहार का नाम किया रोशन

मुख्यमंत्री ने आकाशदीप और उनके परिवार के सदस्यों से मुलाकात कर बातचीत की। उन्होंने कहा कि आकाशदीप ने अपने शानदार प्रदर्शन से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बिहार का गौरव बढ़ाया है। मुख्यमंत्री के आगमन से पूरे गांव में उत्साह का माहौल रहा। बड़ी संख्या में ग्रामीण उनके स्वागत के लिए मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने विशेष तैयारियां की थीं। हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के लिए गांव में अस्थायी हेलीपैड बनाया गया था। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए थे। मौके पर डीएम उदिता सिंह, एसपी रौशन कुमार समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री के इस दौरे से पूरे बड्डी गांव में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला।

शराब माफियाओं पर बड़ा शिकंजा 127 तस्करों की संपत्ति होगी जब्त

पटना (एजेंसी): बिहार में शराबबंदी कानून को और सख्ती से लागू करने के लिए सरकार ने अब शराब माफियाओं की अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। मद्य निषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने शराब के अवैध कारोबार से संपत्ति अर्जित करने वाले १२७ माफियाओं को चिन्हित किया है।

इनकी संपत्ति जब्त करने के लिए इछछड की धारा १०७ के तहत न्यायालय को प्रस्ताव भेजा गया है। सरकार का मानना है कि आर्थिक रूप से कमजोर कर शराब तस्करी के नेटवर्क को प्रभावी ढंग से तोड़ा जा सकता है। मद्य निषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के डीआईजी अजय कुमार पांडेय ने बताया कि वर्ष २०२६ में बिहार पुलिस ने हर महीने औसतन ३.५० लाख लीटर से अधिक शराब बरामद की है, जो पिछले वर्ष की तुलना में करीब ११ प्रतिशत अधिक है। वहीं ब्यूरो द्वारा प्रतिमाह औसतन १.०६ लाख लीटर शराब जब्त की गई है। इस वर्ष मई तक ५७ हजार से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें १९,८७७ शराब कारोबारी और ३७,०२७ शराब पीने वाले शामिल हैं। शराब तस्करों के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए बिहार पुलिस ने राज्य की सीमाओं से बाहर भी अभियान चलाया। मई २०२६ तक उत्तर प्रदेश और झारखंड में छह विशेष ऑपरेशन किए गए।

सीएम सम्राट ने की एयरपोर्ट और धार्मिक स्थलों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का ऐलान

कैमूर (एजेंसी): मुख्यमंत्री सम्राट ने कैमूर के प्रसिद्ध माता मुंडेश्वरी धाम से क्षेत्र के विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। रोहतास और कैमूर के बीच जल्द एयरपोर्ट का निर्माण कराया जाएगा, जिसके लिए जमीन चिन्हित करने का निर्देश अधिकारियों को दिया जा चुका है। लंबे समय से लंबित मुंडेश्वरी धाम रोप-वे परियोजना का काम बरसात के बाद शुरू होगा। मुख्यमंत्री बनने के बाद कैमूर में उनकी पहली यात्रा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मां ताराचंडी, तुतला भवानी और गुप्ता धाम समेत प्रमुख धार्मिक स्थलों को पर्यटन मानचित्र पर लाने के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की जाएगी। सरकार कैमूर को टूरिस्ट हब के रूप में विकसित करने की दिशा में काम कर रही है। इसके साथ ही मुंडेश्वरी धाम परिसर स्थित धर्मशाला के जीर्णोद्धार की भी घोषणा की गई, ताकि श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।

सीएम ने यह भी कहा कि अगले दो वर्षों में बिहार के सभी प्रखंडों में मॉडल स्कूल खोले जाएंगे। यहां नीट, जेईई और आईआईटी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। इस दौरान उन्होंने बिहार में बीएचयू की शाखा खोलने की संभावनाओं पर काम करने की बात भी कही। साथ ही चेतावनी दी कि ३० दिनों तक आदेश लंबित रखने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी। इसके अलावा २५ लाख बीपीएल परिवारों के घरों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे बिजली बिल में राहत मिलेगी जिससे अतिरिक्त बिजली उत्पादन पर सरकार भुगतान भी करेगी।

लखनऊ में फर्जी आईपीएस धराया 40 रुपये के विवाद में खुली पोल

लखनऊ (ईएमएस): लखनऊ में एक शातिर जालसाज को गिरफ्तार किया गया है, जिसने खुद को फर्जी आईपीएस अधिकारी बताकर पुलिसवालों को ही सैल्यूट मारने का दबाव बनाया। महानगर थाना क्षेत्र में सोमवार शाम ४० रुपये के बन को लेकर शुरू हुए विवाद ने उसकी पोल खोल दी और उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। सोमवार देर शाम महानगर के गोल मार्केट चौराहे पर पुलिस चेकिंग के दौरान एक दुकानदार ने सूचना दी कि खुद को आईपीएस बताने वाला व्यक्ति ४० रुपये के बन के पैसे दिए बिना जाने लगा है और धौंस जमा रहा है। पुलिस टीम जब मौके पर पहुंची, तो आरोपी युवक पुलिसकर्मियों पर भड़क उठा।

अयोध्या से 1250 बहुमूल्य श्रीराम शिलाएं गायब होने का दावा

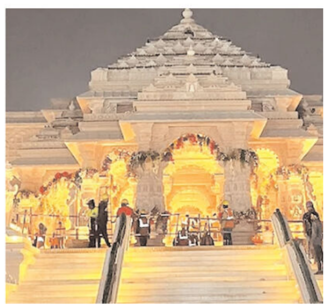

लखनऊ,(ईएमएस): धर्मसेना के संस्थापक संतोष दुबे ने अयोध्या में श्रीराम मंदिर के लिए देशभर से एकत्रित की गई १२५० सोने, चांदी, हीरे जड़ित और अष्टधातु की शिलाओं के 'गायब' होने का सनसनीखेज दावा किया है। दुबे के अनुसार, इन बहुमूल्य शिलाओं की देखरेख का जिम्मा तत्कालीन विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के पदाधिकारी और वर्तमान श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय पर था।

यह मामला १९८९ में विहिप द्वारा चलाए गए सवा रुपया दे दे रे भैया रामशिला के नाम का अभियान से जुड़ा है। इस अभियान के तहत देश-विदेश से करोड़ों लोगों ने श्रद्धापूर्वक दान दिया और अपने घरों से पूजित शिलाएं अयोध्या भेजीं। इसमें सोने, चांदी, हीरे-माणिक्य और अष्टधातु से बनी विशेष शिलाएं भी शामिल थीं। दुबे, जो उस समय २२-२३ वर्ष के थे, ने परमहंस रामचंद्र दास और डॉ. रामविलास वेदांती के साथ मिलकर इन कीमती शिलाओं का लेखा-जोखा तैयार किया था। उनकी जानकारी के अनुसार, मॉरीशस से आई एक शिला सबसे महंगी थी, जबकि मुंबई के एक व्यापारी ने हीरे जड़ित शिला दान की थी। कुल १२५० ऐसी धातु की शिलाएं थीं। दुबे बताते हैं कि ये सभी बहुमूल्य शिलाएं २००२ तक अयोध्या के कारसेवकपुरम में एक सुरक्षित स्थान पर तीन तालों के साथ रखी थीं। इनकी निगरानी का निर्देश तत्कालीन श्रीराम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष परमहंस रामचंद्र दास ने दिया था, और जिम्मेदारी चंपत राय को सौंपी गई थी। हालांकि, २००२ के बाद ये शिलाएं अचानक गायब हो गईं और अब इनका कोई अता-पता नहीं है।

दुबे सीधे तौर पर राय को इस गायब होने के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। उनका आरोप है कि परमहंस रामचंद्र दास इन शिलाओं के गायब होने के सदमे में बीमार पड़ गए और दो साल बाद उनका निधन हो गया, जबकि डॉ. रामविलास वेदांती डर की वजह से इस मुद्दे पर कभी बात नहीं कर पाए। दुबे का दावा है कि श्रीराम मंदिर के नाम पर चढ़ावे की चोरी आज नहीं, बल्कि १९८९ से ही शुरू हो गई थी। उन्होंने बताया कि कारसेवकपुरम में रखे दानपेटी में भी मासिक लाखों रुपये आते थे, जिसकी ५० रुपये से कम की राशियों का कोई लेखा-जोखा नहीं रखा जाता था और दान की कुल राशि कभी सार्वजनिक नहीं की गई। यह दावा श्रीराम मंदिर के नाम पर एकत्र किए गए दान की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

बच्चा मेरी गोद में आते ही रोना बंद कर मुस्कुराने लगता है : सीएम योगी

लखनऊ,(ईएमएस) : यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित डी-३ त्रिवेणी कार्यक्रम में बच्चों के प्रति अपने लगाव का जिक्र किया तो सभागार में मौजूद लोग मुस्कुराने लगे। योगी ने कहा कि जब भी वह किसी गांव, कस्बे या सार्वजनिक कार्यक्रम में जाते हैं तो वहां कई माताएं अपने छोटे बच्चों को लेकर आती हैं। उनका उद्देश्य बच्चों का अन्नप्राशन कराना होता है।

योगी ने कहा कि उन्हें बच्चों का अन्नप्राशन कराना अच्छा लगता है. उन्होंने कहा कि कई बार ऐसा होता है कि बच्चा अपने माता-पिता, दादा या दादी की गोद में होता है, लेकिन जैसे ही वह मेरी गोद में आता है, उसका रोना बंद हो जाता है और वह मुस्कुराने लगता है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सीएम योगी ने कहा कि बच्चे बेहद निष्कपट होते हैं और उनकी भावनाएं भी पूरी तरह स्वाभाविक होती हैं। उन्होंने कहा कि जब कोई बच्चा उनकी गोद में आता है तो उसे सुरक्षा का एहसास होता है। योगी ने कहा कि बच्चे के मन में यह भाव आता है कि वह पूरी तरह सुरक्षित है। शायद यही कारण है कि वह रोना छोड़ देता है और सहज हो जाता है। बच्चों की बात करते-करते सीएम योगी अचानक प्रशासनिक व्यवस्था और अपराध के मुद्दे पर आ गए। उन्होंने कहा कि यदि उनसे पूछा जाए कि उनका सबसे प्रिय विषय क्या है तो उनका जवाब होगा माफिया का सफाया करना। मुख्यमंत्री के इस बयान पर मौजूद लोगों ने तालियां बजाई।

सीएम योगी ने अपने कार्यकाल की एक घटना सुनाते हुए बताया कि एक बार उत्तर प्रदेश पुलिस के तत्कालीन डीजीपी उनसे मिलने पहुंचे। डीजीपी ने उन्हें जानकारी दी कि लखनऊ में पुलिस विभाग की एक अहम जमीन पर माफिया का कब्जा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि जैसे ही उन्होंने यह बात सुनी, उन्होंने तुरंत कहा कि यह तो मेरा सबसे प्रिय विषय है। उन्होंने अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए।

योगी ने बताया कि जमीन खाली कराने के बाद सरकार ने उसे यूं ही नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि उसी जमीन पर बाद में फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट का निर्माण कराया गया। यह सिर्फ अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई नहीं थी, बल्कि एक सकारात्मक बदलाव का उदाहरण भी था, जिस जमीन पर कभी माफिया का कब्जा था, वहां आज कानून व्यवस्था और वैज्ञानिक जांच से जुड़ा संस्थान खड़ा है। सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार अपराध और माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। चाहे वह कितना भी प्रभावशा-ली क्यों न हो कानून तोड़ा है तो कार्रवाई तय है।

फिटमेंट फैक्टर पर टिकीं कर्मचारियों की निगाहें

लखनऊ,(ईएमएस) : केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को ८वें वेतन की बड़ी राहत मिलने वाली है। इससे पहले वित्त आयोग केवल लखनऊ तक ही सीमित नहीं है, बल्कि देश के अलग-अलग हिस्सों में जाकर जमीनी स्तर पर सभी वर्गों से संवाद कर रहा है। लखनऊ के बाद आयोग की अगली बैठकें अगले महीने उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में तय की गई हैं, जिसके तहत ६ और ७ जुलाई को भुवनेश्वर में तथा ९ और १० जुलाई को कोलकाता में बैठकें आयोजित की जाएंगी। इससे पहले आयोग दिल्ली, श्रीनगर और लद्दाख जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों का दौरा कर वहां भी आवश्यक बैठकें संपन्न कर चुका है।

फिलहाल, सभी कर्मचारी और पेंशनर्स एसोसिएशनों की निगाहें सबसे ज्यादा फिटमेंट फैक्टर पर टिकी हुई हैं। विभिन्न संगठनों की तरफ से फिटमेंट फैक्टर को अधिक से अधिक रखने की मांग लगातार की जा रही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और सूत्रों के मुताबिक, वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर को २.८३ से लेकर ३.८३ के बीच तय कर सकता है, जिससे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। हालांकि, फिटमेंट फैक्टर के सटीक आंकड़ों को लेकर केंद्र सरकार की ओर से अभी तक कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ी राहत और उत्साह की बात यह है कि ८वां वेतन आयोग जब भी पूरी तरह लागू होगा, इसे १ जनवरी २०२६ से ही प्रभावी माना जाएगा। इसका सीधा मतलब यह है कि आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों को उनके पे-स्केल और क्लास के हिसाब से एक लंबी अवधि का, अच्छा-खासा एरियर (बकाया राशि) भी मिलेगा। समय पर बैठकों के आयोजन और प्रक्रिया में तेजी को देखते हुए कर्मचारियों में वेतन वृद्धि को लेकर उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं।

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए ८वें वेतन आयोग से जुड़ी एक बेहद महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। आयोग अपनी सिफारिशों और ड्राफ्ट को अंतिम रूप देने के लिए देशव्यापी दौरों और बैठकों का आयोजन कर रहा है। इसी कड़ी में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में २२ और २३ जून को एक बड़ी और अहम बैठक होने जा रही है।

आयोग द्वारा दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार, इस दो दिवसीय बैठक में कर्मचारी संगठनों और पेंशनर्स से जुड़े तमाम पक्षों को शामिल होने और अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। इसी बीच, वेतन आयोग ने साफ कर दिया है कि मेमोरेंडम (ज्ञापन) जमा करने की अंतिम तारीख में अब और कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। आयोग ने पहले इस समयसीमा को २९ मई से बढ़ाकर १५ जून २०२६ किया था, जो कि अब बीत चुकी है। ऐसे में समयसीमा को आगे न बढ़ाने के फैसले से स्पष्ट है कि आयोग अब तेजी से अपने काम को आगे बढ़ा रहा है।

फिर राम मंदिर पहुंची एसआईटी, मंदिर के पुजारियों, ट्रस्ट के पदाधिकारियों से की पूछताछ

अयोध्या (ईएमएस): श्रीराम जन्मभूमि मंदिर की दान पेटिका से जुड़ी कथित अनियमितताओं की जांच के लिए गठित तीन सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) लगातार दूसरी बार मंगलवार को अयोध्या पहुंची। टीम ने पहुंचते ही मामले से जुड़े दस्तावेजों, अभिलेखों और वित्तीय रिकॉर्ड की जांच शुरू कर दी। शासन की ओर से एसआईटी को सात दिन में प्रारंभिक रिपोर्ट और १५ दिन में अंतिम रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। वहीं, आज फिर दोबारा एसआइटी टीम राम मंदिर पहुंची है। यहां पर वो मंदिर के पुजारियों, ट्रस्ट के पदाधिकारियों और पकड़े गए संदिग्धों से पूछताछ की।

इस बीच, श्रीराम जन्मभूमि परिसर की दानपेटिका में कथित अनियमितता और चढ़ावे की चोरी के आरोपों को लेकर धर्म सेना प्रमुख एवं पूर्व शिवसेना नेता संतोष दुबे मंगलवार को थाना राम जन्मभूमि पहुंचे और पुलिस को तहरीर सौंपी।

एसआईटी ने चंपत राय से की लंबी पूछताछ और दस्तावेज भी खंगाले

अयोध्या(ईएमएस): अयोध्या के भव्य श्रीराम मंदिर में चढ़ावे की चोरी और वित्तीय गड़बड़ी के गंभीर आरोपों की जांच तेज हो गई है। राज्य सरकार द्वारा गठित स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) ने सोमवार से मंदिर परिसर में पहुंचकर अपनी जांच की कमान संभाल ली है। जांच के पहले ही दिन एसआईटी ने बेहद कड़ा और गोपनीय रुख अख्तियार किया। टीम ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से बंद कमरे में कई घंटों तक अकेले में पूछताछ की और मामले से जुड़े कई महत्वपूर्ण दस्तावेज व रिकॉर्ड अपने कब्जे में ले लिए। सोमवार दोपहर से शुरू हुआ यह जांच अभियान देर रात तक जारी रहा, जिसके बाद आज यानी मंगलवार से संबंधित लोगों से विधिवत पूछताछ का सिलसिला शुरू होने जा रहा है।

जांच को सुचारू रूप से चलाने के लिए मंदिर परिसर के भीतर ही एसआईटी का एक अस्थायी कैंप कार्यालय बनाने की तैयारी है, ताकि अधिकारी वहीं रहकर पूरी मुस्तैदी से काम कर सकें। सोमवार को जब एसआईटी के अधिकारी तीर्थयात्री सुविधा केंद्र (पीएफसी) पहुंचे, तो सबसे पहले वहां के पूरे स्टाफ को बाहर कर दिया गया। इसके बाद टीम ने उस गणनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया जहां श्रद्धालुओ द्वारा चढ़ाए गए धन की गिनती होती है। टीम ने वहां की सुरक्षा और सीसीटीवी निगरानी व्यवस्था का पूरा ब्योरा तलब किया।

पहले दिन की पड़ताल की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात यह रही कि मंदिर की व्यवस्थाओं में मुख्य भूमिका निभाने वाले वरिष्ठ पदाधिकारी गोपाल राव को इस पूरी प्रक्रिया से पूरी तरह दूर रखा गया। उन्होंने परिसर में प्रवेश करने का प्रयास भी किया, लेकिन एसआईटी के सख्त रुख के कारण उन्हें एंट्री नहीं मिल सकी। इससे यह साफ संकेत मिलता है कि जांच टीम किसी भी बाहरी प्रभाव के बिना, निष्पक्ष तरीके से हर जिम्मेदार पदाधिकारी से अलग-अलग पूछताछ कर सच सामने लाना चाहती है। इस उच्च स्तरीय एसआईटी में कमिश्नर लखनऊ विजय विश्वास पंत, आईजी किरण एस और विशेष सचिव (वित्त) नीलरतन कुमार शामिल हैं। टीम को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट महज एक सप्ताह के भीतर सरकार को सौंपनी है, जबकि विस्तृत और अंतिम रिपोर्ट के लिए १५ दिनों का समय दिया गया है। फिलहाल टीम संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार करने के लिए दो चरणों में काम कर रही है। पहले चरण में यह तय किया जाएगा कि चोरी की घटना वास्तव में हुई है या नहीं, और यदि हुई है तो यह कब से चल रही थी। इसके साथ ही इस बात का आकलन भी किया जाएगा कि कुल कितनी राशि गायब हुई है और क्या इसमें नकदी के साथ-साथ श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए सोने-चांदी के आभूषण भी शामिल हैं। दूसरे चरण में संदिग्धों के बयान दर्ज किए जाएंगे और भविष्य में ऐसी चूक न हो, इसके लिए सुर-क्षात्मक सुझाव दिए जाएंगे।

इस बीच, मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन और ट्रस्ट के पदेन सदस्य नृपेंद्र मिश्र ने इस पूरे मामले पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एसआईटी को इस मामले के आपराधिक और सुधारात्मक, दोनों ही पहलुओं को गहराई से देखना होगा। उनके अनुसार, जब जांच के निष्कर्ष पूरी तरह पारदर्शी होंगे, तभी आम जनता और देश-विदेश के करोड़ों श्रद्धालुओं का विश्वास दोबारा जीता जा सकेगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह की घटनाओं से सनातन की धारा रुकती नहीं है, वह निरंतर बहती रहती है।

झारखंड के 1.63 करोड़ मतदाताओं को नहीं देने होंगे दस्तावेज, पैतृक मैपिंग का पहला चरण पूरा

बीएलओ की मेहनत से आसान हुई एसआईआर प्रक्रियाः के. रविकुमार

रांची (एजेंसी): झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने कहा है कि राज्य के १.६३ करोड़ मौजूदा मतदाताओं को वर्ष २०२६ की विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के तहत कोई दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए राज्य के सभी बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) को बधाई देते हुए कहा कि उनकी मेहनत और समर्पण से स्वयं (सेल्फ) एवं पैतृक (पेरेंटल) मैपिंग का पहला चरण सफलतापूर्वक पूरा हो गया है।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि जिन मतदाताओं की मैपिंग हो चुकी है, उन्हें केवल विधिवत भरा हुआ प्री-फिल्ड गणना फॉर्म और हालिया रंगीन फोटो जमा करनी होगी। इन मतदाताओं का नाम प्रारूप और अंतिम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए किसी अतिरिक्त दस्तावेज की जरूरत नहीं पड़ेगी।

उन्होंने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया को लेकर कुछ चुनौतियां सामने आ रही हैं, लेकिन बीएलओ अपने अनुभव और चुनावी प्रक्रिया की समझ के बल पर इनका सफलतापूर्वक सामना करेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अपने झारखंड दौरे पर भी दौरान बीएलओ के कार्यों और उनके ज्ञान की सराहना की है।

घर-घर जाकर सर्वेक्षण की औपचारिक शुरुआत 30 जून से

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि घर-घर जाकर सर्वेक्षण की औपचारिक शुरुआत ३० जून २०२६ से होगी, लेकिन इससे पहले ही यह स्पष्ट हो चुका है कि अधिकांश मतदाताओं को दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं है।

उन्होंने बताया कि शेष बचे अनमैप मतदाताओं की स्वयं और पैतृक मैपिंग का दूसरा एवं अंतिम चरण ३० जून से २९ जुलाई २०२६ तक चलेगा। यदि कोई मतदाता या उसके माता-पिता पहले झारखंड के बाहर किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की एसआईआर मतदाता सूची में पंजीकृत रहे हैं, तो उन्हें संबंधित विवरण बीएलओ को उपलब्ध कराना होगा।

मतदाता, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और अन्य हितधारक पिछली एसआईआर मतदाता सूची में अपना नाम ऑनलाइन भी खोज सकते हैं। जिन मतदाताओं को दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता होगी, उनकी सूची ५ अगस्त २०२६ को या उसके बाद प्रत्येक मतदान केंद्र और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। ऐसे मतदाताओं को व्यक्तिगत नोटिस भी भेजा जाएगा।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि प्रवासी श्रमिकों, राज्य से बाहर पढ़ाई कर रहे छात्रों तथा अस्थायी रूप से बाहर रहने वाले लोगों को मैपिंग के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। परिवार के सदस्य के माध्यम से, बीएलओ से संपर्क कर या ईसीआईनेट की 'बुक-ए-कॉल' सुविधा का उपयोग कर यह प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।

तकनीक के इस दौर में अंगदान से बचाई जा सकती हैं कई जिंदगियांःहेमन्त सोरेन

रांची (एजेंसी): आज मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन बारियातू रोड स्थित एक होटल में मोहन फाउंडेशन द्वारा आयोजित अंग और ऊतक दान में सर्वोत्तम कार्य-पद्धतियाँ कार्यशाला में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अंगदान के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि यह बेहद महत्वपूर्ण विषय है और इसके लिए व्यापक सामाजिक जागरूकता और सहभागिता की आवश्यकता है। उन्होंने स्वास्थ्य संस्थानों, सामाजिक संगठनों और आम लोगों से मिलकर इस दिशा में कार्य करने का आह्वान किया।अंगदान मानवता, संवेदनशीलता और सामाजिक उत्तरदायित्व का प्रतीक

मुख्यमंत्री हेमन्त ने अपने संबोधन में कहा कि अंगदान किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन में नई उम्मीद और खुशियां ला सकता है। उन्होंने इसे मानवता, संवेदनशीलता, करुणा और सामाजिक उत्तरदायित्व का सबसे बड़ा प्रतीक बताया। मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि अस्पतालों में किसी व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत उनके परिवारवालों से अंगदान के विषय पर संवेदनशीलता के साथ बातचीत की जानी चाहिए ताकि अधिक से अधिक जिंदगियों को बचाया जा सके।

जागरूकता और कानूनी पहलुओं की समझ जरूरी

मुख्यमंत्री ने इस बात पर विशेष बल दिया कि समाज में अंगदान के प्रति झिझक को दूर करने के लिए लोगों को जागरूक करना होगा। इसके साथ ही, इसके कानूनी पहलुओं की सही जानकारी होना भी बेहद जरूरी है। राज्य सरकार भी इस दिशा में निरंतर प्रयास और पहल कर रही है। उन्होंने मोहन फाउंडेशन की इस कार्यशाला की सराहना करते हुए इसे एक बेहतरीन और सकारात्मक पहल बताया।

वर्तमान चिकित्सा प्रणाली का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का युग तकनीक आधारित है। चिकित्सा जगत में बड़े पैमाने पर आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है, जिसके तहत रोबोटिक ऑपरेशन से लेकर लिवर और किडनी का सफल ट्रांसप्लांट किया जा रहा है। झारखंड सरकार भी राज्य के नागरिकों के बेहतर स्वास्थ्य और एक 'स्वस्थ झारखंड' के निर्माण की दिशा में लगातार सकारात्मक और ठोस कदम उठा रही है।

इस महत्वपूर्ण कार्यशाला में स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. इरफान अंसारी, अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह, मणिपाल ऑर्गन शेयरिंग के कंट्री हेड कर्नल अवनीश, मोहन फाउंडेशन की कंट्री हेड श्रीमती ललिता रघुराम, क्रिटिकल केयर मणिपाल के अध्यक्ष डॉ० विजय कुमार मिश्रा, और कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल के संस्थापक निदेशक डॉ० बी० कश्यप सहित चिकित्सा और सामाजिक क्षेत्र के कई गणमान्य अतिथि उपस्थित थे।

सीएम हाउस में महागठबंधन ने दिखायी एकजुटता, हेमंत सोरेन ने पढ़ाया जीत का पाठ

रांची (एजेंसी): राज्यसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच आज महागठबंधन के विधायकों और नेताओं का सीएम हाउस में जमावड़ा लगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में झामुमो प्रत्याशी बैजनाथ राम और कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा के अलावा कांग्रेस प्रभारी के राजू, सैयद नासिर हुसैन, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के अलावा झामुमो, कांग्रेस, राजद और माले विधायक उपस्थित थे।

इस बैठक में महागठबंधन के दोनों प्रत्याशियों को जीत दिलाने के मुद्दे पर सभी दलों के वरीय नेताओं ने अपनी एकजुटता प्रदर्शित की। विधायकों ने भी अपनी इंटीग्रिटी दर्शायी। मुख्य बात यह रही कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधायकों से एकजुट रहने और चट्टानी एकता की तरह दोनों प्रत्याशियों को जीत दिलाने का निर्देश और आदेश दिया।

जानकारी के अनुसार १७ जून को भी महागठबंधन के विधायक फिर सीएम हाउस जुटेंगे। वहां डीनर डिप्लोमेसी होगी। आज भी चाय, नाश्ता के साथ विधायकों को सुस्वादु भोजन कराया गया।

राज्य की जेलों में कक्षपाल पदों पर होगी भर्ती, जारी हुआ आदेश

रांची (एजेंसी): झारखंड सरकार के गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं निरीक्षणालय) ने राज्य की विभिन्न जेलों में खाली पड़े पदों को भरने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। विभाग द्वारा जारी नियुक्ति विज्ञापन संख्या-०२/जेल/२०२६ के अनुसार, राज्य के विभिन्न जेलों में कक्षपाल और महिला कक्षपाल के रिक्त पदों पर कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर भूतपूर्व सैनिकों और अर्धसैनिक बलों के जवानों की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए आगामी १५ जुलाई को वॉक-इन इंटरव्यू का आयोजन किया जा रहा है।

कुल 157 रिक्त पदों पर होगी नियुक्ति

इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल १५७ पदों (१४९ पुरुष और ०८ महिला) पर योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। यह पद पूरी तरह से राज्य स्तरीय हैं। केन्द्रीय कारा, घाघीडीह, जमशेदपुरः ९५ पुरुष और एक महिला कक्षपाल का पद खाली है। मंडल कारा, चाईबासाः ११ पुरुष और तीन महिला कक्षपाल का पद खाली है। मंडल कारा, सरायकेलाः ३२ पुरुष और चार महिला कक्षपाल का पद खाली है।

जमशेदपुर में होगी इंटरव्यू

इच्छुक और योग्य भूतपूर्व सैनिक और अर्धसैनिक बल के जवान अपने सभी आवश्यक मूल दस्तावेज के साथ १५ जुलाई को उपस्थित होकर इस प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। यह इंटरव्यू केन्द्रीय कारा, घाघीडीह अधीक्षक कार्यालय जमशेदपुर में होगा। यह नियुक्तियां शुरुआत में एक वर्ष के लिए की जाएंगी। आवश्यकतानुसार अनुबंध की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। हालांकि नियमित नियुक्ति होने पर अनुबंध समाप्त कर दिया जाएगा। नियुक्त किए गए कर्मियों को बीस हजार रुपये प्रति माह का एकमुश्त मानदेय दिया जाएगा। इसके अलावा, प्रत्येक वर्ष की सेवा अवधि पूरी होने पर मानदेय में आठ प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाएगी। कर्मियों को एक वर्ष में केवल २० दिनों का क्षतिपूर्ति अवकाश मिलेगा। सरकारी ड्यूटी के दौरान नियमानुसार यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता देय होगा। कर्तव्य पालन के दौरान मृत्यु होने पर राज्य पुलिसकर्मियों की तरह अनुग्रह अनुदान मिलेगा, लेकिन आश्रित को सरकारी नौकरी देने का कोई प्रावधान नहीं है।

झारखंड में भोजपुरी समेत क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों को भी मिले बढ़ावा, कलाकारों ने मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू से की मुलाकात

रांची (एजेंसी): झारखंड के कलाकारों और फिल्म जगत से जुड़े लोगों ने राज्य सरकार से एक खास मांग की है। उनका कहना है कि झारखंड की नई फिल्म नीति (ऋळश्रा झेश्रळल्र) में भोजपुरी के साथ-साथ राज्य की सभी क्षेत्रीय और स्थानीय भाषाओं को भी जगह मिलनी चाहिए। इस सिलसिले में कलाकारों के एक दल ने मंगलवार को राज्य के कला एवं संस्कृति मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू से मुलाकात की और उन्हें अपनी मांगों का एक ज्ञापन सौंपा।

फिल्म बनाने वालों ने की सब्सिडी की मांग

कलाकारों का कहना है कि झारखंड में कई तरह की भाषाएं और संस्कृतियां हैं। इसलिए सरकार को चाहिए कि वह भोजपुरी, नागपुरी, संथाली, कुड़ख, मुंडारी, खोरठा, मगही, मैथिली, हिंदी, बंगाली और पंजाबी समेत सभी भाषाओं की फिल्मों को आगे बढ़ाने के लिए मदद करे। उन्होंने मांग की कि इन सभी भाषाओं की फिल्मों को बराबर का मौका मिलना चाहिए और फिल्म बनाने वालों को सब्सिडी (सरकारी मदद) व दूसरी जरूरी सुविधाएं दी जानी चाहिए।

इसके अलावा, राज्य में फिल्मों की शूटिंग आसान बनाने के लिए एक साफ-सुथरी और नई 'शूटिंग पॉलिसी' भी बनाई जानी चाहिए। प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री को बताया कि झारखंड में खूबसूरती की कोई कमी नहीं है। यहां के सुंदर झरने, घने जंगल, पहाड़ और ऐतिहासिक जगहें फिल्मों की शूटिंग के लिए बेहतरीन हैं। अगर सरकार फिल्म बनाने को बढ़ावा देगी, तो बाहर से भी लोग यहां शूटिंग के लिए आएंगे। इससे झारखंड के स्थानीय कलाकारों, तकनीशियनों (ढशलहपळललरपी) और युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेगा। साथ ही, झारखंड की अनूठी संस्कृति को देश और दुनिया में एक नई पहचान मिलेगी। कलाकारों की बातें सुनने के बाद कला एवं संस्कृति मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने उन्हें पूरा भरोसा दिलाया। मंत्री ने कहा कि सरकार राज्य के कलाकारों और फिल्म उद्योग की तरक्की के लिए पूरी तरह गंभीर है। उन्होंने वादा किया कि कलाकारों ने जो भी सुझाव दिए हैं, उन पर सरकार बहुत जल्द और सकारात्मक तरीके से विचार करेगी। इस मुलाकात के दौरान भोजपुरी युवा विकास मंच के अध्यक्ष अशोक द्विवेदी, आशुतोष द्विवेदी, संजय पुजारी, लव पाठक, अशोक कुमार, बृजेश कुमार और मिथिला युवा मंच के अध्यक्ष अवधेश ठाकुर समेत कई प्रमुख लोग मौजूद रहे।

दिव्यांग ने लगायी पुलिस से आवास खाली कराने की गुहार

रांची (एजेंसी): रांची के धुर्वा थाना क्षेत्र के सेक्टर-४ स्थित आवास संख्या --४५/२ चतुर्थ के निवासी संजीत कुमार सिंह ने अपने आवास पर कथित अवैध कब्जा हटाने तथा सुरक्षा प्रदान करने की मांग को लेकर थाना प्रभारी को आवेदन सौंपा है। आवेदन में उन्होंने बताया कि उनके पिता स्वर्गीय रामसेवक सिंह एचईसी के कर्मचारी थे, जिनकी ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो गई थी। इसके बाद वर्ष २००३ में उक्त आवास उन्हें आवंटित किया गया था। संजीत कुमार सिंह का कहना है कि गंभीर बीमारी और आर्थिक तंगी के कारण उन्हें इलाज के लिए बाहर रहना पड़ा, जिससे आवास की देखरेख नहीं हो सकी।

पृष्ठ एक का शेषांश

मोरहाबादी मैदान में सीएम---

लाभ उठाना चाहिए। कम पानी में अधिक उत्पादन, ड्रिप इरिगेशन तथा वैज्ञानिक तरीके से खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की बिरसा हरित ग्राम योजना किसानों के लिए काफी लाभकारी साबित हो रही है। इस योजना के तहत अब तक करीब डेढ़ लाख एकड़ भूमि में फलदार पौधों और बागवानी आधारित खेती का विकास किया गया है। तीन-चार वर्षों के भीतर बड़े पैमाने पर यह कार्य पूरा किया गया है, जिससे किसानों को आय के नए स्रोत मिले हैं और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि झारखंड में कृषि और बागवानी के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। यदि किसान आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाएं तो राज्य कृषि के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू सकता है। सरकार किसानों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जलवायु परिवर्तन का सबसे ज्यादा असर खेती-बाड़ी पर पड़ रहा है। झारखंड में लगभग ८० प्रतिशत लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खेती पर निर्भर हैं। ऐसे में जल संचय को जन आंदोलन बनाने की जरूरत है।

उन्होंने कहा कि आने वाले समय में पीने के पानी और सिंचाई के लिए पानी की बड़ी चुनौती सामने आने वाली है। यदि अभी से जल संरक्षण नहीं किया गया तो भविष्य में बड़ी संख्या में चापाकल सूख सकते हैं। इसलिए गांवों और बंजर जमीनों पर रिचार्ज पिट, सोख्ता पिट तथा वर्षा जल संचयन के कार्यों को बढ़ावा देना होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि धरती से लगातार भूजल निकाला जा रहा है, इसलिए जितना पानी हम धरती से ले रहे हैं, उतना उसे वापस लौटाने की भी जिम्मेदारी हमारी है। उन्होंने किसानों से कम पानी में अधिक उत्पादन देने वाली तकनीकों, खासकर ड्रिप इरिगेशन जैसी आधुनिक सिंचाई पद्धतियों को अपनाने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनियंत्रित शहरीकरण सबसे बड़ा अभिशाप बनता जा रहा है। कंक्रीट के जंगल खड़े हो रहे हैं और लोग पत्थर तथा लोहे के बीच रहने को मजबूर हो रहे हैं। गांवों को आदर्श गांव के रूप में विकसित करने की जरूरत है।

जी-7 शिखर सम्मेलन में---

रक्षा सहयोग, हिंद-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा और हालिया क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर चर्चा होने की संभावना है। जी-७ सम्मेलन में पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने किया। भारत को इस सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार के रूप में देखा जा रहा है और कई वैश्विक मुद्दों पर भारत की भूमिका केंद्र में बनी हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की यह मुलाकात भारत-अमेरिका संबंधों को नई दिशा देने के साथ-साथ वैश्विक कूटनीति में भी महत्वपूर्ण संदेश दे सकती है।

सिरप अब डॉक्टर के---

इस अनुसूची में उन दवाओं को रखा गया था, जिन्हें कुछ नियमों में छूट दी गई थी। अब इस सूची से सिरप को हटा लिया गया है। मंत्रालय ने बताया कि इस बदलाव से पहले २९ दिसंबर २०२५ को मसौदा अधिसूचना जारी कर आम लोगों और संबंधित पक्षों से सुझाव और आपत्तियां मांगी गई थीं। सरकार ने कहा कि नियमों में संशोधन से पहले देश की सर्वोच्च वैधानिक तकनीकी सलाहकार संस्था ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड से परामर्श किया गया था। केंद्र सरकार ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, १९४० की धारा १२ और ३३ के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए यह बदलाव किया था। ड्रग्स रूल्स, १९४५, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, १९४० के तहत बनाए गए हैं। ये नियम भारत में दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण को नियंत्रित करते हैं।

दवा सुरक्षा और गुणवत्ता को लेकर केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों में कई कदम उठा चुकी है। २०२२-२३ में भारत में बनी कुछ कफ सिरप दवाओं को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सवाल उठे थे। अफ्रीकी देशों और उज्बेकिस्तान में बच्चों की मौत के मामलों के बाद भारतीय दवाओं की गुणवत्ता पर निगरानी बढ़ाई गई थी। इसके बाद सरकार ने कफ सिरप के निर्यात से पहले सरकारी लैब में अनिवार्य परीक्षण की व्यवस्था लागू की। साथ ही दवा निर्माण इकाइयों के लिए गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस मानकों को भी सख्त किया गया। कई कंपनियों के लाइसेंस निलंबित किए गए और उत्पादन इकाइयों पर कार्रवाई हुई।

आधार का इस्तेमाल---

पते या जन्मतिथि का सबूत है। इसके बावजूद, यह दस्तावेज व्यापक रूप से स्कूल में दाखिले, प्रॉपर्टी के लेनदेन, जन्म प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और नए वोटर रजिस्ट्रेशन (फॉर्म-६) जैसे विभिन्न कार्यों के लिए उम्र, निवास, नागरिकता और पते के सबूत के तौर पर स्वीकार किया हो रहा है। याचिकाकर्ता ने नए वोटर रजिस्ट्रेशन में जन्मतिथि और निवास के लिए आधार के उपयोग को विशेष रूप से चुनौती दी है, इस आधार और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के खिलाफ बताया है।

याचिका में तर्क दिया गया है कि आधार नामांकन फ्रेमवर्क के तहत, भारत में करीब १८२ दिनों से रह रहे विदेशी नागरिक भी आधार प्राप्त करने के हकदार हैं। आरोप है कि इस ढीले वेरिफिकेशन सिस्टम का फायदा उठाकर कथित घुसपैठिए और अवैध प्रवासी आधार कार्ड पा लेते हैं। वे बाद में इन आधार कार्डों का उपयोग राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर पहचान पत्र जैसे अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज प्राप्त करने के लिए करते हैं। यह प्रक्रिया आधार अधिनियम के तहत स्थापित पहचान फ्रेमवर्क की विश्वसनीयता को कमजोर करती है और अयोग्य लोगों को सब्सिडी और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने में मदद करती है, जिससे सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग होता है और वास्तविक लाभार्थियों को वंचित होना पड़ता है।

झारखंड में दुर्लभ---

में दुर्लभ और महत्वपूर्ण खनिजों से संबंधित २० से अधिक खनिजों की मौजूदगी है। इनमें लिथियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, सिल्वर, ग्रेफाइट समेत कई महत्वपूर्ण खनिज शामिल हैं। साथ ही, दुर्लभ खनिजों के नए क्षेत्रों की खोज और अन्वेषण की प्रक्रिया भी लगातार जारी है। बैठक के दौरान अमेरिकी काउंसलेट जनरल के माध्यम से अमेरिकी कंपनियों को झारखंड में खनन, खनिज अन्वेषण और उन्नत तकनीक आधारित गतिविधियों से जुड़ने के लिए आमंत्रित किया गया। उन्हें बताया गया कि इस क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीक के साथ कार्य कर रही विश्व की विभिन्न अग्रणी कंपनियों के साथ राज्य सरकार लगातार संपर्क स्थापित कर रही है और इस दिशा में उल्लेखनीय प्रगति भी हुई है। बैठक में इच्छुक कंपनियों को खनिज ब्लॉक उपलब्ध कराने तथा अत्याधुनिक तकनीकों के माध्यम से खनन और प्रसंस्करण कार्य किए जाने की संभावनाओं पर भी चर्चा की गई। बैठक में खान एवं भूतत्व विभाग के सचिव अरवा राजकमल, खान निदेशक राहुल कुमार सिन्हा, अमेरिकी काउंसलेट जनरल कैली जाइल डियाज सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

राज्यपाल से मिलीं सर्जन वाइस एडमिरल आरती सारिन; विशेष नेत्र चिकित्सा शिविर की दी जानकारी

रांची (एजेंसी): झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मंगलवार को सर्जन वाइस एडमिरल आरती सारिन ने रांची स्थित लोक भवन में शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर आरती सारिन ने राज्यपाल को बताया कि मुख्यालय पूर्वी कमान एवं मुख्यालय १११ एरिया के तत्वावधान में १५ से १९ जून तक रांची के नामकुम स्थित सैन्य चिकित्सालय में एक विशेष नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है।

यह शिविर आर्मी हॉस्पिटल (रिसर्च एंड रेफरल), नई दिल्ली की विशेषज्ञ टीम के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। शिविर में भूतपूर्व सैनिकों, उनके आश्रितों, जनजातीय समुदाय के लोगों तथा आम नागरिकों को नेत्र परीक्षण, परामर्श और विभिन्न प्रकार की नेत्र चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

जनकल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के मेगा चिकित्सा शिविर समाज के विभिन्न वर्गों तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि इससे दूरस्थ और जरूरतमंद लोगों को विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी। यह भी कहा कि ऐसे आयोजन स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने के साथ-साथ जनकल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं।

राज्यपाल से 'पॉलिथीन मुक्त अभियान' से जुड़े प्रतिनिधिमंडल ने की भेंट

राज्यपाल से मंगलवार को रामगढ़ निवासी उपेंद्र पांडेय सहित प्रतिनिधिमंडल के अन्य सदस्यों ने रांची स्थित लोकभवन में शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने 'पॉलिथीन मुक्त अभियान' के तहत किए जा रहे जन-जागरूकता और पर्यावरण संरक्षण संबंधी प्रयासों की विस्तृत जानकारी दी।

प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को बताया कि वे लोगों को प्लास्टिक पॉलिथीन के उपयोग से बचने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और इसके स्थान पर कपड़े एवं पर्यावरण-अनुकूल झोलों के उपयोग को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके साथ ही 'सेल्फी विद झोला' अभियान के माध्यम से भी आम लोगों में जागरूकता फैलाने का कार्य किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि वे विभिन्न विद्यालयों में जाकर विद्यार्थियों और शिक्षकों को पर्यावरण संरक्षण से जुड़े विषयों पर जागरूक कर रहे हैं तथा दैनिक जीवन में कपड़े के झोले के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। राज्यपाल ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि स्वच्छ एवं हरित पर्यावरण के निर्माण में जनभागीदारी अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के जन-जागरूकता अभियान समाज के लिए अत्यंत प्रेरणादायी हैं और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

केला

कई रोग दूर करता है

केला खाने से शरीर मजबूत और स्वस्थ बनता है। पका केला स्वाद में मीठा और तासीर में ठंडा होता है। केला वीर्यवर्द्धक माना जाता है। यह ऐसा फल है, जिसे हर आयु के लोग खाना पसंद करते हैं। चार-पाँच माह के शिशु को भी केला अच्छी तरह से मैश करके देने की सलाह डॉक्टर देते हैं। सर्दियों में शिशु को केला देते समय उबलते पानी में छिलके समेत कुछ ढीला होने तक रखें, फिर उसे मैश करके में दो पके केले व थोड़ा-सा नमक, डालकर खाने से दस्त और पेचिश ठीक होने में सहायता मिलती है। कब्ज होने पर दो केले एक साथ लगातार कई दिन तक सेवन करें। आग से जलने पर पके केले के गदे का लेप करें। महिलाओं के प्रदर रोग में भी केला लाभप्रद है। दस दिन एक गिलास दूध के साथ केले का सेवन करने से नकसीर वाले रोगियों को फायदा होता है। केले के तने का रस पीने से पेट के रोग

पुराना केला ढीला होने पर अपना स्वाद खो देता है और उसकी पौष्टिकता भी समाप्त हो जाती है। बुखार में केला खाने से शरीर को ताकत मिलती है।

शिशु को दे सकते हैं, जिससे ठंडे मौसम के अनुसार शिशु को नुकसान नहीं होगा। ध्यान रखें, केला हमेशा ताजा खाएँ। पुराना केला ढीला होने पर अपना स्वाद खो देता है और उसकी पौष्टिकता भी समाप्त हो जाती है। बुखार में केला खाने से शरीर को ताकत मिलती है। दुबले लोग पके केले को दूध के साथ लगातार लें, जिससे शरीर का वजन बढ़ाया जा सकता है। केले को भोजन के साथ या भोजन के बाद खाएँष खाली पेट केले का सेवन न करें। मुँह में छाले होने पर सुबह गाय के घी के साथ केला खाने से छालों में लाभ होता है। पेट में गैस बनने पर भी दूध और केला एक साथ लें। जब कभी पेचिश या दस्त लगे हों, आधी कटोरी दही दूर होते हैं। केला रक्तचाप सामान्य करने में भी लाभदायक बताया जाता है, क्योंकि इसमें पोटेशियम अधिक मात्रा में होता है। रक्ताल्पता के शिकार लोगों के लिए भी केला लाभप्रद है।

केला अत्यधिक लाभदायक फल है। इसका सेवन नियमित करते रहें। पर यह भी ध्यान रखें कि अधिक मात्रा में कुछ भी खाना नुकसानदेह हो सकता है। मोटापे के शिकार लोग भी सावधानीपूर्वक केला खाएँ क्योंकि एक मध्यम आकार के केले में 100 कैलोरी ऊर्जा होती है।

आंखों को सुरक्षित रखने के नुस्खे

- सुबह उठते ही सबसे पहले आंखों पर अच्छी तरह छींटे मारकर उन्हें धोएं। सुखाने के लिए मुलायम तौलिए का इस्तेमाल करें।
- कच्चे आलू या खीरे को लगभग चार चम्मच के बराबर घिस लें। इन्हे दोनों आंखों पर 15 मिनट रखें और इसके बाद ठंडे पानी से धो दें।
- इस्तेमाल किए हुए टी बैग फ्रिज में रखें और ठंडे होने पर आंखों पर रख कर कुछ देर लेटें। इसके अलावा गुनगुने पानी में नमक डालकर रूई इसमें भिगो कर भी कुछ देर आंखों पर रख सकती हैं। इससे आंखों में चमक आती है।
- अंजीर के आधे कटे टुकड़े आंखों पर रखें।
- आलू या खीरे के कटे टुकड़े फ्रिज में हमेशा रखें। बाहर से आने पर कुछ देर रखने से आंखों को ठंडक मिलती है।
- अपने भोजन पर ध्यान दें। हरी सब्जियां, सभी तरह के फल और ढेर सा पानी आंखों के काले दायरों से निजात दिलाता है।

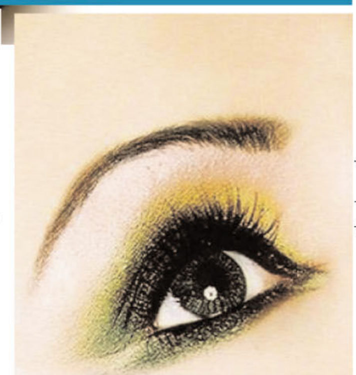

अंकुरित अनाज

पोषण का खजाना

यदि आप अधिक स्वास्थ्य कर लाइफ स्टाइल चाहते हैं तो अंकुरित अनाज को अपने भोजन में शामिल करना सबसे सरल उपाय हो सकता है। पोषण के शक्तिस्थल इन 'लिविंग फूड्स' को खरीदने के लिए कहने का एक बड़ा कारण यह भी है कि इनमें विटामिन्स, मिनरल्स, एंटी-ऑक्सीडैंट्स बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं।

अल्फा-अल्फा अंकुर

यह विविधतापूर्ण अंकुर विटामिन ए, बी, डी, ई और जी का बहुमूल्य स्त्रोत है। यह कैल्शियम, मैग्निशियम, फास्फोरस, क्लोरीन, सोडियम, पोटाशियम और सिलीकोन भी प्रदान करता है। शरीर के अंगों के ठीक तरह काम करने के लिए ये सभी बहुत आवश्यक हैं। इसमें गेहूं तथा मक्का के मुकाबले डेढ़ गुणा अधिक प्रोटीन होता है जबकि कार्बोहाईड्रेट्स की मात्रा आधी होती है। यह डाइट्री फाइबर तथा क्लोरोफिल का भी बढ़िया साधन है। इसे दिल, पेट तथा श्वास की गड़बड़ी को दूर करने तथा आर्थराइटिस, बालों का झड़ना और उच्च रक्तचाप के लिए इस्तेमाल किया जाता है।''

काले चने का अंकुर

यह विटामिन बी कॉम्पलैक्स का बढ़िया स्त्रोत है। रात को भिहों कर और सुबह जामुन के शहद के साथ खाने से यह प्राकृतिक टॉनिक की तरह काम करता है। अंकुरित चने का पानी ग्लूकोज का उपभोग बढ़ाता है जो मधुमेह के लिए विशेषरूप से सहायक है। यह आयरन का भी बड़ा स्त्रोत है।

मूंग का अंकुर

यह सारा साल उपलब्ध रहता है। यह स्वादिष्ट और क्रंची अंकुर बीमारी के बाद कमजोरी को दूर करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सबसे हल्के अंकुरों मे से एक है।

दैनिक जीवन में इस्तेमाल

यदि आप बीमार हैं तो सूप में इसका इस्तेमाल सबसे बढ़िया रहता है। इसे कच्चा, उबाल कर या सलाद में मिला कर भी खाया जा सकता है।

एसिडिटी का उपचार

शहरों में अधिकांश मरीज अम्लाधिक्य-जन्य रोगों से पीड़ित हैं, जैसे उदर, हृदय-प्रदेश तथा कंठ में दाह, भोजनानंतर उदरशूल, अम्ल उद्गार, उल्टी की आशंका, अजीर्ण विकार, अतिलाला-स्त्राव, बमन, क्षुधानाश, अफारा, गैस, आमाशय शोथ आदि। ये सब पित्त विकार के लक्षण हैं। इसे साधारण भाषा में एसिडिटी या तेजाब बनना कहते हैं।

पित्त की उत्पत्ति

विषम भोजन करने, खटाई, खारे, चरपटे, मिर्च आदि तीक्ष्ण पदार्थों को अधिक खाने, भूख-प्या, रोकने, चाय, शराब, गुटखा आदि के अधिक प्रयोग, थकावट, क्रोध करने, अग्नि तपने, धूप में अधिक फिरने से, दोपहर के वक्त, आधी रात, जवानी की उम्र में, शरद और ग्रीष्म ऋतुओं में, भोजन पचने के काल में पित्त उत्पन्न होकर विकार पैदा करता है।

पित्त प्रकोप के लक्षण

मुंह का जायका कड़वा होना, चेहरा व्याकुल होना, होंठ सूखना, प्यास अधिक लगना, शरीर कमजोर पड़ना, पसीना अधिक आना, बुखार तेज होना, ठंडे पदार्थों पर रूचि चलना, दाह अधिक होना, त्वचा का वर्ण पीला होना, नींद कम आना, इंद्रियों में दुर्बलता, मल-मूत्र में पीलापन, अग्नि का तीक्ष्ण होना आदि हो, तो पित्त प्रकोप जानें। जबकि क्षीण पित्त में गठराग्नि मंद हो जाती है तथा आहार ठीक से नहीं पचता।

पित्त शांति के उपाय

ठंडे जल से स्नान करना, ठंडा जल पीना, रसदार और सुगंधित भोजन करना, चंद्रमा की चांदनी में बैठना व सोना विशेषकर शरद ऋतु में। घरेलू चीजों में कुछ चीजें इसमें उपयोगी हैं जैसे हल्दी, सौंफ, सुपारी, सिंघाड़ा, सनाय, शंखपुष्पी, धनिया, अडूसा, आवंला, छोटी इलायची, ईख, कुनेन, खजूर खशखश, ग्वारपाठा, अंगूर, अनार, मेहंदी, गूलर, जीरा, नीम, त्रिफला, प्रवाल, गुलाबजल, लौंग, चंदन आदि।

जापानी मैंगो सैंडविच

अगर आप कुछ नया, ठंडा और मीठा-तीखा स्वाद एक साथ ट्राई करना चाहते हैं, तो यह जापानी मैंगो सैंडविच एक बेहतरीन और यूनिक डेजर्ट है। आम और वनीला आइसक्रीम का यह कॉम्बिनेशन न सिर्फ स्वाद में लाजवाब है, बल्कि गर्मियों में इसे बनाना भी बेहद आसान है। मीठे आम और हल्की मसालेदार चाट मसाला ट्विस्ट इसे एक अलग ही लेवल का फ्यूजन डिश बना देते हैं।

ब्रेड स्लाइस – 2
लाल मिर्च पाउडर – 1/2 छोटा चम्मच
नमक – 1/2 छोटा चम्मच
चाट मसाला – 1/2 छोटा चम्मच
वनीला आइसक्रीम – 2 स्कूप/स्लाइस
आम – 150 ग्राम

बनाने की विधि

1. सबसे पहले ब्रेड स्लाइस के किनारे (क्रस्ट) काट लें।
2. एक बाउल में 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च, 1/2 छोटा चम्मच नमक और 1/2 छोटा चम्मच चाट मसाला अच्छे से मिला लें।
3. अब एक ब्रेड स्लाइस को क्लिंग रैप पर रखें। उस पर वनीला आइसक्रीम की एक लेयर लगाएं और ऊपर आम के टुकड़े रखें।
4. फिर ऊपर से थोड़ा सा तैयार किया हुआ मसाला छिड़कें।
5. इसके बाद फिर से आइसक्रीम की एक लेयर लगाकर दूसरी ब्रेड स्लाइस से ढक दें।
6. इसे अच्छे से क्लिंग रैप में लपेटकर 10 मिनट के लिए फ्रीजर में रख दें।
7. जब यह सेट हो जाए, तो इसे बीच से काट लें।
8. ठंडा-ठंडा सर्व करें।

चॉकलेट राइस केक

चावल को उबालकर डार्क चॉकलेट के साथ पकाएं। ठंडा करके ब्लेंडर में चीनी, अंडे, तेल और बेकिंग पाउडर डालकर स्मूद बैटर बनाएं। मोल्ड में डालकर 180एष्ट पर 25-30 मिनट बेक करें। ऊपर से पाउडर शुगर डालें और सर्व करें।

पानी – 500 मिलीलीटर
चावल – 150 ग्राम
डार्क चॉकलेट – 150 ग्राम
चीनी – 100 ग्राम
पानी – 200 मिलीलीटर
अंडे – 2
तेल – 30 मिलीलीटर
बेकिंग पाउडर – 1 चम्मच
मक्खन – मोल्ड को ब्रश करने के लिए
पिसी हुई चीनी – सजाने के लिए

बनाने की विधि

1. एक पैन में 500 मिलीलीटर पानी उबालें और उसमें 150 ग्राम चावल डालें। इसे 8-10 मिनट तक उबालें।
2. गैस बंद करें और चावल को छान लें।
3. अब चावल को एक पैन में डालें और 150 ग्राम डार्क चॉकलेट मिलाएं। चॉकलेट पिघलने तक अच्छे से मिक्स और कुक करें।
4. गैस बंद करें और मिश्रण को 15 मिनट ठंडा होने दें।
5. ठंडा होने के बाद इसे ब्लेंडर में डालें। इसमें 100 ग्राम चीनी, 200 मिलीलीटर पानी, 2 अंडे, 30 मिलीलीटर तेल और 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डालकर स्मूद बैटर बना लें।
6. केक मोल्ड को मक्खन से ग्रीस करें और तैयार बैटर उसमें डालें।
7. ओवन को प्रीहीट करें और केक को 25-30 मिनट तक बेक करें।
8. बेक होने के बाद ऊपर से पिसी हुई चीनी छिड़कें और टुकड़ों में काट लें।
9. गरमा-गरम सर्व करें और आनंद लें।

गर्मियों में लीची से बनाएं ये लाजवाब चीजें, स्वाद के साथ ठंडक भी मिलेगी

गर्मियों का मौसम आते ही लोगों का मन ठंडा- ठंडा खाने को करता है। बाजार रसीली और मीठी लीची से भर जाते हैं। स्वाद में बेहतरीन और पानी से भरपूर लीची न सिर्फ शरीर को ठंडक पहुंचाती है, बल्कि दिनभर ताजगी का एहसास भी कराती है। ज्यादातर लोग इसे सीधे खाना पसंद करते हैं, लेकिन लीची से कई स्वादिष्ट और रिफ्रेशिंग रेसिपीज भी तैयार की जा सकती हैं। अगर आप इस समर कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, तो ये 5 टेस्टी लीची रेसिपीज जरूर बनाएं।

लीची शेक

गर्मियों में ठंडा-ठंडा लीची शेक पीने का मजा ही अलग होता है। इसे बनाने के लिए लीची का गूदा, ठंडा दूध, चीनी और बर्फ को मिक्सर में डालकर अच्छी तरह ब्लेंड करें। ऊपर से ड्राई फ्रूट्स डालकर सर्व करें। यह सवाद होने के साथ शरीर को इंस्टेंट एनर्जी भी देता है।

लीची आइसक्रीम

अगर आप घर पर आसान तरीके से आइसक्रीम बनाना चाहते हैं, तो लीची आइसक्रीम बेस्ट ऑप्शन है। इसके लिए लीची का गूदा, क्रीम और कंडेंस्ड मिल्क को मिलाकर फ्रीजर में जमने के लिए रख दें। कुछ घंटों बाद स्वादिष्ट होममेड लीची आइसक्रीम तैयार हो जाएगी।

लीची मॉकटेल

समर पार्टी के लिए लीची मॉकटेल एक परफेक्ट ड्रिंक है। इसे बनाने के लिए लीची जूस में सोडा, पुदीने की पत्तियां और बर्फ मिलाएं। इसका फ्रेश स्वाद शरीर को तुरंत तरोताजा कर देता है।

लीची कस्टर्ड

गर्मियों में कुछ मीठा और ठंडा खाने का मन हो, तो लीची कस्टर्ड एक बेहतरीन विकल्प है। इसे बनाने के लिए वनीला कस्टर्ड तैयार करें और उसमें ताजी लीची के कटे हुए टुकड़े मिला दें। फिर इसे कुछ देर फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दें। चाहें तो स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें सेब, अंगूर या आम जैसे दूसरे फल भी मिला सकते हैं। ठंडा-ठंडा लीची कस्टर्ड गर्मियों में ताजगी और मिठास का परफेक्ट कॉम्बिनेशन देता है।

लीची जेली

इसे घर पर बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। इसके लिए लीची के ताजे जूस में जिलेटिन या अगर-अगर मिलाकर कुछ देर के लिए सेट होने रखें। जब यह अच्छी तरह जम जाए, तो इसे ठंडा-ठंडा सर्व करें। इसका मीठा और फ्रेश स्वाद गर्मियों में ताजगी का एहसास कराता है और हर किसी को पसंद आता है।

कहानी

चालाक लोमड़ी की पोल खुल गई

आज हम सुंदरवन के घने जंगल की एक ऐसी मर्मस्पर्शी कहानी लेकर आए हैं, जहाँ एक बेहद चतुर और मीठी बातें करने वाली लोमड़ी ने अपनी झूठी अफवाहों से सीधे-सादे जानवरों को डरा दिया। आइए पढ़ते हैं कि कैसे एक छोटी सी गिलहरी की सूझबूझ से उस 'चालाक लोमड़ी की पोल खुल गई'।

सुंदरवन में सावन का महीना बीत चुका था और पेड़ों पर मीठे फल, रसीले जामुन और लाल गाजरों की बहार आई हुई थी। जंगल के सभी छोटे-बड़े जानवर सर्दियों के लिए भोजन इकट्ठा करने की तैयारी में जुटे थे। इसी जंगल के एक छोर पर 'झमहरू' नाम की एक लोमड़ी रहती थी। झमहरू को मेहनत करना बिल्कुल पसंद नहीं था; उसकी गृहस्थी दूसरों की कमाई पर डाका डालकर ही चलती थी। उसकी जुबान पर शहद घुला था, पर दिल में कपट का समंदर था।

एक दिन झमहरू ने बिना किसी परिश्रम के ढेर सारा भोजन हड़पने की एक तरकीब सोची। उसने चेहरे पर गहरी चिंता का मुखौटा लगाया और चौपाल के पास जाकर जोर-जोर से छाती पीटने लगी। उसकी आवाज सुनकर 'चीकू' खरगोश और 'भोला' हिरन वहाँ दौड़े चले आए।

झमहरू ने अपनी आँखें मटकाते हुए कहा, 'अरे ओ सीधे-सादे भाइयों! तुम लोग यहाँ मजे से फल जमा कर रहे हो, तुम्हें कुछ पता भी है? कल रात मैंने आसमान के तारों को टूटते देखा है। उत्तर दिशा से एक भयंकर आग का तूफ़ान आ रहा है, जो जंगल के सारे फल-सब्जियों को जलाकर राख कर देगा। अगर अपनी जान और भोजन बचाना है, तो अपना सारा जमा किया हुआ राशन मेरी गहरी और ठंडी गुफा में रख दो। मैं सुरक्षा की गारंटी लेती हूँ, बदले में बस कुल भोजन का एक-चौथाई हिस्सा मेरी सेवा के रूप में मुझे दे देना।'

चीकू खरगोश और भोला हिरन ठहरे सीधे-सादे जीव। वे झमहरू की इस मीठी और डरावनी बात में आ गए। डर के मारे उनके हाथ-पैर कांपने लगे। उन्होंने बिना सोचे-समझे अपनी मेहनत से इकट्ठा की हुई ताजा गाजरें, मीठे जामुन और मक्के के भुट्टे झमहरू की गुफा में पहुँचा दिए।

झमहरू मन ही मन अपनी अक्ल पर इतरा रही थी। अब उसे सर्दियों में बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं थी। वह दिन भर गुफा के भीतर बैठती, जानवरों के भोजन पर ऐश करती और उनका मजाक उड़ाती।

लेकिन कहते हैं ना कि पाप का घड़ा एक दिन जरूर भरता है। इसी जंगल में 'चुटकी' नाम की एक छोटी सी, चंचल गिलहरी भी रहती थी। चुटकी बहुत ही खोजी स्वभाव की थी। उसने देखा कि उत्तर दिशा से कोई तूफ़ान नहीं आ रहा है, बल्कि हवा तो बिल्कुल साफ़ और सुहानी है। उसे झमहरू की नीयत पर शक हो गया।

एक शाम, चुटकी चुपके से रेंगते हुए झमहरू की गुफा के पिछले रास्ते से अंदर घुस गई। गुफा के भीतर का नज़ारा देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। चालाक झमहरू चीकू खरगोश की गाजरें चबा रही थी और अकेले में ठहाके मारकर खुद से कह रही थी, 'वाह झमहरू! तेरी अक्ल का कोई जवाब नहीं। उन मूर्ख जानवरों को तूफ़ान का ऐसा डर दिखाया कि बिना हाथ-पैर हिलाए पूरी सर्दी का माल जमा हो गया। वे बाहर भूखे मरेंगे और मैं यहाँ रानी की तरह राज करूँगी!'

चुटकी ने अपनी आँखों से उसकी मक्कारी देख ली थी। वह बिना कोई आवाज किए गुफा से बाहर आई और उसने तुरंत जंगल के मुखिया 'गजराज' हाथी, चीकू और भोला को सारी सच्चाई बताई। पहले तो किसी को यकीन नहीं हुआ, पर चुटकी ने एक योजना बनाई।

अगली सुबह, चुटकी सभी जानवरों और मुखिया गजराज को लेकर गुफा के मुँह पर पहुँची और खुद गुफा के पिछले छेद से अंदर जाकर एक भारी पत्थर के पीछे छिप गई। चुटकी ने अपनी आवाज बदलकर गुफा के भीतर एक गूँजती हुई रहस्यमयी आवाज निकाली, 'ओ झमहरू लोमड़ी! मैं आसमान का वही तूफ़ान हूँ। तुमने जंगल के जानवरों से झूठ बोलकर उनका खाना चुराया है। अगर तुमने अभी सच नहीं उगला, तो मैं तुम्हारी गुफा को यहीं भस्म कर दूँगा!'

नकली तूफ़ान की कड़कड़ाती आवाज सुनकर झमहरू का घमंड हवा हो गया। वह डर के मारे थर-थर कांपने लगी और रोते हुए चिल्लाई, 'मुझे माफ़ कर दो आसमान के देवता! मुझसे बड़ी गलती हो गई। जंगल में कोई तूफ़ान नहीं आने वाला है। मैंने तो सिर्फ़ चीकू और भोला का भोजन हड़पने के लिए झूठ बोला था। सारा खाना सुरक्षित है, मुझे बख्श दो!'

झमहरू का यह इक़बालिया बयान सुनते ही गुफा के बाहर खड़ा हर जानवर सन्न रह गया। चीकू और भोला का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुँच गया। मुखिया गजराज ने अपनी भारी सूंड से गुफा के सामने का पत्थर हटाया और कड़कती आवाज में कहा, 'बाहर निकल झमहरू! आज तेरी चालाकी की पोल खुल गई है।'

पकड़े जाने पर झमहरू के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। सरेआम बेइज्जती होने के बाद उसे उसी वक्त सुंदरवन छोड़कर भागना पड़ा। सभी जानवरों को उनका भोजन वापस मिल गया और उन्होंने चुटकी गिलहरी की सूझबूझ का आभार व्यक्त किया।

संक्षिप्त समाचार

नेतन्याहू की धमकी: 'ईरान को किसी भी हाल में परमाणु हथियार नहीं रखने देंगे, चाहे शांति समझौता हो या नहीं'

तेल अवीव, एजेंसी। इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान को किसी भी

हाल में परमाणु हथियार नहीं रखने दिए जाएंगे, चाहे शांति समझौता हो या नहीं। उनका यह बयान तब आया है, जब पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच एक समझौते पर सहमति बनी है। नेतन्याहू ने कहा कि उनका पूरा राजनीतिक जीवन ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लक्ष्य पर केंद्रित रहा है। उन्होंने इसे अपने जीवनभर की जिम्मेदारी बताया। उन्होंने साफ कहा कि जब तक वह प्रधानमंत्री हैं, ईरान को परमाणु हथियार नहीं हासिल करने देंगे। उधर, अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ईरान के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें भविष्य की बातचीत और सहयोग का ढांचा तय किया गया है। इस ढांचे में ईरान के सहयोग के आधार पर उस पर लगे प्रतिबंधों में राहत और आर्थिक संबंध बढ़ाने की संभावना है, खासकर अगर वह परमाणु शर्तों और क्षेत्रीय सुरक्षा नियमों का पालन करेगा। अमेरिका का कहना है कि यह समझौता ईरान को अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था से जोड़ने का रास्ता खोल सकता है, अगर वह अपनी प्रतिबद्धताओं का पालन करता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे एक 'बहुत मजबूत दस्तावेज' बताया है। उन्होंने कहा है कि इसका पूरा विवरण जल्द सार्वजनिक किया जाएगा। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी पुष्टि की है कि डिजिटल हस्ताक्षर पहले ही हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधों में राहत तभी मिलेगी, जब ईरान अपने संवर्धित यूरेनियम भंडार को कम करेगा और आवश्यक सत्यापन व्यवस्था (परमाणु हथियारों की जांच) को स्वीकार करेगा। स्विट्जरलैंड और अन्य देश इस समझौते के औपचारिक हस्ताक्षर समारोह की तैयारी में जुटे हैं, जो इस सप्ताह जिनेवा में होने की संभावना है।

गहरी खाई में गिरी यात्रियों से भरी बस, 30 से अधिक लोगों की दर्दनाक मौत

अदीस अबाबा, एजेंसी। इथियोपिया के उत्तरी अमहारा क्षेत्र में एक भीषण हादसा हो गया है। इस हादसे में कम से कम 31 लोगों की मौत हो गई है और दर्जनों लोग घायल हैं। ये इलाका संघर्ष से प्रभावित है और हादसे के बाद आपातकालीन सेवाओं में देरी से स्थिति और गंभीर हो गई। बता दें कि ये हादसा सोमवार की सुबह उस समय हुई जब एक खचाखच भरी बस डेसी क्षेत्र से राजधानी अदीस अबाबा की तरफ जा रही थी। पुलिस ने बताया कि इसी दौरान बस अचानक सड़क से फिसल गई और एक गहरी खाई में जा गिरी। हादसे के बाद आपातकालीन सेवाओं की प्रतिक्रिया में देरी की वजह भी सामने ई है। जिस इलाके में ये हादसा हुआ, वहां बुनियादी ढांचे की भारी कमी है और एम्बुलेंस सेवाओं का भी अभाव है। यही कारण है कि घायलों को निजी वाहनों में अस्पताल ले जाना पड़ा। इस दौरान घायलों की हालत और बिगड़ने की आशंका है। इथियोपिया में क्यों होते हैं ज्यादा सड़क हादसे? इथियोपिया दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां सड़क दुर्घटनाओं और उनसे होने वाली मौतों की दर काफी अधिक है। इसके पीछे कई कारण जिम्मेदार हैं, जिनमें खराब सड़क ढांचा, वाहनों की जर्जर स्थिति और यातायात नियमों का प्रभावी ढंग से पालन न होना प्रमुख हैं। देश के कई ग्रामीण और पहाड़ी इलाकों में सड़क नेटवर्क पर्याप्त विकसित नहीं है। संकरी और खराब सड़कों के कारण वाहन अक्सर नियंत्रण खो देते हैं और गहरी खाइयों में गिर जाते हैं। इसके अलावा, गलत तरीके से मोड़ लेना, खतरनाक ओवरटेकिंग करना, वाहनों के बीच पर्याप्त दूरी न रखना और निर्धारित गति सीमा से अधिक रफ्तार में वाहन चलाना आम समस्याएं हैं। बड़ी संख्या में पैदल यात्रियों की मौत हादसों की एक बड़ी वजह बसों और ट्रकों की खराब तकनीकी स्थिति भी है। कई वाहन क्षमता से अधिक यात्रियों या माल को ढोते हैं, जिससे दुर्घटनाओं का जोखिम बढ़ जाता है। बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण पैदल यात्रियों की सुरक्षा भी प्रभावित होती है।

समझौते के बाद भी अमेरिका के हाथ खाली

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता हो गया है लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि इस समझौते के बाद भी अमेरिका के हाथ खाली हैं और अमेरिका अपने कोई भी लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाया है। विशेषज्ञ मानते हैं कि दोनों देशों के बीच शांति समझौता केवल युद्ध की पूर्व यथास्थिति की बहाली है। अगले 60 दिनों में होने वाली बातचीत तय करेगी कि अमेरिका को इस युद्ध और तबाही से कुछ हासिल होगा भी या नहीं। यह बात सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के पश्चिम एशिया प्रोग्राम के वरिष्ठ फेलो विल टॉडमैन ने कही।

टॉडमैन के अनुसार, इस समझौते का मुख्य उद्देश्य युद्धविराम और होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलना है, जिससे स्थिति अमेरिका और इस्राइल द्वारा ईरान पर हमले से पहले जैसी ही होगी। उन्होंने कहा, 'इस समय तक अमेरिका, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा युद्ध शुरू करते समय तय किए गए किसी भी प्रमुख लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाया है।'

अमेरिका और ईरान रविवार को होर्मुज जलडमरूमध्य को दोबारा खोलने पर सहमत हुए। इस कदम से दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्गों में से एक के जरिए तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने की उम्मीद है। हालांकि समझौते का पूरा विवरण अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। ईरान ने संकेत दिया है कि औपचारिक हस्ताक्षर समारोह के बाद ही समझौते को लागू किया जाएगा। औपचारिक समारोह शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में आयोजित होगा।

ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर रोक की कोई बात नहीं

समझौते में ईरान के उच्च स्तर पर संवर्धित यूरेनियम भंडार और उसके परमाणु कार्यक्रम से जुड़े लंबित मुद्दों पर बातचीत के लिए 60 दिनों की समय-सीमा भी तय की गई है। अमेरिका और इस्राइल ने 28 फरवरी को ईरान पर सैन्य कार्रवाई शुरू की थी। उन्होंने कहा कि अगले 60 दिनों की बातचीत यह तय करेगी कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम के संबंध में अमेरिका अपने लक्ष्यों को हासिल कर पाता है या नहीं।

टॉडमैन का मानना है कि ईरान परमाणु मुद्दों पर बड़े समझौते करने को तैयार नहीं होगा और उसे लगता है कि समय उसके पक्ष में है। उन्होंने कहा, 'ईरान संभवतः वार्ताओं को लंबा खींचने की कोशिश करेगा क्योंकि उसे नहीं लगता कि राष्ट्रपति ट्रंप मध्यावधि चुनावों से पहले फिर से सैन्य कार्रवाई करेंगे। ऐसे में अमेरिका के लिए अपने उद्देश्यों को हासिल करना कठिन होगा।' टॉडमैन के मुताबिक समझौते के बाद ईरान के पश्चिम एशिया में और अधिक आर्थिक रूप से एकीकृत होने की संभावना है। अरब खाड़ी देश तेहरान के साथ आर्थिक परस्पर निर्भरता बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं ताकि भविष्य में किसी संभावित हमले को रोका जा सके। अमेरिका को उठाना पड़ा भारी रणनीतिक नुकसान विशेषज्ञ के अनुसार तीन महीने से अधिक चले युद्ध ने अमेरिका के अपने प्रमुख क्षेत्रीय साझेदारों और सहयोगियों के साथ संबंधों को भी नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि अरब खाड़ी देशों को महसूस हुआ कि अमेरिका ने युद्ध से पहले और उसके दौरान उनकी चिंताओं और हितों को पर्याप्त महत्व नहीं दिया। इसी कारण ये देश अपनी सुरक्षा साझेदारियों में विविधता लाने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं ताकि अमेरिका पर निर्भरता कम की जा सके। टॉडमैन ने कहा, 'यह संभावना कम है कि राष्ट्रपति ट्रंप या भविष्य का कोई अमेरिकी प्रशासन इस भरोसे की कमी को दूर करने के लिए पर्याप्त राजनीतिक पूंजी खर्च करेगा। ऐसे में अमेरिका और अरब खाड़ी देशों के संबंध धीरे-धीरे कमजोर हो सकते हैं।'

ट्रंप बोले- ईरान को 300 मिलियन डॉलर भुगतान का दावा फर्जी

वॉशिंगटन डीसी, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को एक बड़ा दावा किया। उन्होंने बताया कि ईरान सहमत हो गया है कि वह अब कभी भी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। ट्रंप ने ईरान के साथ एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ट्रंप ने उन खबरों को पूरी तरह गलत बताया जिनमें कहा गया था कि अमेरिका इस शांति समझौते के बदले ईरान को 300 मिलियन डॉलर देगा। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा 'ईरान ने परमाणु हथियार न रखने पर सहमति जताई है! साथ ही, यह खबर कि अमेरिका ईरान को 300 मिलियन डॉलर दे रहा है, फर्जी खबर है, जिसे डेमोक्रेट्स ने फैलाया है' ट्रंप ने साफ किया कि उनकी सरकार ने यह पक्का कर लिया है कि ईरान परमाणु हथियार विकसित न कर पाए। यह नया समझौता भविष्य के रिश्तों के लिए एक रास्ता तैयार करता है। इसके तहत ईरान पर लगे प्रतिबंधों को हटाना इस बात पर निर्भर करेगा कि वह परमाणु जांच में कितना सहयोग करता है। साथ ही ईरान को क्षेत्रीय सुरक्षा के वादे भी पूरे करने होंगे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी ट्रंप के इस कदम का समर्थन किया। वेंस ने कहा कि ट्रंप की शांति की कोशिशें सफल रही हैं। उन्होंने कहा कि ईरान को परमाणु ताकत बनने से रोकना ही इस समझौते का सबसे बड़ा लक्ष्य है।

निर्णायक होगी 60 दिन की अवधि

पश्चिम एशिया: परमाणु मुद्दे से बड़ी है जंग रोकने की अग्निपरीक्षा

वाशिंगटन/तेहरान, एजेंसी। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते का जो ढांचा तय हुआ है, उसको पश्चिम एशिया में स्थायी शांति बहाली की कसौटी पर परखने के लिए 60 दिन की अवधि तय की गई है। यहां तक पहुंचने के लिए अमेरिका ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम के मुद्दे पर अपने रुख को काफी नरम किया है। ईरान पर समझौते के लिए सबसे पहले परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह बंद करने की शर्त नहीं थोपी गई है। बल्कि बातचीत के लिए उसे पूरा समय दिया। जाहिर तौर पर पश्चिम एशिया के मौजूदा संकट बीच ईरान का परमाणु कार्यक्रम एक बड़ा मुद्दा रहा है। लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि समझौते से पुख्ता समाधान तक पहुंचने के लिए तय की गई 60 दिन की अवधि परमाणु मुद्दे से कहीं ज्यादा जंग को स्थायी रूप से रोकने की अग्निपरीक्षा है। अगले दो महीनों में तय होगा कि अमेरिका और ईरान के बीच परस्पर भरोसा कितना मजबूत होता है। समझौता मानने से इन्कार कर चुका इस्राइल आगे क्या रुख अपनाता है। बम, ड्रोन और मिसाइलों के इस्तेमाल में कितना संयम बरता जाता है, और समझौते की शर्तों का कितनी शिद्दत से पालन किया जाता है, क्योंकि यही पश्चिम एशिया में शांति की राह तय करने में निर्णायक साबित होगा।

चार बातों पर टिका समाधानत इस्राइल की आक्रामक कार्रवाइयों पर अमेरिका किस हद तक नियंत्रण रख पाता है।

अमेरिकी नौसेना ईरानी समुद्री क्षेत्र के पास अपनी नाकेबंदी कितनी तेजी से हटाती है।

यूएस-ईरान समझौते के बाद होर्मुज से जल्द निकलेंगे 34 भारतीय जहाज, करोड़ों किसानों को मिलेगी बड़ी राहत

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता हो गया है। समझौते के तहत होर्मुज जलडमरूमध्य से जहाजों की मुक्त आवाजाही सुनिश्चित होगी। इसका असर भी दिखना शुरू हो गया है। दरअसल तरल प्राकृतिक गैस (एलएनजी) ला रहे भारतीय टैंकर दिशा ने सुरक्षित होर्मुज जलडमरूमध्य पार कर लिया है। भारत आ रहे 34 अन्य जहाजों के भी जल्द होर्मुज पार करने की उम्मीद है। ये जहाज पश्चिम एशिया संकट के चलते होर्मुज में फंसे हैं।

होर्मुज में फंसे 34 जहाजों में से 16 जहाज ऐसे हैं, जो फर्टिलाइजर लेकर भारत आ रहे हैं। इन 16 जहाजों में से 8 पर यूरिया, चार पर डाइ-अमोनियम फॉस्फेट और तीन पर सल्फर और एक पर अमोनिया लदा है। अगर समझौते के तहत सबकुछ सही रहता है और होर्मुज खुलता है तो जल्द ही भारत के करोड़ों किसानों को खेती के लिए फर्टिलाइजर मिल सकते हैं। हालांकि अभी हालात सामान्य होने में वक्त लग सकता है। तुरंत पूर्ण राहत के आसार नहीं पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान ऊर्जा केंद्रों को निशाना बनाया गया। पश्चिम एशिया की कई अहम रिफाइनरियां और गैस प्लांट हमलों में बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं।

जिससे युद्ध समाप्त होने के बाद भी आपूर्ति सामान्य होने में कई महीनों का वक्त लग सकता है। कतर का रास लफ्फान प्लांट हमले में बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है और वहां से ईंधन आपूर्ति सामान्य होने में कई महीने लग सकते हैं। भारत के इस गैस प्लांट से एलपीजी आपूर्ति का कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसे में हालात सामान्य होने में अभी वक्त लगेगा।

भारत अपनी जरूरत का 88 प्रतिशत कच्चा तेल आयात करता है। इसमें से करीब आधा हिस्सा पश्चिम एशिया से ही आपूर्ति होता है। साथ ही भारत के कुल आयात की 60 प्रतिशत से ज्यादा एलएनजी भी होर्मुज से गुजरकर भारत आती है। यही वजह है कि पश्चिम एशिया संकट के चलते होर्मुज जलडमरूमध्य बंद होने से भारत को होने वाली तेल और गैस की आपूर्ति बाधित हो गई। होर्मुज से पार हुआ दिशा टैंकर 18 जून तक भारत आ सकता है और इस पर 62,370 टन एलएनजी है।

आतंकवाद के खिलाफ साथ आए भारत-स्लोवाकिया, शिक्षा-रोजगार समेत 11 क्षेत्रों में हुए बड़े करार

ब्रातिस्लावा, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्लोवाकिया की ऐतिहासिक यात्रा के दौरान भारत और स्लोवाकिया ने अपने रिश्तों को एक नई ऊंचाई दी है। दोनों देशों ने अपने संबंधों को 'व्यापक साझेदारी' में बदल दिया है। विदेश मंत्रालय के सचिव सिबी जॉर्ज ने एक मीडिया वार्ता में इस यात्रा की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह यात्रा दोनों देशों के बीच सहयोग को एक नई गति देगी।

इस यात्रा का सबसे बड़ा फैसला आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ना है। भारत और स्लोवाकिया ने आतंकवाद विरोधी सहयोग के लिए एक 'संयुक्त कार्य समूह' बनाने पर सहमति जताई है। साथ ही दोनों देशों ने सीमा पर आतंकवाद सहित इसके सभी रूपों की कड़ी निंदा की। दोनों नेताओं ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की भी निंदा की।

इसके अलावा, दोनों देशों के बीच 'कांसुलर संवाद तंत्र' भी शुरू किया जाएगा। स्लोवाकिया ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का भी समर्थन किया है। स्लोवाकिया का मानना है कि सुरक्षा परिषद का विस्तार होना चाहिए और इसमें भारत जैसे देशों को जगह मिलनी चाहिए। साथ ही स्लोवाकिया के पीएम फिको ने भारतीय कारोबारियों को स्लोवाकिया में निवेश करने का खुला न्योता दिया।

साल 1993 में स्लोवाकिया की आजादी के बाद यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट

फिको के साथ विस्तार से बातचीत की। उन्होंने राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मुलाकात की। इन नेताओं ने आपसी हितों के साथ-साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी अपने विचार साझा किए। इसमें यूक्रेन संघर्ष, पश्चिम एशिया के हालात और भारत-यूरोपीय संघ के रिश्तों जैसे अहम विषय शामिल थे।

दोनों नेताओं ने भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते पर भी चर्चा की। सिबी जॉर्ज ने कहा कि इस समझौते से स्लोवाकिया जैसे यूरोपीय देशों के साथ भारत के जुड़ाव को मजबूती मिली है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में सुधारों की जरूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र को आज की हकीकत के हिसाब से बदलना चाहिए क्योंकि यह फिलहाल पुराने समय में अटका हुआ है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और शांति अभियानों में इसका बड़ा योगदान है, इसलिए इसे सुरक्षा परिषद में स्थायी जगह मिलनी चाहिए।

इस यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर हुए। इनमें श्रम प्रवास, उच्च शिक्षा, शोध और ऑडियो-विजुअल सहयोग शामिल हैं। इन समझौतों का मकसद दोनों देशों के बीच छात्रों और पेशेवरों के आने-जाने, शैक्षणिक आदान-प्रदान और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना है।

प्रधानमंत्री मोदी को मिल सर्वोच्च राजकीय सम्मान

एक विशेष सम्मान के तौर पर, राष्ट्रपति पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च राजकीय सम्मान 'ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास' से नवाजा। यह सम्मान भारत और स्लोवाकिया के रिश्तों को मजबूत करने में उनके खास योगदान के लिए दिया गया है।

● देशों ने अपने रिश्तों को अब 'व्यापक साझेदारी' का दर्जा दिया है

पीएम बोले- ब्रातिस्लावा में बनारस का कनेक्शन! कलाकारों की सराहना कर कही खास बात

ब्रातिस्लावा, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्लोवाकिया की अपनी दो दिनों की ऐतिहासिक यात्रा पूरी कर ली है। साल 1993 में स्लोवाकिया की आजादी के बाद यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला दौरा था। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, शिक्षा और रोजगार जैसे कई अहम क्षेत्रों में बड़े समझौते हुए। दोनों देशों ने अपने रिश्तों को अब 'व्यापक साझेदारी' का दर्जा दिया है।

अपनी इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी के साथ राजधानी ब्रातिस्लावा के राष्ट्रपति महल में एक खास प्रदर्शनी देखी। इस प्रदर्शनी का मुख्य केंद्र भारत का प्राचीन और पवित्र शहर वाराणसी (बनारस) था। इसमें उन स्लोवाकियाई कलाकारों की कलाकृतियां शामिल थीं, जिन्होंने हाल ही में वाराणसी की यात्रा की थी। कलाकारों ने अपनी कला के जरिए बनारस की खूबसूरती

और वहां की संस्कृति को कैनवास पर उतारा था।

प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर इस अनुभव को साझा करते हुए इसे 'ब्रातिस्लावा में बनारस का जुड़ाव' बताया। पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा 'ब्रातिस्लावा में बनारस से जुड़ाव! कल ब्रातिस्लावा के राष्ट्रपति भवन में, राष्ट्रपति पेलेग्रिनी और मैंने वाराणसी पर केंद्रित एक आकर्षक प्रदर्शनी देखी, जिसमें उन स्लोवाक कलाकारों की कृतियां शामिल थीं जिन्होंने हाल ही में वाराणसी का दौरा किया था। कला और संस्कृति में लोगों को करीब लाने की अद्भुत क्षमता होती है। इस प्रदर्शनी में प्रदर्शित सभी कलाकारों को मेरी हार्दिक बधाई।' यह प्रदर्शनी दिखाती है कि भारत और स्लोवाकिया के बीच केवल राजनीतिक और व्यापारिक रिश्ते ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक जुड़ाव भी गहरा हो रहा है। स्लोवाकिया के कलाकारों ने अपनी कला के जरिए बनारस की विरासत को यूरोप में पेश किया। इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च राजकीय सम्मान से भी नवाजा गया, जो दोनों देशों की बढ़ती दोस्ती का प्रतीक है।

नेतन्याहू बोले- गाजा-लेबनान-सीरिया में तैनात रहेगी आईडीएफ, ट्रंप ने समझौते को बताया शक्तिशाली दस्तावेज

यरुशलम, एजेंसी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार नहीं रखने के लिए सहमत हो गया है। उन्होंने यह भी साफ किया कि अमेरिका से ईरान को 300 मिलियन डॉलर देने की बात पूरी तरह झूठी खबर है। ट्रंप ने आरोप लगाया कि यह गलत खबर उनके विरोधियों ने फैलाई है। फलस्तीन और इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआईसी) ने यरूशलम में सोमालीलैंड के दूतावास खुलने की निंदा की है और इसे अंतरराष्ट्रीय कानून का 'स्पष्ट उल्लंघन' बताया है। यह मामला तब सामने आया, जब सोमालिया से अलग हुए क्षेत्र सोमालीलैंड के राष्ट्रपति अब्दिरहमान मोहम्मद अब्दुल्लाही ने सोमवार को अपने पहले इस्राइल दौरे के दौरान दूतावास का उद्घाटन किया।

पिछले वर्ष दिसंबर में इस्राइल ने सोमालीलैंड को मान्यता दी थी, जिसकी अरब लीग, ओआईसी और अफ्रीकी संघ ने आलोचना की थी। दौरे के दौरान अब्दुल्लाही ने इस्राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच रणनीतिक सहयोग को लेकर एक संयुक्त समझौते पर हस्ताक्षर किए।

जल्द सार्वजनिक किया जाएगा समझौते का विवरण: ट्रंपत्न अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते का पूरा विवरण जल्द ही सार्वजनिक किया जाएगा। उन्होंने इसे 'बहुत शक्तिशाली दस्तावेज' बताया। यह बयान

उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ एवियन में हुई द्विपक्षीय बैठक के दौरान दिया, जो जी7 शिखर सम्मेलन के दौरान आयोजित की गई थी।

ट्रंप ने कहा कि दस्तावेज संभवतः औपचारिक हस्ताक्षर समारोह के बाद जारी किया जाएगा, जिसकी उम्मीद इस सप्ताह के अंत में की जा रही है। जब उनसे पूछा गया कि समझौता कब सार्वजनिक होगा, तो उन्होंने कहा कि इसे जल्द जारी किया जाएगा क्योंकि यह एक अहम दस्तावेज है।

इस बीच, सीएनएन के अनुसार एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने पुष्टि की है कि पूरा समझौता अगले 24 से 48 घंटों के भीतर सार्वजनिक कर दिया जाएगा। अधिकारी ने कहा कि ट्रंप प्रशासन की नीति पूरी पारदर्शिता रखने की है और दस्तावेज को सार्वजनिक रूप से जारी किया जाएगा। इस्राइल की सेना गाजा, लेबनान और सीरिया में तैनात रहेगी: नेतन्याहू इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमवार को कहा कि इस्राइली सेना गाजा, लेबनान और सीरिया में 'जब तक जरूरत होगी, तब तक' तैनात रहेगी। यह बयान ऐसे समय आया, जब कुछ घंटे पहले ही ईरान और अमेरिका के बीच पश्चिम एशिया में युद्ध खत्म करने को लेकर समझौते की घोषणा की गई थी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेतन्याहू ने कहा, हमने इस्राइल के चारों ओर गहरे सुरक्षा क्षेत्र बनाए हैं। हमने यह गाजा, लेबनान और सीरिया में किया है। उन्होंने आगे कहा, और मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम अपने देश की सुरक्षा के लिए इन सुरक्षा क्षेत्रों में उतनी ही देर तक रहेंगे, जब तक आवश्यकता होगी। ईरान की सेना ने कहा कि अमेरिका के साथ समझौता लागू होने के बावजूद वह पूरी तरह सतर्क स्थिति में बनी रहेगी। ईरानी सेना के एक प्रवक्ता ने बताया कि इस दौरान सशस्त्र बलों की तैयारियों का स्तर पहले से भी अधिक बनाए रखने की योजना है। उन्होंने कहा कि समझौते की अवधि में देश अपनी रक्षा क्षमताओं को और मजबूत करेगा। यह जानकारी ईरान की समाचार एजेंसी फार्स के हवाले से दी गई है।

नेतन्याहू बोले- गाजा-लेबनान-सीरिया में तैनात रहेगी आईडीएफ ट्रंप ने समझौते को बताया शक्तिशाली दस्तावेज

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सहयोगी देशों से समर्थन हासिल करने की उम्मीद के साथ जी7 शिखर सम्मेलन मेंपहुंचे हैं। हालांकि उनके रवैये को लेकर यह सवाल भी उठ रहे हैं कि वह पूरी तरह सहयोगी भावना से बातचीत करेंगे या नहीं। रासमुसेन कंसल्टेंसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) और उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) के पूर्व नीति योजनाकार फैब्रिस पोथियर के अनुसार, ट्रंप के पास ईरान युद्ध को लेकर किसी तरह का राजनीतिक समाधान मौजूद है, इसलिए वह अब यूरोपीय और जी7 देशों का पूरा समर्थन चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका चाह सकता है कि होर्मुज जलडमरूमध्य को व्यापार के लिए खुला रखने में उसे परिचालन स्तर पर भी सहयोग मिले। पोथियर ने अल जजीरा से बातचीत में कहा कि यह स्थिति जी7 देशों और अमेरिका के बीच पिछले छह महीनों से चले आ रहे तनाव के बाद संबंधों में सुधार का मौका बन सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि ट्रंप के पास जी7 में शामिल होने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

सौरव गांगुली ने सोशल मीडिया पेज के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर

कोलकाता (एजेंसी)। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के प्रेसिडेंट सौरव गांगुली ने कोलकाता पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के मुताबिक उन्होंने आरोप लगाया कि 'सौरव गांगुली फैंस' नाम का एक फेसबुक पेज उनकी इमेज खराब करने की कोशिश कर रहा है और मीडिया प्लेटफॉर्म स्पोर्टजविकी का भी जिक्र किया है। ठाकुरपुकुर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। गांगुली ने कहा कि पेज लगातार ऐसे पोस्ट शेयर कर रहा था जिनका मकसद मेरी रेप्युटेशन खराब करना और जनता के बीच नेगेटिव इमेज बनाना है। गांगुली ने अपनी शिकायत में कहा, 'एक पब्लिक फिगर होने के नाते मैं समझता हूं कि राय और आलोचना पब्लिक लाइफ का हिस्सा हैं, हालांकि, मेरी छवी को नुकसान पहुंचाने के इरादे से गुमराह करने वाला, बदनाम करने वाला और नुकसान पहुंचाने वाला कंटेंट फैलाना मंजूर नहीं है और इसके लिए सही कानूनी कार्रवाई की जरूरत है।' उन्होंने आगे कहा, 'इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कृपया इस पेज को चलाने वाले लोगों/ग्रुप के खिलाफ मेरी शिकायत दर्ज करें और लागू कानूनों के अनुसार जरूरी कार्रवाई करें।'
गांगुली पिच पर अपने पूरे समय अपने खास लीडरशिप स्टाइल के लिए जाने जाते थे। 1996 की गर्मियों में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया जिससे उन्हें 'दादा' निकनेम मिला। लॉर्ड्स में अपने पहले टेस्ट में शतक बनाने के बाद वे जल्द ही सुर्खियों में आ गए और 'कोलकाता के प्रिंस' ने फिर दूसरे टेस्ट में भी शतक बनाया और इतिहास में अपनी पहली दो पारियों में सेंचुरी बनाने वाले तीसरे बैट्समैन बन गए। सन् 2000 में टीम इंडिया कैंप एक मैच-फिक्सिंग स्कैंडल में फंस गया। इसके बाद गांगुली को टीम का कप्तान बनाया गया, जहां उन्होंने नए टैलेंट को तैयार करना शुरू किया। गांगुली ने भारत को पहली बार 2000 आईसीसी नॉकआउट ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचाया। टीम इंडिया ने एक और बड़ी उपलब्धि 2001 में हासिल की जब गांगुली की लीडरशिप वाली टीम ने बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हराया। स्टीव वॉ की कप्तानी वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम ने भारत को सीरीज में फॉलोऑन के लिए चैलेंज किया, लेकिन वीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ ने भारतीय क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी वापसी की। पूर्व भारतीय कप्तान का सबसे यादगार पल निश्चित रूप से वह था जब उन्होंने 2002 में नेटवेस्ट ट्रॉफी के फाइनल में इंग्लैंड को हार के मुंह से बचाते हुए लॉर्ड्स की बालकनी पर अपनी शर्ट उतार दी थी। गांगुली ने 2003 में भारत को वर्ल्ड कप फाइनल में भी पहुंचाया, जहां वे चैंपियनशिप गेम में ऑस्ट्रेलिया से बहुत कम अंतर से हार गए थे। 2004 में उन्होंने पाकिस्तान में एक वनडे और टेस्ट सीरीज भी देखी। टेस्ट सीरीज में जीत भारत की पाकिस्तानी धरती पर पहली जीत थी। 'दादा' की 2005-6 में तत्कालीन कोच ग्रेग चैपल के साथ एक बहस भी हुई थी, जब 'प्रिंस ऑफ कोलकाता' को टीम इंडिया टीम से बाहर कर दिया गया था।

स्मृति मंधाना सबसे प्रभावशाली खेल हस्तियों में शामिल, सूची में इकलौती भारतीय एथलीट

नईदिल्ली (एजेंसी)। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उपकप्तान स्मृति मंधाना ने अपने शानदार करियर में एक और बड़ी उपलब्धि जोड़ ली है। प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने उन्हें वर्ष 2026 की 100 सबसे प्रभावशाली खेल हस्तियों की सूची में शामिल किया है। खास बात यह है कि इस सूची में जगह बनाने वाली वह एकमात्र भारतीय एथलीट हैं।

दुनिया के दिग्गज खिलाड़ियों के बीच मिली जगह – टाईम की इस प्रतिष्ठित सूची में स्मृति मंधाना ने फुटबॉल के सुपरस्टार लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, टेनिस स्टार कार्लोस अल्काराज, बास्केटबॉल खिलाड़ी विक्टर वेम्बनयामा, गोल्फर रोरी मैक्लरॉय, फ्रीस्की खिलाड़ी एलीन गु और फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो जैसी वैश्विक खेल हस्तियों के साथ स्थान हासिल किया है।

क्यों चुनी गई स्मृति मंधाना – टाईण मैगजीन ने स्मृति मंधाना को शामिल करने के पीछे उनके लगातार शानदार प्रदर्शन और नेतृत्व क्षमता को अहम वजह बताया। मंधाना ने महिला प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) को 2025 और 2026 में लगातार खिताब दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा, भारत की ऐतिहासिक आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 जीत में भी उनका योगदान बेहद अहम रहा था।

फीफा वर्ल्ड कप में 68 साल बाद हुआ ऐसा

एक दिन में खेले गए चारों मैच रहे ड्रॉ

लॉस एंजिल्स (एजेंसी)। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के पांचवें दिन का आखिरी मैच ईरान और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया. लॉस एंजिल्स स्टेडियम में ग्रुप त का ये रोमांचक मैच 2-2 से ड्रॉ पर समाप्त हुआ. जिससे दोनों टीमों को एक-एक अंक शेयर करना पड़ा। यह मैच न केवल मैदान पर रोमांचक खेल के लिए यादगार रहेगा, बल्कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 के पांचवें दिन खेले जाने वाले आखिरी मैच के तौर रिकॉर्ड बुक में भी दर्ज करा दिया, क्योंकि वो दिन का चौथा ड्रा मैच था. जिसके साथ टूर्नामेंट के इतिहास में एक दिन में चार मैच ड्रॉ होने का अनोखा रिकॉर्ड बन गया। ऐसा फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में केवल दूसरा बार हुआ है. इससे पहले ऐसी घटना 68 साल पहले 1958 में स्वीडन में हुए टूर्नामेंट में देखने को मिला था. जब 15 जून के दिन खेले गए चार मैच ड्रॉ पर समाप्त हुए थे. उन मैच का नतीजा नीचे देख सकते हैं।

फीफा वर्ल्ड कप 1958 (15 जून)

- स्वीडन बनाम वेल्स (0-0)
- इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया (2-2)
- पराग्वे बनाम यूगोस्लाविया (3-3)
- वेस्ट जर्मनी बनाम नॉर्दर्न आयरलैंड (2-2)

- **68 साल बाद फिर हुआ ऐसा** – अब 68 साल बाद दूसरी बार ऐसा हुआ है जब फीफा वर्ल्ड कप 2026 के पांचवें दिन यानी कि 15 जून को खेले गए वर्ल्ड कप के चार मुकाबले बिना किसी विजेता के समाप्त हुए. दिन के पहले मैच में केप वर्डे ने स्पेन को बिना किसी गोल के ड्रॉ पर रोका. बेल्जियम और मिस्र का मैच 1-1 से ड्रॉ रहा, जबकि सऊदी अरब और उरुग्वे के बीच भी मुकाबला 1-1 से ड्रॉ रहा और दोनों ने अंक बांटे. दिन के आखिरी मैच में ईरान और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा।

भारत ने जापान को हराकर नेशंस कप के सेमीफाइनल में बनाई जगह

ऑकलैंड (एजेंसी)। कप्तान सलीमा टेटे और लालरेम्सियामी के गोल की मदद से भारतीय महिला हॉकी टीम ने मंगलवार को यहां जापान को 2-1 से हराकर एफआईएच नेशंस कप के सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। यह टूर्नामेंट में भारत की दूसरी जीत थी। उसने अपने पहले मैच में अमेरिका को हराया था। इस टूर्नामेंट की विजेता टीम अगले सत्र में एफआईएच प्रो लीग में खेलेगी। भारत पिछले सत्र में इस टूर्नामेंट से बाहर हो गया था।

भारत के लगातार दूसरी जीत से छह अंक हो गए हैं और उसने अंतिम चार में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली है। भारत ने तीसरे क्वार्टर में स्कोरिंग की शुरुआत की, जब फॉरवर्ड खिलाड़ियों के लगातार दबाव बनाने के बाद सलीमा टेटे ने 33वें मिनट में गोल दागा। भारत की बढ़त हालांकि ज्यादा देर तक नहीं रही और जापान ने इसके दो मिनट बाद ही ऐ हिरमित्सु के गोल से स्कोर बराबर कर दिया। लालरेम्सियामी ने हालांकि 49वें मिनट में गोल दागा जो आखिर में निर्णायक साबित हुआ।

जापान ने अंतिम क्षणों में आक्रामक खेल दिखाया लेकिन भारत ने उसके हमलों को नाकाम करते हुए जीत हासिल की। यह मैच मिडफील्डर ज्योति के लिए भी एक यादगार अवसर था, जिन्होंने सीनियर स्तर पर अपना 100वां अंतरराष्ट्रीय मैच खेला। पहले हाफ में काफी करीबी मुकाबला रहा, जिसमें दोनों टीमों ने मौके बनाए लेकिन मध्यांतर से पहले कोई भी गोल करने में असफल रही।

नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप में चंडीगढ़ का जलवा, अंडर-12 बॉयज ने जीता गोल्ड

देहरादून (एजेंसी)। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आयोजित पहली नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप में चंडीगढ़ की अंडर-12 बॉयज टीम ने सभी मुकाबले जीतकर गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया. जबकि, लड़कियों की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से देहरादून के हिमाद्री आइस स्केटिंग रिंक में आयोजित की जा रही पहली नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप में चंडीगढ़ की टीम का दबदबा देखने को मिला. अंडर-12 वर्ग में चंडीगढ़ के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किए। उन्होंने न केवल पदक जीते बल्कि, पूरे टूर्नामेंट में अपनी प्रतिभा और मेहनत का लोहा भी मनवाया. जहां अंडर-12 बॉयज टीम ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया, तो वहीं अंडर-12 गर्ल्स टीम ने कांस्य पदक जीतकर चंडीगढ़ का गौरव बढ़ाया।

बेमिसाल रहे अंडर-12 बॉयज, जीते सभी मुकाबलेः पहली बार आयोजित हो रही इस राष्ट्रीय चैंपियनशिप में चंडीगढ़ के अंडर-12 बॉयज खिलाड़ियों ने शुरुआत से ही अपने इरादे जाहिर कर दिए थे. टीम ने पूरे टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं गंवाया और सभी मुकाबलों में एकतरफा जीत दर्ज कर गोल्ड मेडल हासिल किया।

खास बात यह रही कि चंडीगढ़ में आइस हॉकी के लिए समर्पित मैदान तक उपलब्ध नहीं है, इसके बावजूद खिलाड़ियों ने जिस स्तर का प्रदर्शन किया, उसने सभी को प्रभावित किया. खिलाड़ियों की इस सफलता के पीछे उनके कोचों की मेहनत और लगातार प्रशिक्षण की बड़ी भूमिका रही।

पांच मैचों में दागे 84 गोलः चंडीगढ़ की अंडर-12 बॉयज टीम ने पहले ही मैच से विपक्षी टीमों पर अपना दबदबा बनाना शुरू कर दिया था. टीम ने अपने पहले मुकाबले में राजस्थान को 16-0 से हराकर शानदार शुरुआत की. इसके बाद दूसरे मैच में तमिलनाडु को 12-1 से मात दी।

तीसरे मुकाबले में महाराष्ट्र के खिलाफ चंडीगढ़ के खिलाड़ियों ने आक्रामक खेल का प्रदर्शन करते हुए 23-2 की बड़ी जीत दर्ज की. सेमीफाइनल में पंजाब के खिलाफ भी टीम ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा और 21-1 से मुकाबला जीतकर फाइनल में जगह बनाई।

खिताबी मुकाबले में कर्नाटक की टीम सामने थी, लेकिन चंडीगढ़ के खिलाड़ियों ने यहां भी कोई मौका नहीं छोड़ा. टीम ने 12-2 से जीत दर्ज करते हुए पहली नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप का स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया. पूरे टूर्नामेंट के पांच मुकाबलों में टीम ने कुल 84 गोल किए, जो उनकी आक्रामक क्षमता और बेहतरीन टीम समन्वय को दर्शाता है।

अंडर-12 गर्ल्स टीम ने जीता कांस्य पदकः बॉयज टीम के साथ-साथ चंडीगढ़ की अंडर-12 गर्ल्स टीम ने भी शानदार प्रदर्शन किया. लड़कियों ने अपने पहले मुकाबले में महाराष्ट्र को 22-0 से हराकर दमदार शुरुआत की. इसके बाद दूसरे मैच में आंध्र प्रदेश को 10-4 से हराकर जीत का सिलसिला जारी रखा।

हालांकि कर्नाटक के खिलाफ मुकाबला बेहद रोमांचक रहा, जिसमें चंडीगढ़ की टीम को 3-2 से हार का सामना करना पड़ा. इसके बावजूद टीम ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार खेल दिखाया और कांस्य पदक जीतकर अपने अभियान का सफल समापन किया. लड़कियों के इस प्रदर्शन ने साबित कर दिया कि चंडीगढ़ में आइस हॉकी का भविष्य उज्ज्वल है. आने वाले सालों में यह टीम राष्ट्रीय स्तर पर और भी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकती हैं।

कोच और मैनेजर की हर तरफ हो रही सराहनाः चंडीगढ़ टीम की इस सफलता के पीछे कोच उज्जवल प्रताप सिंह और टीम मैनेजर आदित्य रामपाल की मेहनत को महत्वपूर्ण माना जा रहा है. उनकी अगुवाई में दोनों टीमों ने राष्ट्रीय प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया।

खिलाड़ियों के अभिभावकों के साथ-साथ अन्य राज्यों से आए प्रशिक्षकों और खिलाड़ियों ने भी टीम के कोचिंग स्टाफ की जमकर प्रशंसा की. विशेषज्ञों का मानना है कि सीमित संसाधनों के बावजूद खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर के लिए तैयार करना अपने आप में बड़ी उपलब्धि है. यही कारण है कि चंडीगढ़ टीम के प्रदर्शन की चर्चा पूरे टूर्नामेंट में होती रही।

उर्मिंदर पाल सिंह की मेहनत भी लाई रंगः चंडीगढ़ में आइस हॉकी के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं होने के बावजूद खिलाड़ियों का यह प्रदर्शन कई लोगों की सालों की मेहनत का परिणाम है. इनलाइन हॉकी के वरिष्ठ कोच उर्मिंदर पाल सिंह का भी इस टीम को तैयार करने में महत्वपूर्ण योगदान माना जा रहा है. उनकी देखरेख में खिलाड़ियों ने पहले इनलाइन हॉकी में अपनी पहचान बनाई और अब आइस हॉकी में भी राष्ट्रीय स्तर पर सफलता हासिल की है?

उधर, चैंपियनशिप का अगला चरण शुरू हो चुका है, जिसमें अंडर-15 वर्ग के मुकाबले खेले जा रहे हैं. चंडीगढ़ टीम से इस वर्ग में भी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीदें हैं. इसके बाद अंडर-18 और सीनियर वर्ग के मुकाबले आयोजित होंगे, जिन पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं. पहली नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप में अंडर-12 वर्ग की इस सफलता ने चंडीगढ़ को देश के उभरते आइस हॉकी केंद्रों में शामिल कर दिया है।

महिला टी-20 वर्ल्ड कप

नीदरलैंड के खिलाफ बल्लेबाजी में और बेहतरीन प्रदर्शन करना चाहेगा भारत

लीड्स (एजेंसी)। पाकिस्तान के खिलाफ पहले मैच में शानदार जीत से आत्मविश्वास से भरी भारतीय टीम बुधवार को यहां नीदरलैंड के खिलाफ होने वाले महिला टी20 विश्व कप के अपने दूसरे ग्रुप मैच में बल्लेबाजी में और बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करेगी। पाकिस्तान के खिलाफ पहले मैच में स्मृति मंधाना ने शीर्ष क्रम में और ऋचा घोष ने निचले क्रम में अच्छी बल्लेबाजी की थी जिससे भारत 64 रन से जीत हासिल करने में सफल रहा था।

सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा और कप्तान हरमनप्रीत कौर सहित बाकी बल्लेबाज अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। भारती फुलमाली मध्य क्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, लेकिन पहले मैच में वह खाता भी नहीं खोल पाई थी। भारत को टूर्नामेंट में आगे और भी कड़े मैच खेलने है और इसलिए बल्लेबाजी में निरंतरता बेहद महत्वपूर्ण है। भारत को नीदरलैंड से किसी तरह की खास चुनौती मिलने की संभावना नहीं है लेकिन उसे सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए लीग चरण में ऑस्ट्रेलिया या दक्षिण अफ्रीका में से किसी एक को हराना होगा।

पाकिस्तान के खिलाफ शुरू में फील्डिंग अच्छी नहीं थी, लेकिन पारी आगे बढ़ने के साथ भारतीय खिलाड़ियों ने कुछ अच्छे कैच लिए। गेंदबाजी विभाग में तेज गेंदबाज अरुंधति रेड्डी और क्रांति गौड़ कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई। लेकिन स्पिनरों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। दीप्ति शर्मा और श्री चरणी की स्पिन जोड़ी ने मिलकर आठ विकेट लिए। दीप्ति शर्मा ने चार ओवर में केवल 10 रन देकर 5 विकेट लिए और फॉर्म में वापसी की। भारत के लिए दीप्ति का फॉर्म में लौटना काफी महत्वपूर्ण था क्योंकि इससे पहले वह दो श्रृंखलाओं में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी।

नीदरलैंड की टीम अपने पहले मैच में बांग्लादेश से हार गई थी। भारत के सामने चुनौती पेश करने के लिए उसे खेल के सभी विभागों में सुधार करना होगा। कप्तान बैबेट डी लीड ने शुरुआती मैच में हार के बाद कहा, 'मुझे लगता है कि खेल के तीनों विभाग में हम वैसा प्रदर्शन नहीं कर पाए जैसी हमें उम्मीद थी। हम बल्लेबाजी में किसी भी समय लय में नहीं आ पाए। हमने कुछ ज्यादा ही विकेट गंवा दिए।'

टीमें :

- **नीदरलैंड** : बैबेट डी लीडे (कप्तान), कैरोलीन डी लैंग, फ्रेडरिक ओवरडिज्क, हन्ना लैंडहीर, हीथर सीजर्स, आइरिस जविलिंग, इसाबेल वान डेर वोनिंग, लारा लीमहुइस, मायरथे वान डेन राड, फेबे मोल्केनबोअर, रॉबिन रिजके, रोजाली लॉरेंस, सान्या खुराना, सिल्वर सिल्वर, स्टेरेलिस।
- **भारत** : हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, भारती फुलमाली, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष, श्री चरणी, यास्तिका भाटिया, नंदनी शर्मा, अरुंधति रेड्डी, रेणुका सिंह, क्रांति गौड़, श्रेयंका पाटिल, राधा यादव।
- **समय** : शाम 7 बजे।

केप वर्डे का वर्ल्ड कप में शानदार आगाज, स्पेनिश टीम से ड्रॉ खेलकर वर्ल्ड को चौंकाया

लॉस एंजिल्स (एजेंसी)। फीफा वर्ल्ड कप में पहली बार खेलने वाली टीम केप वर्डे ने उस समय सबको हैरान कर दिया, जब उन्होंने स्पेन जैसी खतरनाक और मजबूत टीम को एक भी गोल नहीं करने दिया. जिसकी वजह से वो 0-0 से मैच ड्रॉ करने में सफल रहे और अपने पहले ही वर्ल्ड कप मैच में एक पॉइंट्स लेकर इतिहास रच दिया।

केप वर्डे के इस शानदार प्रदर्शन में गोलकीपर वोजिन्हा ने सबसे अच्छा खेल दिखाया और 40 साल की उम्र में मैच के आखिर में स्पेन के जबरदस्त हमलों को नाकाम कर दिया. जिसकी वजह से स्पेन एक गोल भी नहीं कर सका। स्पेन मौजूदा यूरोपियन चैंपियन है. इस टीम में लामिन यामल जैसा शानदार युवा खिलाड़ी भी है. लेकिन वो पहले हॉफ में मैच खेलने नहीं उतरे, दूसरे हाफ में यामल मैदान पर जरूर उतरे, लेकिन उनके आने के बावजूद स्पेन जीत हासिल नहीं कर सका. केप वर्डे के गोलकीपर वोजिन्हा मैच के हीरो रहे, जिन्होंने पूरे खेल के दौरान सात गोल बचाकर स्पेन को गोल करने से रोके रखा।

केप वर्डे ने पूरे 90 मिनट तक अनुशासित खेल दिखाया और पूरे मैच में सिर्फ एक फाउल किया. दूसरी ओर, स्पेन ने बॉल पर कब्जा तो रखा लेकिन उसका सही इस्तेमाल नहीं किया और अफ्रीकी टीम पर दबाव बनाने के लिए शुरुआती मौके नहीं बना पाए।

कौन हैं वोजिन्हा?

40 वर्षीय वोजिन्हा का जन्म केप वर्डे के मिंडेलो में जोसिमार होजे एवोरा डायस में हुआ. वो अभी पुर्तगाली क्लब चावेस के लिए खेल रहे हैं. लगभग 15 साल के अंतरराष्ट्रीय अनुभव के साथ टूर्नामेंट में आए थे. फिर भी, 2012 से केप वर्डे का प्रतिनिधित्व करने के बावजूद, वह कभी भी फुटबॉल के सबसे बड़े मंच पर नहीं खेले थे. इस दौरान वोजिन्हा अपनी राष्ट्रीय टीम के लिए लगातार खेलते रहे और केप वर्डे के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ियों में से एक के तौर पर अपनी पहचान बनाई।

40 साल की उम्र में वोजिन्हा वर्ल्ड कप में डेब्यू करने वाले दूसरे सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए. उनसे ज्यादा उम्र के केवल मिस्र के पूर्व गोलकीपर एस्साम अल-हदारी थे, जो 2018 के टूर्नामेंट में 45 साल के थे।

श्रीलंका ए से हारने के बाद बीसीसीआई ने इंडिया ए स्क्वाड में किया बड़ा बदलाव

डंबुला (एजेंसी)। इंडिया ए टीम अभी डंबुला में श्रीलंका ए और अफगानिस्तान ए के खिलाफ 50-ओवर की ट्राई-सीरीज खेल रही है. सोमवार 15 जून को खेले गए सीरीज के एक मैच में इंडिया ए को श्रीलंका ए के खिलाफ सुपर ओवर में हार का सामना करना पड़ा. उसके बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने इंडिया ए स्क्वाड में बड़ा बदलाव किया है।

बोर्ड ने तेज गेंदबाज अशोक शर्मा को ट्राई-सीरीज के लिए इंडिया टीम में चोटिल युधवीर सिंह की जगह चुना गया है. हालांकि युधवीर को सीरीज में एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला सका था।

बीसीसीआई ने एक बयान में कहा, 'पुरुष चयन समिति ने श्रीलंका में चल रही ट्राई-सीरीज के लिए इंडिया टीम में युधवीर सिंह की जगह अशोक शर्मा को शामिल किया है. युद्धवीर ने 13 जून को गेंदबाजी करते समय अपने दाहिने कंधे में तकलीफ की शिकायत की थी और इससे पहले 11 जून को फील्डिंग सेशन के दौरान भी उन्हें ऐसा ही दर्द महसूस हुआ था।

बयान में आगे कहा गया, 'बीसीसीआई की मेडिकल टीम ने एक स्पेशलिस्ट से सलाह लेने के बाद सुझाव दिया कि युद्धवीर को दाहिने रोटेटर कफ की चोट से पूरी तरह ठीक होने के लिए बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) की देखरेख में एक ग्रेजुएटेड रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम से गुजरना चाहिए।'

अशोक का घरेलू क्रिकेट में प्रदर्शन – अशोक ने आईपीएल 2026 में अपनी तेज गेंदबाजी से काफी प्रभावित किया था. उन्होंने उस सीजन 154.2 किमी की रफ्तार से गेंद फेंकी थी. हालांकि उन्हें गुजरात टाइटन्स के लिए छह मैच ही खेलने का मौका मिला. जिसमें वो छह विकेट लिए थे. लेकिन अशोक 2025/26 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में दस मैचों में 22 विकेट लेकर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने थे।

ट्राई-सीरीज में इंडिया ए का प्रदर्शन – ट्राई सीरीज में तिलक वर्मा की कप्तान में इंडिया का प्रदर्शन मिला जुला रहा है. टीम ने अब तक तीन मैच खेले हैं, जिसमें उसे दो में हार और एक में जीत मिली है. जिसमें एक सुपर ओवर में हार भी शामिल है. सीरीज के पहले मैच में इंडिया ए ने श्रीलंका ए को 8 रनों से मात दी थी. जबकि दूसरे मैच में उन्हें अफगानिस्तान ए से डक्वर्थ लुईस नियम के आधार पर 4 रनों से हार का सामना करना पड़ा था. उसके बाद इंडिया ए अपने तीसरे मैच में श्रीलंका के खिलाफ सुपर ओवर में हार गई. अब इंडिया ए का अगला मैच अफगानिस्तान ए से 17 जून को है. फाइनल की रेस में बने रहने के लिए उन्हें ये मैच हर हाल में जीतना होगा।

- **इंडिया ए की अपडेटेड टीम** – तिलक वर्मा (कप्तान), रुतुराज गायकवाड़ (उप-कप्तान), प्रियांश आर्य, वैभव सूर्यवंशी, आयुष बडोनी, निशांत सिंधु, सूर्यांश शेडगे, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), विपराज निगम, यश ठाकुर, अंशुल कंबोज, अरशद खान, अनुकूल रॉय, अशोक शर्मा।